आज का विचार

जीवन में सबसे अच्छा रिश्ता वह होता है जो आपकी पीठ पीछे भी आपका सम्मान करे।

दैनिक सिटी दर्पण

आईना सच का

5

सिटी दर्पण-राष्ट्रीय दैनिक हिंदी समाचार पत्र की अधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए स्कैन करें।

पंचकूला । रविवार, 19 अप्रैल, 2026 वर्ष 1, अंक 246, मूल्य: 3 रुपए, पृष्ठ 8 RNI Regn No.: HRHIN/25/A2164 Established 2025 www.citydarpan.com

ईएसआई अस्पतालों में अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा: नायब सिंह सैनी

पानीपत के छह निजी अस्पतालों को तुरंत डी-पैनल बारे भेजा नोटिस व पानीपत ईएसआई अस्पताल के 3 कर्मचारियों को किया सस्पेंड

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ईएसआई हेल्थ केयर सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कड़े निर्देश जारी करते हुए कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही या भ्रष्टाचार को सहन नहीं किया जाएगा।

मुख्यमंत्री शनिवार को हरियाणा सिविल सचिवालय में ईएसआई हेल्थ केयर हरियाणा की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने पानीपत के ईएसआई अस्पताल से जुड़े मामलों पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि उन छह निजी अस्पतालों को तुरंत डी-पैनल किए जाने की कार्रवाई की जाए, इस पर अमल करते हुए विभाग ने अस्पतालों को नोटिस जारी कर दिया है।

इन अस्पतालों ने वर्ष 2020-21 से 2023-24 के दौरान अत्यधिक रेफरल किए थे और रेफरल प्रपत्रों पर चिकित्सकों के हस्ताक्षरों में गड़बड़ी पाई गई। उन्होंने इस पूरे प्रकरण में संलिप्त पानीपत ईएसआई अस्पताल के संबंधित 3 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ में ही 5 चिकित्सा अधीक्षकों के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले की निष्पक्ष और गहन जांच के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) को जिम्मेदारी सौंपी जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रदेश भर में ईएसआई के पैनल पर शामिल अन्य 133 निजी अस्पतालों के रिकॉर्ड की भी एसीबी द्वारा जांच करवाई जाए, ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता का समय रहते पता लगाया जा सके।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पानीपत ईएसआई अस्पताल की क्षमता 75 बेड से बढ़ाकर 100 बेड की जाए तथा वहां ऑपरेशन थिएटर का विस्तार किया जाए।

इसी प्रकार जगाधरी ईएसआई अस्पताल को 80 से 100 बेड और हिसार ईएसआई डिस्पेंसरी को 12 से बढ़ाकर 50 बेड करने के निर्देश दिए गए। सभी अस्पतालों में आधुनिक तकनीक से युक्त उपकरण भी लगाए जाएं।

मुख्यमंत्री ने बावल और बहादुरगढ़ में निमार्णाधीन 100-100 बेड के ईएसआई अस्पतालों का कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश देते हुए कहा कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से प्रदेश के श्रमिकों और आम नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

उन्होंने कहा कि ईएसआई हेल्थ केयर में डॉक्टरों और पैरा-मेडिकल स्टाफ की किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहने दी जाएगी। आवश्यकतानुसार स्टाफ की भर्ती प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के निर्देश भी दिए गए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है, और इस दिशा में कोई भी ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बैठक में हरियाणा के मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, श्रम विभाग के प्रधान सचिव श्री राजीव रंजन व अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

बांग्लादेशी घुसपैठियों के पैरोकारों ने पास नहीं होने दिया नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक : योगी

योगी ने माथाभांगा व धुपगुड़ी विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित कर भाजपा प्रत्याशियों के लिए मांगे वोट

एजेंसी (हि.स.)
कूच बिहार/जलपाईगुड़ी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में फिर गरजे। माथाभांगा व धुपगुड़ी विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित जनसभाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक पर लोकसभा में विपक्षी दलों के रुख की भर्त्सना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के पैरोकारों ने यह संशोधन विधेयक पास नहीं होने दिया। यह देश की आधी आबादी का अपमान है, माता-बहनें इसे किसी रूप में बर्दाश्त नहीं करेंगी। सीएम योगी ने पश्चिम बंगाल की मौजूदा अराजक स्थिति के लिए तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) को दोषी ठहराते हुए ऐलान किया कि ममता बनर्जी सिंहासन खाली करो, बीजेपी आ रही है। अब बंगालवासियों को घबराने की आवश्यकता नहीं है।

आधी आबादी को हक नहीं देना चाहते विपक्षी दलमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहन-बेटियों के लिए लोकसभा व विधानसभाओं में 33 फीसदी आरक्षण 2029 में लागू करने का संशोधन विधेयक संसद में प्रस्तुत किया, लेकिन कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, सपा व वामपंथियों ने इसे पास नहीं होने दिया। ये लोग आधी आबादी को उसका हक नहीं देना चाहते, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठियों की पैरोकारी करते हैं। बंगाल में मुसलमानों का नाम मतदाता सूची में चढ़े और वे गरीबों के हक पर डकैती डाल सकें, तृणमूल सरकार का यही काम है। आखिर यह कब तक चलेगा। नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक को गिराने से आधी आबादी का अपमान हुआ है। देश की बहन-बेटियां इसे कतई स्वीकार नहीं कर सकती हैं।

देश ने संसद में देखा मां के साथ तृणमूल का व्यवहारसीएम योगी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस मां, माटी व मानुष की बात करती थी। देश-दुनिया ने संसद में मां के साथ उनके व्यवहार को देखा। बंगाल में माटी की स्थिति यह है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों ने यहां के राजवंशियों व नागरिकों का हक छीना जा रहा है। मानुष टीएमसी की गुंडागर्दी से भयभीत है। उपज का दाम नहीं मिलने से किसान पलायन करने को विवश है। यूपी में आलू का दाम 15 से 20 रुपए है और यहां एक से डेढ़ रुपये। टीएमसी के 15 वर्ष के कार्यकाल में 7000 से अधिक बड़े कारखाने बंद हुए। यूपी में हमने तीन करोड़ नौजवानों को रोजगार दिया, लेकिन बंगाल में 30 लाख नौजवान बेरोजगार हुए। धान व मछली उत्पादन में लगातार गिरावट आ रही है। केंद्र सरकार विकास के लिए जो पैसा देती है, वह जरूरतमंदों तक नहीं पहुंचता। यह पैसा तृणमूल के गुंडे व बांग्लादेशी घुसपैठिए खा जाते हैं। सैंड माफिया, बागान माफिया सभी आपके हक पर डकैती डाल रहे हैं।

ममता को जय श्रीराम के घोष से चिढ़: सीएम

ममता दीदी को हिंदुओं व जय श्रीराम से चिढ़टीएमसी प्रमुख पर कड़ा प्रहार करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ममता दीदी को हिंदुओं व जय श्रीराम के उद्घोष से चिढ़ है। जिस तरह उन्होंने संसद में आधी आबादी को मिलने वाले हक का विरोध किया। ऐसे ही उन्होंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के दौरान भी किया था। इस एक्ट में मोदी जी ने बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों में प्रताड़ित होकर भारत आने वाले हिंदू, जैन, सिख आदि को भारत की नागरिकता देने व जमीन का अधिकार देने का प्रावधान किया है। अभी पिछले सप्ताह ही उत्तर प्रदेश के अंदर 1056 ऐसे परिवारों को भूमि अधिकार दिया गया है, नागरिकता दी गई है, जिन्हें पूर्वी बंगाल से निकाला गया था। कांग्रेस, कम्युनिस्ट दलों व टीएमसी ने सीएए का विरोध किया, लेकिन हमारी सरकार दुनिया के किसी भी कोने में हिंदुओं के साथ मजबूती के साथ खड़ी रहेगी। उनकी सुरक्षा करेगी। मुसलमानों के अलावा किसी के बारे में नहीं सोचती टीएमसीमुख्यमंत्री ने टीएमसी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि उसे मुस्लिम तुष्टिकरण से फुर्सत ही नहीं है। वह मुसलमानों के अलावा किसी के बारे में नहीं सोचती। बंगाल में आज ह्रजय श्रीरामह्व का नारा नहीं लगा सकते, क्योंकि सरकार आप पर अत्याचार करेगी, टीएमसी के गुंडे हमला बोल देते हैं। दुर्गापूजा से पहले उपद्रव हो जाता है। सरकार दुर्गापूजा व विसर्जन की अनुमति नहीं देती, गोहत्या कराती है और आमजन को प्रताड़ित करती है। 2017 से पहले यही स्थिति उत्तर प्रदेश में भी थी। वहां भी त्योहारों से पहले दंगे होते थे, महीनों कर्फ्यू रहता था। जय श्रीराम बोलने पर टीएमसी की पार्टनर सपा व कांग्रेस हमला कराती थीं और पुलिस से पिटवाती थीं। जुमे के दिन सड़कें जाम हो जाती थीं। सुबह 5 बजे से लोग मस्जिदों की आवाज से परेशान रहते थे। अब यूपी में अजान की आवाज केवल मस्जिद तकसीएम योगी ने कहा कि अब यूपी में डबल इंजन सरकार के कारण नो कर्फ्यू, नो दंगा, सब चंगा है।

महिला आरक्षण का विरोध किया एनडीए जारी रखेगा संघर्ष: मोदी

कोयंबटूर रैली में प्रधानमंत्री का डीएमके-कांग्रेस पर निशाना

एजेंसी (हि.स.)
कोयंबटूर

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को तमिलनाडु के कोयंबटूर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए डीएमके और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और कहा कि भाजपा-एनडीए जनता के अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखेगा। प्रधानमंत्री ने कहा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह हमारी लड़ाई का अंत नहीं, बल्कि शुरूआत है। भाजपा और एनडीए आपके अधिकारों के लिए लगातार काम करते रहेंगे।

उन्होंने संसद में पारित ह्यनारी शक्ति अधिनियमह्व का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण लागू करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है और सभी राजनीतिक दलों से इसका समर्थन करने की अपील की है। मोदी ने आरोप लगाया कि डीएमके, कांग्रेस और उनके सहयोगियों ने इस विधेयक का विरोध किया, जिससे महिलाओं को पहले ही अधिक प्रतिनिधित्व मिल सकता था। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2011 की जनगणना के आधार पर तमिलनाडु को अतिरिक्त सीटें मिल सकती थीं, लेकिन डीएमके ऐसा नहीं चाहती थी। उन्होंने आरोप लगाया कि काले कपड़े पहनकर डीएमके अपनी गलत मंशा नहीं छिपा सकती और जनता सब जानती है।

उन्होंने डीएमके पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि यह पार्टी परिवार द्वारा, परिवार के लिए और परिवार की नीति पर चलती है। मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और दिल्ली में पार्टी के प्रमुख नेता एक ही परिवार से हैं। मोदी ने राज्य में कानून-व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा पर भी सवाल उठाए और कहा कि डीएमके का महिला विरोधी रवैया अब जनता के सामने है और इसका जवाब मिलेगा। उन्होंने महिलाओं से अपील की कि वे डीएमके नेताओं से महिला आरक्षण का विरोध करने पर सवाल पूछें।

प्रधानमंत्री ने अपने पिछले दौरे का उल्लेख करते हुए कहा, पिछले साल नवंबर में मैं प्राकृतिक खेती पर एक सम्मेलन के लिए कोयंबटूर आया था। यह अनुभव मैं कभी नहीं भूल सकता। तमिलनाडु के मेहनती किसानों ने अपनी नवाचार क्षमता दिखाई। उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य में डबल इंजन सरकार बनने पर किसानों के जीवन में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि वह इस मुद्दे पर आज रात विस्तार से देश को संबोधित करेंगे।

प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि जनधन खातों, आवास, जल कनेक्शन और मुद्रा ऋण जैसी योजनाओं से करोड़ों लोगों को लाभ मिला है और 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं।

महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने की सरकार की साजिश नाकाम, विपक्ष की एकता से बचा लोकतंत्र : प्रियंका गांधी

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

महिला आरक्षण विधेयक संसद में पारित न होने के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष ने लोकतंत्र की रक्षा की है और परिसीमन से जुड़ी साजिश को विफल कर दिया है। कांग्रेस मुख्यालय में शनिवार को आयोजित प्रेस वार्ता में प्रियंका गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण कानून पर तीन साल तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया और हाल ही में जल्दबाजी में अधिसूचना जारी की। उन्होंने मांग की कि पहले के स्वरूप में महिला आरक्षण बिल को तुरंत लागू किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा, शुक्रवार को लोकतंत्र की बड़ी जीत हुई है। केंद्र सरकार ने लोकतंत्र को कमजोर करने और संघीय ढांचे में बदलाव की कोशिश की, जिसे विपक्ष ने मिलकर नाकाम कर दिया। यह संविधान और देश की जीत है। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार महिला आरक्षण के नाम पर बिल पास करवाकर परिसीमन में मनमानी करना चाहती थी और जातिगत जनगणना से बचना चाहती थी। उनके अनुसार, यदि बिल पारित होता तो सरकार इसे अपनी उपलब्धि बताती और यदि नहीं होता तो विपक्ष को महिला विरोधी करार देती। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि महिलाओं से जुड़े कई गंभीर मामलों, उन्नाव, हाथरस, महिला खिलाड़ियों और मणिपुर की घटनाओं में सरकार का रवैया उदासीन रहा है। अब वही सरकार खुद को महिलाओं का हितैषी दिखाने की कोशिश कर रही है। प्रियंका गांधी ने स्पष्ट किया कि यह केवल महिला आरक्षण का मुद्दा नहीं था, बल्कि परिसीमन और राजनीतिक संतुलन से भी जुड़ा हुआ था। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस तरह के प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर सकता था, जिसमें सरकार को बिना पारदर्शिता के फैसले लेने की छूट मिलती।

सरकार के लिए 'किसान हित सर्वोपरि' : शिवराज सिंह चौहान

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को कहा कि सरकार के लिए 'किसान हित सर्वोपरि' है और किसी भी प्रतिकूल मौसम परिस्थिति, विशेषकर अल नीनो के प्रभाव से निपटने के लिए केंद्र पूरी तरह तैयार है। शिवराज चौहान ने आज दिल्ली में कृषि क्षेत्र की वर्तमान स्थिति और आगामी खरीफ सीजन की तैयारियों की एक उच्चस्तरीय वर्चुअली समीक्षा के दौरान यह बात कही। मंत्री ने कहा, मौसम संबंधी पूर्वानुमान को गंभीरता से लेते हुए सरकार पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रही है और किसानों को किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं है। केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयास से संभावित चुनौतियों का प्रभाव काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। वर्ष 2000-2016 के बीच अल नीनो का असर ज्यादा होता था लेकिन आज की उन्नत तकनीक, सूक्ष्म सिंचाई और बेहतर प्रबंधन के कारण हम कृषि उत्पादन में स्थिरता बनाए रखने में सक्षम हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का उद्देश्य केवल संभावित जोखिम का आकलन करना नहीं बल्कि समय रहते ऐसे सभी कदम उठाना है जिससे किसानों का आत्मविश्वास बना रहे, खेती की निरंतरता प्रभावित न हो और खरीफ सत्र सुचारु रूप से आगे बढ़े। मंत्री ने भरोसा जताया कि बेहतर जल प्रबंधन, तकनीकी विकास, उन्नत कृषि पद्धतियों और समय पर की गई तैयारियों के बल पर संभावित चुनौतियों का प्रभाव कम किया जा सकेगा और किसानों के हितों की पूरी रक्षा की जाएगी।

कृषि मंत्री ने भरोसा जताया कि राज्यों के साथ निरंतर समन्वय और तकनीकी हस्तक्षेप के माध्यम से केंद्र सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और किसानों की आय की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

पंजाब के औद्योगिक विकास को गति देने और वैश्विक निवेश को आकर्षित करने के लिए भगवंत मान नीदरलैंड के दौरे पर

यज्ञांश शर्मा
चंडीगढ़

राज्य के औद्योगिक और आर्थिक विकास को गति देने के लिए पंजाब सरकार द्वारा किए जा रहे निरंतर प्रयासों के तहत मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान फूड प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक्स, अलॉयज एंड स्टील्स, फार्मास्यूटिकल्स और सूचना प्रौद्योगिकी समेत प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने तथा निवेश आकर्षित करने के लिए आज नीदरलैंड के दौरे पर रवाना हो गए हैं।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि हमारा विजन पूरी तरह स्पष्ट है, जो नीति स्थिरता, तेजी से फैसले लेने और निवेशकों के समय व भरोसे का सम्मान करने वाली शासन व्यवस्था प्रदान करके पंजाब को विश्व स्तर पर उद्योग के लिए प्राथमिकता वाला स्थान बनाने पर केंद्रित है।

- मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान फूड प्रोसेसिंग से लेकर आई.टी. सेक्टर तक पंजाब की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए नीदरलैंड के प्रमुख सेक्टरों तक पहुंच बनाएंगे
- टिकाऊ नीतियों और त्वरित फैसलों के साथ वैश्विक निवेश के लिए पंजाब पसंदीदा स्थान के रूप में उभरेगा: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

यह दौरा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि नीदरलैंड भारत के लिए सबसे बड़े विदेशी निवेशकों में से एक है और कई डच कंपनियां पहले से ही पंजाब में अपना कारोबार चला रही हैं। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने इससे पहले अक्टूबर-2023 में विविधा इंडस्ट्रियल पार्क, राजपुरा में डी ह्यूस फैक्टरी का शिलान्यास किया था। इसी प्रकार आलू की फसल के लिए इंडो-डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पहले ही राज्य में सफलतापूर्वक काम कर रहा है, जो पंजाब और नीदरलैंड के बीच बढ़ते सहयोग को दर्शाता है।

इस दौरे के दौरान मुख्यमंत्री राज्य के औद्योगिक विकास को और गति देने के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी पर जोर देंगे। वे पंजाब की रणनीतिक स्थिति, एनसीआर और प्रमुख बंदरगाहों से निर्बाध संपर्क, मजबूत औद्योगिक क्लस्टर, गुणवत्तापूर्ण निर्बाध बिजली आपूर्ति, कुशल कार्यबल और प्रगतिशील नीति ढांचे को उजागर करके पंजाब को उत्तरी भारत के पसंदीदा निवेश स्थल के रूप में भी प्रस्तुत करेंगे।

मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाला प्रतिनिधिमंडल पंजाब सरकार द्वारा लागू किए गए प्रमुख प्रशासनिक और नियामक सुधारों को पेश करेगा, जिसमें 173 सरकार से कारोबार सेवाएं, ऑटो-डीम्ड मंजूरियां, पैन-आधारित व्यापारिक पहचान, पंजाब राइट टू बिजनेस एक्ट में संशोधन और फास्टट्रैक पंजाब सिंगल-विंडो सिस्टम शामिल हैं।

इस प्रतिनिधिमंडल का उद्देश्य श्रृंखलाबद्ध रोड शो, वन-टू-वन बिजनेस मीटिंग्स और बड़ी ग्लोबल कॉर्पोरेट कंपनियों व संस्थाओं के साथ चर्चाओं के माध्यम से पंजाब को यूरोपीय देशों के लिए निवेश के आकर्षक गंतव्य के रूप में प्रस्तुत करना और पंजाब में नया निवेश लाना है।

मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों और विधायकों के वेतन का 50 से 20 फीसदी हिस्सा छह महीने के लिए स्थगित

आर्थिक तंगी से जूझ रही सुक्खू सरकार का कड़ा फैसला; जनप्रतिनिधियों के वेतन पर अस्थायी रोक

एजेंसी (हि.स.)
शिमला

हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष-उपाध्यक्ष और विधायकों के वेतन के एक हिस्से को अगले छह महीनों के लिए अस्थायी रूप से स्थगित करने का निर्णय लागू कर दिया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग (संसदीय कार्य) ने शनिवार को अधिसूचना जारी कर दी है। यह कदम राज्य की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिए उठाया गया बताया गया है।

जारी अधिसूचना के अनुसार मुख्यमंत्री के वेतन का 50 प्रतिशत, उपमुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद के सदस्यों, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन का 30 प्रतिशत तथा विधायकों के वेतन का 20 प्रतिशत हिस्सा अगले छह महीनों के लिए स्थगित रहेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह स्थगन अस्थायी होगा और राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार होने पर इसे बाद में जारी किया जाएगा। अधिसूचना में कहा गया है कि वेतन के देय और स्थगित हिस्से को ई-सैलरी प्रणाली और वेतन पर्चियों में अलग-अलग स्पष्ट रूप से दशार्या जाएगा, ताकि प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे। साथ ही आयकर सहित सभी वैधानिक कटौतियां पहले की तरह पूर्ण वेतन राशि पर ही लागू रहेंगी, जिससे भविष्य में लेखा संबंधी किसी प्रकार की समस्या न आए। हालांकि स्थगित की जाने वाली राशि की गणना कर निर्धारण और अन्य निश्चित कटौतियों के बाद बची राशि के आधार पर की जाएगी।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन जनप्रतिनिधियों के वेतन से हाउस बिल्डिंग एडवांस या मोटर कार एडवांस की किस्तें कट रही हैं, उनके लिए अलग व्यवस्था लागू होगी। ऐसे मामलों में संबंधित जनप्रतिनिधि निर्धारित प्रारूप में ड्रॉइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर को लिखित सहमति दे सकते हैं। सहमति देने के बाद उनकी किस्तों की कटौती के पश्चात शेष वेतन राशि के आधार पर ही स्थगन की गणना की जाएगी। अधिसूचना में यह भी साफ किया गया है कि वेतन का स्थगित हिस्सा किसी प्रकार की स्थायी कटौती नहीं माना जाएगा। यह राशि बाद में राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति को देखते हुए जारी की जाएगी। सरकार ने इसे सामूहिक प्रयास बताते हुए कहा है कि वित्तीय संसाधनों के कुशल प्रबंधन के लिए यह कदम अस्थायी तौर पर उठाया गया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 21 मार्च को वित्त वर्ष 2026-27 के बजट भाषण के दौरान मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष-उपाध्यक्ष और विधायकों के वेतन के हिस्से को स्थगित करने की घोषणा की थी। इसी बजट भाषण में उन्होंने उच्च अधिकारियों के वेतन में तीन प्रतिशत स्थगन का भी ऐलान किया था। हालांकि बाद में 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने उच्च अधिकारियों के वेतन में तीन प्रतिशत स्थगन के फैसले को वापस लेने की घोषणा कर दी थी।

मुख्यमंत्री ने बजट भाषण के दौरान यह भी कहा था कि केंद्र सरकार द्वारा राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) बंद किए जाने से हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ा है। उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार को सीमित संसाधनों के बीच वित्तीय संतुलन बनाए रखने के लिए कई कठिन लेकिन जरूरी फैसले लेने पड़ रहे हैं। ऐसे में जनप्रतिनिधियों के वेतन के एक हिस्से का अस्थायी स्थगन भी इसी दिशा में उठाया गया कदम है।

मेले हमारी संस्कृति और भाईचारे को करते हैं मजबूत : हर्षवर्धन चौहान

एजेंसी (हि.स.)
नाहन

सिरमौर जिला के शिलाई विधानसभा क्षेत्र की कोटी-बौंच पंचायत में आयोजित बैसाखी मेले के समापन समारोह में प्रदेश के उद्योग, संसदीय मामले एवं श्रम-रोजगार मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कोटी-बौंच बैसाखी मेला क्षेत्र के आराध्य देव शिरगुल महाराज के नाम पर आयोजित किया जाता है और धार्मिक, सामाजिक तथा व्यापारिक दृष्टि से इस मेले की क्षेत्र में विशेष पहचान है।

समारोह को संबोधित करते हुए उद्योग मंत्री ने कहा कि ऐसे मेलों और त्योहारों से समाज में सौहार्द और आपसी भाईचारे की भावना मजबूत होती है। उन्होंने कहा कि किसी भी मजबूत समाज की नींव उसकी समृद्ध संस्कृति और परंपराओं पर टिकी होती है। मेलों और त्योहारों के माध्यम से जहां लोगों को अपने रीति-रिवाजों और परंपराओं को सहेजने का अवसर मिलता है, वहीं नई पीढ़ी को भी अपनी संस्कृति को समझने और उससे जुड़ने का मौका मिलता है। उन्होंने बताया कि इस मेले के दौरान विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के अलग-अलग हिस्सों से आए खिलाड़ियों ने भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से युवाओं को आगे बढ़ने और अपनी क्षमता दिखाने का मंच मिलता है। उद्योग मंत्री ने कहा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है और आने वाले समय में प्रदेश एक मॉडल राज्य के रूप में उभरेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। इसी क्रम में गाय के दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर 61 रुपये प्रति लीटर और भैंस के दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य 71 रुपये प्रति लीटर किया गया है। इसके अलावा दूध को संग्रह केंद्रों तक पहुंचाने के लिए परिवहन सहायता भी तीन रुपये से बढ़ाकर छह रुपये प्रति लीटर कर दी गई है, जिससे पशुपालकों को सीधा लाभ मिलेगा। इससे पहले उद्योग मंत्री ने लोक निर्माण विभाग के विश्रामगृह रोहनाट में क्षेत्र के लोगों की समस्याएं भी सुनीं। इस दौरान लोगों ने सामूहिक और व्यक्तिगत समस्याएं उनके सामने रखीं। विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों ने भी अपने-अपने क्षेत्रों से संबंधित मांगें मंत्री के समक्ष प्रस्तुत कीं। मंत्री ने अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया और जो मामले स्थानीय स्तर पर लंबित थे, उन्हें संबंधित अधिकारियों को सौंपते हुए समयबद्ध तरीके से निपटाने के निर्देश दिए।

कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा ने भगवान परशुराम जयंती पर सभी श्रद्धालुओं को दी शुभकामनाएं

एजेंसी (हि.स.)
कठुआ

कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा ने कठुआ स्थित ब्राह्मण सभा में चल रहे 7 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम में भाग लिया और भगवान परशुराम जन्मोत्सव के अवसर पर सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दीं। इस मौके पर हीरानगर के विधायक विजय शर्मा भी उनके साथ मौजूद रहे।

कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर ब्राह्मण सभा के पदाधिकारियों ने मंत्री का फूल-मालाओं से भव्य स्वागत किया। इसके बाद अखनूर के श्रीमद्भागवत कथावाचक कुलदीप शास्त्री ने उन्हें पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। मंत्री ने कथा में पहुंचे श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए सनातन धर्म के महत्व पर प्रकाश डाला। मंत्री सतीश शर्मा ने कहा कि पड़ोसी देश पाकिस्तान अब सीधे तौर पर सफल नहीं हो पा रहा है इसलिए वह नशे के माध्यम से युवाओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने बताया कि जम्मू-कश्मीर में नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है ताकि युवाओं को इस खतरे से बचाया जा सके। मीडिया से बातचीत में मंत्री ने कहा कि सरकार खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठा रही है। उन्होंने जानकारी दी कि हीरानगर में बन रहे स्पोर्ट्स स्टेडियम का काम तेजी से चल रहा है और उम्मीद है कि एक साल के भीतर वहां आईपीएल मैच आयोजित किए जा सकेंगे जिससे स्थानीय लोगों को लाभ मिलेगा। इसी प्रकार सीयूईटी परीक्षा रद्द होने के मुद्दे पर मंत्री ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि बच्चों के पैसे बर्बाद नहीं होने दिए जाएंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार इस मामले में छात्रों के हितों का पूरा ध्यान रखेगी।

एशियाई विकास बैंक की टीम ने किया एचपी शिवा परियोजना का मध्यावधि निरीक्षण

मंडी। प्रदेश के बागवानों की आर्थिकी सुदृढ़ करने के उद्देश्य से चलाई जा रही हिमाचल प्रदेश सब-ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, इरिगेशन एंड वैल्यू एडिशन एचपी शिवा परियोजना की प्रगति का जायजा लेने के लिए एशियाई विकास बैंक एडीबी की एक उच्चस्तरीय टीम इन दिनों मंडी जिले के दौरे पर है। प्रोजेक्ट टीम लीडर डेनिस लोपेज के नेतृत्व में इस टीम में ब्रैंडो एंजेल्स, प्राची शर्मा और दिनेश गोदियाल शामिल हैं। बागवानी विभाग के उपनिदेशक डॉ. संजय गुप्ता ने बताया कि टीम द्वारा दो दिवसीय सघन दौरे के दौरान परियोजना के विभिन्न चरणों की समीक्षा की गई। गत दिवस टीम ने विकास खंड गोपालपुर के भांबला क्लस्टर का दौरा किया और वहां चल रही गतिविधियों का निरीक्षण किया। इसके अतिरिक्त आज विकास खंड सुंदरनगर के खग्राओं व पलौहटा-2 क्लस्टर और विकास खंड बल्ह के तमरोह क्लस्टर का दौरा कर जमीनी हकीकत जानी। निरीक्षण के दौरान टीम ने क्लस्टरों में तैयार किए गए बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता जांची। इसके साथ ही टीम ने सीएचपीएमए और डब्लूयूए के सदस्यों के साथ विशेष बैठकें कीं। टीम ने इन संस्थाओं की क्लस्टर निर्माण में भूमिका और उनके कामकाज के तरीकों का सूक्ष्मता से अवलोकन किया।

कांगड़ा वैली रेल सेवा जल्द बहाल हो चार साल से लोग परेशान : हर्ष महाजन

एजेंसी (हि.स.)
शिमला

हिमाचल प्रदेश से भाजपा के राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने कांगड़ा वैली रेल सेवा को जल्द बहाल करने और पठानकोट रेलवे स्टेशन को ममून कैंटोनमेंट में स्थानांतरित करने के प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने की मांग उठाई है। इस संबंध में उन्होंने केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव को पत्र लिखकर दोनों मुद्दों पर शीघ्र कार्रवाई करने का आग्रह किया है।

हर्ष महाजन ने अपने पत्र में कहा है कि पठानकोट-जोगिंदर नगर कांगड़ा वैली रेल सेवा केवल एक सामान्य परिवहन साधन नहीं है, बल्कि यह क्षेत्र के हजारों लोगों के लिए जीवनरेखा के रूप में काम करती रही है। उन्होंने बताया कि इस रेल सेवा का उपयोग लंबे समय से छात्र, मरीज, पर्यटक और रक्षा सेवाओं से जुड़े लोग करते रहे हैं। लेकिन पिछले लगभग चार वर्षों से इस ऐतिहासिक रेल मार्ग पर सेवाएं बंद रहने के कारण आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि रेल सेवा बंद रहने से न केवल लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन गतिविधियों पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ा है। महाजन के अनुसार कांगड़ा घाटी के लोग लंबे समय से इस रेल सेवा को फिर से शुरू करने की मांग कर रहे हैं और इसे प्राथमिकता के आधार पर बहाल किया जाना जरूरी है। राज्यसभा सांसद ने अपने पत्र में पठानकोट रेलवे स्टेशन को ममून कैंटोनमेंट में स्थानांतरित करने के प्रस्ताव पर भी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि वर्तमान पठानकोट रेलवे स्टेशन पिछले करीब एक सदी से क्षेत्र की सेवा कर रहा है और यह बस स्टैंड, अस्पताल, बाजार, होटल और सैन्य प्रतिष्ठानों से बेहतर तरीके से जुड़ा हुआ है। ऐसे में स्टेशन को दूसरी जगह स्थानांतरित करने से लोगों की सुविधा प्रभावित हो सकती है।

संक्षिप्त-समाचार

फार्मा कंपनी की लिफ्ट टूटने से युवक की मौत, भड़के ग्रामीणों का कंपनी के बाहर हंगामा

नाहन। सिरमौर के औद्योगिक क्षेत्र शंभूवाला में स्थित सनवेट हेल्थ केयर फार्मा कंपनी में शुक्रवार देर रात एक दर्दनाक हादसा पेश आया। कंपनी की लिफ्ट की तार अचानक टूटने से 29 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई। इस घटना के बाद शनिवार को मृतक के परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने कंपनी के मुख्य द्वार पर जोरदार हंगामा शुरू कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार रात कंपनी में कामकाज के दौरान लिफ्ट सामान लेकर ऊपर की मंजिल की ओर जा रही थी। इसी बीच लिफ्ट की लोहे की तार अचानक टूट गई और लिफ्ट सीधे नीचे जा गिरी। हादसे के वक्त लिफ्ट के साथ मौजूद युवक टीका राम (29) पुत्र रूप सिंह, निवासी रुखड़ी, जिला सिरमौर, गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत नाहन मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। शनिवार सुबह जैसे ही हादसे की खबर रुखड़ी और आसपास के गांवों में फैली, भारी संख्या में ग्रामीण कंपनी परिसर के बाहर एकत्र हो गए। ग्रामीणों का आरोप है कि इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद कंपनी का कोई भी उच्च अधिकारी या मालिक मौके पर नहीं पहुंचा। प्रबंधन के इस अमानवीय रवैये और सुरक्षा मानकों में बरती गई कथित लापरवाही से गुस्साए ग्रामीणों ने कंपनी के गेट पर धरना प्रदर्शन और नारेबाजी शुरू कर दी है। मौके पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, जिसे देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।

डोगरा विरास्त हमारी अस्मिता, उपेक्षा नहीं सरक्षण चाहिए: शिवसेना

जम्मू। विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर शिवसेना (यूबीटी) जम्मू-कश्मीर इकाई ने जम्मू की डोगरा सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्मारकों और पारंपरिक पहचान की लगातार हो रही उपेक्षा पर गहरा रोष व्यक्त करते हुए सरकार से जम्मू क्षेत्र के लिए एक समर्पित डोगरा हेरिटेज कंजर्वेशन बोर्ड के गठन की जोरदार मांग उठाई है। पार्टी मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष मनीश साहनी ने कहा कि यद्यपि जम्मू-कश्मीर में वर्ष 2010 से जम्मू-कश्मीर हेरिटेज कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन एक्ट लागू है, जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण के लिए वैधानिक प्राधिकरण का प्रावधान है लेकिन फिर भी जम्मू की डोगरा विरासत को अपेक्षित प्राथमिकता नहीं मिल रही है। साहनी ने उपराज्यपाल प्रशासन और पुरातत्व विभाग पर जम्मू की ऐतिहासिक पहचान के साथ गंभीर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए कहा कि जम्मू की शान और डोगरा गौरव के प्रतीक मुबारक मंडी पैलेस कॉम्प्लेक्स का जीर्णोद्धार कार्य वर्षों से कछुआ गति से चल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा पहले भी इसके संरक्षण हेतु करोड़ों रुपये की योजनाएं घोषित की गईं लेकिन जमीनी स्तर पर कार्य की गति और गुणवत्ता दोनों ही चिंता का विषय हैं। उन्होंने कहा कि केवल मुबारक मंडी ही नहीं बल्कि हीरानगर का जसमेरगढ़ किला, सांबा के प्राचीन किले, अखनूर किला तथा रियासी का भीमगढ़ किला भी संरक्षण के अभाव में अपना अस्तित्व खोने की कगार पर हैं। प्रशासन जम्मू को सिटी ऑफ टेम्पल्स कहकर केवल नारेबाजी करता है लेकिन यहां की ऐतिहासिक धरोहरों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने में पूरी तरह विफल रहा है।

कठुआ में एलपीजी आपूर्ति की समीक्षा, होम डिलीवरी करने के निर्देश

कठुआ। अतिरिक्त उपायुक्त कठुआ विश्वजीत सिंह ने जिला मुख्यालय में एलपीजी गैस एजेंसियों के साथ बैठक कर घरेलू गैस की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक में अधिकारियों और गैस एजेंसी संचालकों ने भाग लिया। बैठक में बताया गया कि जिले में एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता है और किसी प्रकार की कमी नहीं है। एडीसी ने उपभोक्ताओं तक समय पर सिलेंडर पहुंचाने के लिए सक्रिय होम डिलीवरी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और रोजाना स्टॉक व वितरण का रिकॉर्ड रखने को कहा। उन्होंने कालाबाजारी और जमाखोरी पर सख्त नजर रखने तथा ऐसी किसी भी गतिविधि की तुरंत सूचना प्रशासन को देने के निर्देश भी दिए। साथ ही शहरी क्षेत्रों में 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन के निर्धारित डिलीवरी चक्र का पालन करने को कहा। एडीसी ने ई-केवाईसी प्रक्रिया को भी तेज करने पर जोर देते हुए सभी उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से इसे नियमित रूप से कराने के निर्देश दिए। बैठक में सभी संबंधित पक्षों को बेहतर समन्वय के साथ सुचारू गैस आपूर्ति सुनिश्चित करने पर बल दिया गया।

जम्मू पश्चिम में 45 लाख की लागत से लेन-ड्रेन कार्यों का शुभारंभ

जम्मू। जम्मू पश्चिम के विधायक अरविंद गुप्ता ने आज वॉर्ड संख्या-39 में 45 लाख रुपये की लागत से लेन और ड्रेन निर्माण कार्यों का उद्घाटन किया। इस परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही टूटी सड़कों, खराब जल निकासी और जलभराव जैसी समस्याओं का समाधान करना है। इस अवसर पर विधायक अरविंद गुप्ता ने कहा कि यह परियोजना स्थानीय निवासियों को बेहतर सुविधाएं और स्वच्छ वातावरण प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार जमीनी स्तर पर आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है और हर क्षेत्र में विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि वॉर्ड स्तर पर इस प्रकार के विकास कार्य आधुनिक और प्रगतिशील शहर की नींव होते हैं जो लोगों के दैनिक जीवन पर सीधे प्रभाव डालते हैं। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखते हुए समय पर इन्हें पूरा किया जाए। कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश कोषाध्यक्ष प्रभात सिंह, मंडल अध्यक्ष कुशांत प्रजापति, महासचिव मोहित अभियंता, जूनियर इंजीनियर और संबंधित ठेकेदार भी उपस्थित रहे।

विपक्ष ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध कर किया महिला विरोधी मानसिकता को उजागर: जयराम ठाकुर

एजेंसी (हि.स.)
मंडी

पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शनिवार को अपने गृह क्षेत्र सराज के थुनाग में महिलाओं के साथ विशाल रोष प्रदर्शन में भाग लेते हुए कांग्रेस और उसके सहयोगी विपक्षी दलों की महिला विरोधी सोच पर जमकर प्रहार किया और कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन का विरोध करके इन दलों ने यह सिद्ध कर दिया है कि वे महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकार देने के पक्ष में नहीं हैं, जिसके लिए देश की मातृशक्ति उन्हें कभी क्षमा नहीं करेगी।

जयराम ठाकुर ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी केवल एक गांधी परिवार तक ही सीमित होकर रह गई है और वह राजनीति के क्षेत्र में अन्य प्रतिभावान महिलाओं को आगे आने का अवसर प्रदान नहीं करना चाहती, यही कारण है कि दशकों के लंबे इंतजार के बाद मातृशक्ति को मिलने वाला आरक्षण का अधिकार आज कांग्रेस की महिला सशक्तिकरण विरोधी राजनीति की भेंट चढ़ गया है।उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि महिलाओं के साथ किया गया यह व्यवहार केवल नाइंसाफी नहीं बल्कि एक अक्षम्य अपराध है जिसे देश की जनता कभी नहीं भूलेगी, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व और मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी नारी शक्ति को उनके वास्तविक अधिकार दिलाने की अपनी प्रतिबद्धता और लड़ाई को निरंतर जारी रखेगी। नेता प्रतिपक्ष ने इस बात पर भी गहरा रोष प्रकट किया कि महिला आरक्षण एवं परिसीमन विधेयक का विरोध करने के पश्चात कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने अपनी इस संकीर्ण मानसिकता पर जश्न भी मनाया, जो अत्यंत शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। सराज के थुनाग में हुए इस प्रदर्शन के माध्यम से क्षेत्र की महिलाओं ने कांग्रेस के इस कृत्य के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद की, जिसके उपरांत जयराम ठाकुर ने विधानसभा क्षेत्र के पदाधिकारियों और कार्यकताओं के साथ बैठक कर आगामी रणनीति पर आवश्यक दिशा-निर्देश भी साझा किए।

आज मनाई जाएगी अक्षय तृतीया, दान-पुण्य और शुभ कार्यों का विशेष संयोग

जम्मू। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाने वाली अक्षय तृतीया इस वर्ष 19 अप्रैल, रविवार को मनाई जाएगी। श्री कैलख ज्योतिष एवं वैदिक संस्थान ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं प्रधान ज्योतिषाचार्य महंत रोहित शास्त्री ने बताया कि तृतीया तिथि 19 अप्रैल को सुबह 10:50 बजे प्रारंभ होकर 20 अप्रैल को सुबह 7:28 बजे समाप्त होगी, लेकिन मध्याव्यापिनी तिथि 19 अप्रैल को होने के कारण पर्व इसी दिन मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस दिन कृत्तिका नक्षत्र, आयुष्मान योग तथा तैतिल और गर करण का विशेष संयोग बन रहा है। साथ ही चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ में स्थित रहेंगे जिससे इस पर्व का महत्व और अधिक बढ़ जाता है।महंत रोहित शास्त्री के अनुसार अक्षय का अर्थ है-जो कभी समाप्त न हो। इस दिन किए गए दान, यज्ञ, तर्पण और पूजन का फल अक्षय माना जाता है। इसे सर्वसिद्धि मुहूर्त भी कहा जाता है जिसमें बिना पंचांग देखे किसी भी शुभ कार्य की शुरूआत की जा सकती है। उन्होंने बताया कि इस दिन सोना-चांदी, बर्तन, भूमि, मकान और वाहन की खरीदारी शुभ मानी जाती है। साथ ही घी, शक्कर, अनाज, फल, कपड़े, जौ, गेहूं, सत्तू, दही-चावल, मिट्टी के घड़े, कूलर-पंखे आदि का दान विशेष पुण्यदायी होता है।

बस में सवार युवक से चिट्टा बरामद, गिरफ्तार

एजेंसी (हि.स.)
धर्मशाला

जिला कांगड़ा पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ निरन्तर जारी विशेष अभियान के अन्तर्गत शनिवार को एचआरटीसी बस में सवार एक युवक से 5.71 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी कक गिरफ्तार कर उकसे खिलाफ कांगड़ा पुलिस थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई की है।

जानकारी के मुताबिक कांगड़ा पुलिस की विशेष टीम गश्त पर थी।इसी दौरान कांगड़ा के समीप रानीताल में परवाणू से धर्मशाला आ रही एचआरटीसी बस को रोका गया तो उसमें एक सवार की गतिविधि से पुलिस को शक हुआ। पुलिस ने तुरंत उसके पास मौजूद पिट्ठू बैग की तलाशी ली तो उससे 5.71 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। आरोपी की पहचान विंपाशु चौधरी पुत्र विक्रमजीत गांव तालपुरा बार्ड नम्बर 3 डाकखाना, तहसील व जिला कांगड़ा उम्र 23 साल के रूप में हुई है। एसपी कांगड़ा अशोक रत्न ने बताया कि आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया तथा इसके विरुद्ध पुलिस थाना कांगड़ा में मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि जिला में नशा तस्करी करने वालों के खिलाफ पुलिस की यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

महिला आरक्षण विधेयक पर विपक्ष बना रोड़ा : प्रो. सिकंदर कुमार

एजेंसी (हि.स.)
शिमला

हिमाचल से राज्यसभा सांसद प्रो. सिकंदर कुमार ने लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 के पारित न हो पाने को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण देने का रास्ता साफ करने के लिए लाया गया यह महत्वपूर्ण विधेयक अपेक्षित दो-तिहाई बहुमत नहीं मिलने के कारण पारित नहीं हो सका, जिससे देश की करोड़ों महिलाओं की उम्मीदों को झटका लगा है।

प्रो. सिकंदर कुमार ने शनिवार को एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार देश की आधी आबादी को उनका अधिकार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। उनका कहना था कि यह विधेयक केवल एक कानून नहीं, बल्कि विकसित भारत के निर्माण की दिशा में एक अहम कदम था।उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष ने तकनीकी और प्रक्रियागत मुद्दों का हवाला देकर इस बड़े बदलाव को रोकने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि सरकार का स्पष्ट उद्देश्य संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी 33 प्रतिशत तक सुनिश्चित करना था, ताकि नीति निर्धारण में महिलाओं की मजबूत भूमिका तय हो सके। उनके अनुसार, दशकों से लंबित इस मुद्दे को आगे बढ़ाने का साहस मोदी सरकार ने दिखाया है और बिना महिलाओं की भागीदारी के देश का समग्र विकास संभव नहीं है।

मौसम | मैदानी व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में बढ़ सकता है गर्मी का असर

हिमाचल में कल तक मौसम रहेगा खराब, कोई अलर्ट नहीं

एजेंसी (हि.स.)
शिमला

हिमाचल प्रदेश में 20 अप्रैल तक मौसम खराब रहेगा और इस दौरान कई स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है, लेकिन मौसम विभाग ने किसी प्रकार का अलर्ट जारी नहीं किया है। विभाग के अनुसार 18 अप्रैल को कुछ स्थानों पर बारिश के आसार हैं। 19 और 20 अप्रैल को भी राज्य के अलग-अलग हिस्सों में हल्की वर्षा की संभावना बनी रहेगी। हालांकि 21, 22 और 23 अप्रैल को मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है, जिससे अधिकतम तापमान में उछाल आएगा और मैदानी व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में गर्मी का असर बढ़ सकता है। 24 अप्रैल को फिर से कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा की संभावना जताई गई है।

बीती रात राज्य के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी दर्ज की गई। लाहौल-स्पीति, किन्नौर और कुल्लू की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं पर हल्का हिमपात हुआ। वहीं मध्यवर्ती और निचले इलाकों में कई जगह हल्की वर्षा दर्ज की गई। सबसे अधिक वर्षा सलापड में 21.0 मिमी और सलूणी में 18.3 मिमी रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा कुकुमसेरी में 14.4 मिमी, सांगला में 7.8 मिमी, कल्पा में 5.2 मिमी, जोत में 4.0 मिमी, सराहन में 3.0 मिमी, भाबानगर में 2.4 मिमी, गोंधला में 2.2 मिमी, भरमौर में 2.0 मिमी, सेओबाग में 1.8 मिमी और जोगिंद्रनगर में 1.0 मिमी वर्षा दर्ज की गई। एक-दो स्थानों पर तेज हवाएं भी चलीं। सियोबाग में हवा की गति 35 किलोमीटर प्रति घंटा रिकॉर्ड की गई। हालांकि शनिवार सुबह राज्य के कई हिस्सों में मौसम साफ रहा और राजधानी शिमला तथा मनाली में धूप खिली रही । इससे लोगों को ठंड से कुछ राहत मिली, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि दिन के दौरान कुछ स्थानों पर फिर से हल्की वर्षा हो सकती है।तापमान की बात करें तो राज्य का औसतन न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.8 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है। कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान 0.8 डिग्री, कल्पा में 4.6 डिग्री, ताबो में मंडी और धर्मशाला में 14.7 डिग्री, पालमपुर में 15.0 डिग्री, शिमला में 15.6 डिग्री, ऊना और कांगड़ा में 16.0 डिग्री, नाहन में 18.1 डिग्री, बिलासपुर और देहरा गोपीपुर में 19.0 डिग्री तथा पांवटा साहिब में 21.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

अगले दो दिनों तक जम्मू और कश्मीर में मौसम अस्थिर रहने की संभावना

श्रीनगर। श्रीनगर मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले दो दिनों तक जम्मू और कश्मीर में अस्थिर मौसम का पूवार्नुमान लगाया है जिसमें कई स्थानों पर रुक-रुक कर बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। पूवार्नुमान के अनुसार 18- 19 अप्रैल को आंशिक रूप से लेकर सामान्यतः बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ेंगी, साथ ही 40-50 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की भी संभावना है। 20 से 23 अप्रैल तक मौसम सामान्यतः शुष्क रहने की उम्मीद है जिससे बारिश के बाद अस्थायी राहत मिलेगी। हालांकि 24 से 26 अप्रैल के बीच मौसम विभाग ने मुख्यतः शुष्क मौसम का पूवार्नुमान लगाया है जिसमें कुछ स्थानों पर दोपहर के समय हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है।

दैनिक सिटी दर्पण आईना सच का
न्वोन्मेषक: स्व. कृष्णा शर्मा
स्व. गीता शर्मा
संस्थापक: स्व. सतपॉल शर्मा
स्वामी, प्रकाशक एवं संपादक भूपिंद्र शर्मा द्वारा मुद्रक प्रवीन तोमर की इंप्रेशन्ज प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, प्लॉट नं. 22 और 49, ग्राउंड फ्लोर, इंडस्ट्रियल एरिया, फेस-2, पंचकूला-134115 (हरियाणा) पर मुद्रित एवं 180 ए, सेक्टर 19 सी, ओल्ड हाउसिंग बोर्ड कालोनी, पंचकूला, हरियाणा-134113 से प्रकाशित।
सभी विवादों का केंद्र न्यायालय पंचकूला होगा।
स्थानीय कार्यालय
180 ए, सेक्टर 19 सी, ओल्ड हाउसिंग बोर्ड कालोनी, पंचकूला, हरियाणा-134113
संपर्क: 7888450261
Email: citydarpanharyana@gmail.com

युद्ध के कारण तारकोल की कमी से सड़क निर्माण प्रभावित न हो, 6 माह के लिए इम्पोर्टिड तारकोल के इस्तेमाल को मंजूरी: नायब सैनी

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने सड़क निर्माण से संबंधित सभी विभागों के कार्यों की समीक्षा की

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

मीडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के कारण तारकोल की कमी व इसकी बढ़ी कीमतों के कारण सड़क निर्माण व मरम्मत के कार्य बाधित न हों, इसके लिए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों के अनुरोध पर अगले 6 माह के लिए इंपोर्टिड तारकोल के इस्तेमाल को मंजूरी दी है।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी आज हरियाणा सिविल सचिवालय में सड़क निर्माण व रखरखाव से संबंधित विभागों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने वित्त वर्ष 2025-26 में किए गए सड़क निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी ली और वित्त वर्ष 2026-27 में किए जाने वाले कार्यों के संबंध में विभागों के लक्ष्यों पर चर्चा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में पीडब्ल्यूडी (बीएंडआर), हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जिला परिषद/पंचायती राज, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, एचएसआईडीसी, शहरी स्थानीय निकाय तथा पीएमडीए, जीएमडीए, एसएमडीए सहित अन्य विभागों के सड़क निर्माण से जुड़े कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक के दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि 28 फरवरी को जहां तारकोल के दाम 46402 रुपये प्रति मीट्रिक टन थे वहीं 1 अप्रैल को यह 76152 रुपये प्रति मीट्रिक टन हो गए हैं। तारकोल की आपूर्ति करने वाली आईओसीएल ने इसकी आपूर्ति 50 प्रतिशत तक प्रभावित होने की सूचना दी है। ऐसी परिस्थिति में केंद्र सरकार ने इंपोर्टिड तारकोल के इस्तेमाल की मंजूरी दी है। इस पर मुख्यमंत्री ने हरियाणा में भी 6 माह के लिए इंपोर्टिड तारकोल का इस्तेमाल

करने की मंजूरी प्रदान की ताकि सड़क निर्माण व मरम्मत के कार्य प्रभावित न हों। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जनता की सुविधा के लिए सड़कों का अच्छी हालत में होना आवश्यक है। संबंधित विभाग सभी जिलों में सड़कों के गड्ढे भरवाने तथा अन्य मरम्मत कार्यों के लिए पैच वर्क मशीनों का इस्तेमाल करें ताकि सड़कों की रिपेयर जल्द हो सके। पीडब्ल्यूडी (बीएंडआर) द्वारा इन मशीनों का उपयोग किया जा रहा है, अन्य विभाग भी इन मशीनों के लिए पीडब्ल्यूडी से संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि टूटी सड़कों से आमजन को परेशानी होती है जिसे किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर विभाग अपने कार्यों की मासिक प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से उनके पास भिजवाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि म्हारी सड़क एप पर आमजन द्वारा क्षतिग्रस्त सड़कों की शिकायत की जाती है। इन सभी शिकायतों पर भी त्वरित कार्रवाई करते हुए इनका समाधान करवाया जाए। जिन सड़कों की मरम्मत की जिम्मेदारी इनका निर्माण करने वाली कंपनी की होती है, उन कंपनियों के माध्यम से आवश्यक मरम्मत कार्य त्वरित गति से करवाए जाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विभागों के लिए वित्त वर्ष 2025-26 में सड़क निर्माण हेतु जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि वित्त वर्ष 2026-27 के लक्ष्यों को भी समय पर पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में सभी विभागों के माध्यम से प्रदेश में सड़कों के निर्माण व मरम्मत के लिए 63170 किलोमीटर का लक्ष्य रखा गया है। यदि किसी तकनीकी पेंच के चलते जिला परिषद से संबंधित सड़क के प्रशासनिक अनुमोदन में कोई दिक्कत आती है तो संबंधित उपायुक्त को उसके अनुमोदन के लिए अधिकृत करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अक्सर यह देखने में आया है कि सभी विभागों की सड़क निर्माण की गुणवत्ता अलग-अलग होती हैं। उन्होंने सभी विभागों से पीडब्ल्यूडी (बीएंडआर) के मानकों के अनुरूप सड़क निर्माण करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण व मरम्मत के चालू कार्य मानसून के आने से पहले पूरे कर लिए जाएं।

मुख्यमंत्री ने सेक्टरों की क्षतिग्रस्त सड़कों को तुरंत ठीक करवाने के निर्देश देते हुए कहा कि शहरी क्षेत्रों में किस सड़क की जिम्मेदारी किस विभाग की है, इस संशय को दूर किया जाए। उन्होंने अधिकारियों की एक कमेटी गठित कर इस संबंध में प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सभी शहरी क्षेत्रों में कुछ स्मार्ट रोड बनाने की हिदायतें भी अधिकारियों को दीं ताकि शहरों की सुंदरता तथा आमजन की सुविधाओं को बढ़ाया जा सके।

बैठक में मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरुण गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग अग्रवाल, श्री एके सिंह, श्री विजेंद्र कुमार सहित अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे।

हरियाणा में अंडर ग्रैजूएट दाखिला प्रक्रिया शुरू, पोर्टल ओपन: महिपाल ढांडा

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

- प्रदेश के सभी डिग्री कॉलेजों में इअ, इ.उड्ढे, इ.रू, इउअ सहित विभिन्न कोर्सों में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित

हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री महिपाल ढांडा ने बताया कि प्रदेश के सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी डिग्री कॉलेजों में स्नातक (वऋ) प्रथम वर्ष के विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल 17 अप्रैल 2026 से खोल दिया गया है।

उन्होंने बताया कि इस पोर्टल के माध्यम से छात्र-छात्राएं इअ, इ.उड्ढे, इ.रू, इउअ सहित अन्य स्नातक पाठ्यक्रमों में घर बैठे ही सरलता से आवेदन कर सकते हैं। यह पहल दाखिला प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी, सुगम और डिजिटल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

श्री महिपाल ढांडा ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य है कि हर योग्य विद्यार्थी को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध हों और उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसी दृष्टिकोण से एडमिशन प्रक्रिया को ऑनलाइन माध्यम से संचालित किया जा रहा है, जिससे समय की बचत के साथ-साथ प्रक्रिया में पारदर्शिता भी सुनिश्चित हो सके।

विद्यार्थियों एवं अभिभावकों से अपील की कि वे निर्धारित समयावधि के भीतर पोर्टल पर आवेदन करना सुनिश्चित करें।

हरियाणा प्रीवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, 1989 के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

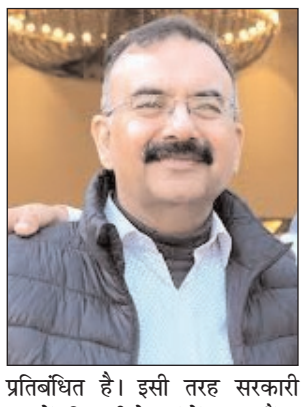

- अवैध प्रचार सामग्री हटेगी, खर्च उम्मीदवार/दल से वसूला जाएगा :देवेंद्र सिंह कल्याण

हरियाणा राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री देवेंद्र सिंह कल्याण ने नगर निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के मद्देनजर लागू आदर्श आचार संहिता के तहत हरियाणा प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, 1989 के सख्त पालन के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आयोग के संज्ञान में आया है कि कई उम्मीदवार और राजनीतिक दल सार्वजनिक व निजी संपत्तियों पर अवैध रूप से पोस्टर-बैनर लगा रहे हैं और दीवारों पर लिखाई कर रहे हैं, जो कानून का उल्लंघन है और प्रदेश की सुंदरता को प्रभावित करता है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि इस एक्ट की धारा- 3 और 3-ए के तहत किसी भी सार्वजनिक स्थान पर आने वाली संपत्ति को स्याही, चॉक, पेंट या अन्य माध्यम से लिखकर या चिन्हित करना प्रतिबंधित है। इसी तरह सरकारी भवनों, बिजली के खंभों, बस स्टैंड, सार्वजनिक स्थानों या मूर्तियों पर पोस्टर, बैनर या फ्लेक्स लगाना तथा सार्वजनिक परिवहन, खासकर राज्य परिवहन की बसों पर प्रचार सामग्री चिपकाना पूरी तरह से मना है। यह संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है।

आयुक्त ने कहा कि ऐसे मामलों में अवैध प्रचार सामग्री हटाने और संपत्ति को पहले जैसी स्थिति में लाने का खर्च संबंधित उम्मीदवार या राजनीतिक दल से वसूला जाएगा। यदि किसी उम्मीदवार के पक्ष में इस तरह की गतिविधि होती है, तो उसे इसके लिए जिम्मेदार माना जाएगा, जब तक वह यह साबित न कर दे कि यह उसकी जानकारी या सहमति के बिना हुआ है।

उन्होंने निर्देश दिए कि उम्मीदवार केवल उन्हीं स्थानों पर प्रचार सामग्री लगाएं, जो शहरी क्षेत्रों में कार्यकारी अधिकारी/सचिव और ग्रामीण क्षेत्रों में बीडीपीओ/पंचायत अधिकारी द्वारा निर्धारित किए गए हैं। जिन संपत्ति मालिकों ने अपनी दीवारों पर विज्ञापन की अनुमति नहीं दी है, वे इसकी शिकायत संबंधित पर्यवेक्षक या उपायुक्त को कर सकते हैं। आयोग ने स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि ऐसी शिकायत मिलने पर 24 घंटे के भीतर अवैध सामग्री हटाई जाए।

हरियाणा राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि लोकतंत्र में भागीदारी जरूरी है, लेकिन यह सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सभी उम्मीदवारों से अपील की कि वे आदर्श आचरण अपनाएं और स्वच्छ व निष्पक्ष चुनाव में सहयोग करें। साथ ही, उड़न दस्तों को ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई के लिए अधिकृत किया गया है। किसी भी शिकायत के लिए उपायुक्त, नगर आयुक्त, रिटर्निंग अधिकारी या अन्य अधिकृत अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।

संक्षिप्त-समाचार

महिला आरक्षण के नाम पर लोकतंत्र से खिलवाड़ करने की साजिश बेनकाब: सैलजा

चंडीगढ़ /नई दिल्ली। सिरसा की सांसद, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी महासचिव एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि महिलाओं के अधिकारों के नाम पर देश के लोकतंत्र, संविधान और संघीय ढांचे को कमजोर करने की साजिश रची जा रही थी, जिसे एकजुट विपक्ष ने समय रहते विफल कर दिया। कुमारी सैलजा ने कहा कि भाजपा का असली चेहरा अब देश के सामने पूरी तरह उजागर हो चुका है। सरकार महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन का ऐसा जाल बुन रही थी, जिससे राजनीतिक संतुलन बिगाड़कर लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपने पक्ष में मोड़ा जा सके। यह केवल महिलाओं के साथ छल नहीं, बल्कि संविधान की मूल भावना पर सीधा प्रहार है। उन्होंने कहा कि आज जो गिरा है, वह महिला आरक्षण विधेयक नहीं, बल्कि भाजपा की साजिशों का ढांचा है। यह देश की जागरूक जनता और मजबूत विपक्ष की जीत है, जिसने लोकतंत्र को बचाने का काम किया। कुमारी सैलजा ने स्पष्ट मांग रखते हुए कहा कि 2023 के नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अनुसार 2029 के लोकसभा चुनावों से ही महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। अब किसी भी प्रकार की देरी या बहानेबाजी देश की महिलाओं के साथ अन्याय होगा, जिसे कांग्रेस पार्टी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने बार-बार महिलाओं के सम्मान के नाम पर केवल राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास किया है, लेकिन जमीनी स्तर पर महिलाओं को सशक्त करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। अब देश की महिलाएं और युवा वर्ग भाजपा की नीयत को भलीभांति समझ चुके हैं। अंत में कुमारी सैलजा ने कहा कि यह केवल एक राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि देश के भविष्य और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की लड़ाई है। भाजपा चाहे जितनी सच्चाई छुपाने की कोशिश कर ले, लेकिन अब देश की जनता जाग चुकी है और आज से ही भाजपा के पतन की शुरूआत हो चुकी है।

नई दिल्ली में शिक्षा सुधारों पर मंथन: शिक्षा मंत्री ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से लिया मार्गदर्शन

चंडीगढ़। हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री महीपाल ढांडा ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री श्री मनोहर लाल से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं, नवाचारों और सुधारात्मक पहलों पर विस्तार से चर्चा की तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मार्गदर्शन प्राप्त किया। बैठक के दौरान शिक्षा मंत्री ने राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता सुधार, डिजिटल लर्निंग, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास तथा विद्यार्थियों के समग्र विकास से जुड़ी योजनाओं की प्रगति से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार शिक्षा प्रणाली को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने राज्य सरकार द्वारा शिक्षा क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि शिक्षा किसी भी समाज की प्रगति की आधारशिला होती है और इसमें नवाचारों को बढ़ावा देना समय की आवश्यकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि तकनीक आधारित शिक्षा को और अधिक मजबूत किया जाए, ताकि विद्यार्थियों को वैश्विक स्तर की प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार किया जा सके। इस अवसर पर दोनों नेताओं ने केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से शिक्षा क्षेत्र में और अधिक प्रभावी परिणाम सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।

पंचकूला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में होगी शारीरिक माप परीक्षा, सुबह 6:30 बजे से शुरू होगा टेस्ट

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के सदस्य श्री भूपेंद्र चौहान ने आज पंचकूला में प्रेस वार्ता कर शारीरिक माप परीक्षा (ढटळ) की व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि परीक्षा पंचकूला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आयोजित की जाएगी।

श्री चौहान ने कहा कि शारीरिक माप परीक्षा (ढटळ) सुबह 6:30 बजे से शुरू होगी। प्रारंभ में प्रतिदिन 700 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, जिसे बाद में बढ़ाकर 1500 अभ्यर्थी प्रतिदिन तक किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि आयोग प्रतिदिन 1500 से 2000 अभ्यर्थियों को बुलाएगा और आवश्यकता पड़ने पर यह संख्या 3000 तक बढ़ाई जा सकती है। पूरी प्रक्रिया में लगभग 60 से 80 दिन का समय लगेगा।

आयोग की ओर से स्टेडियम के गेट पर अभ्यर्थियों एवं उनके परिजनों के लिए विश्राम क्षेत्र बनाया गया है, जहां वे आराम से बैठ सकें। अभ्यर्थियों के लिए बैगेज जमा करने की व्यवस्था भी की गई है। स्टेडियम में प्रवेश के बाद सख्त जांच के उपरांत दस्तावेजों की पुष्टि की जाएगी। इसके बाद बायोमेट्रिक प्रक्रिया पूरी कर अभ्यर्थी को क्रमांक देकर मुख्य हॉल में भेजा जाएगा। मुख्य हॉल के प्रवेश द्वार पर चेस्ट नंबर दिया जाएगा तथा वहां पुनः बायोमेट्रिक प्रक्रिया की जाएगी।

सभी औपचारिकताएं पूर्ण होने के बाद मुख्य हॉल में 21 आधुनिक डिजिटल मशीनें स्थापित की गई हैं, जिनके माध्यम से अभ्यर्थियों की लंबाई एवं छाती का मापन किया जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी मापन से संतुष्ट नहीं होता है, तो वह तुरंत अपील कर सकता है और उसका पुनः परीक्षण किया जाएगा। इन व्यवस्थाओं के अतिरिक्त आयोग ने सिख अभ्यर्थियों के लिए विशेष प्रबंध किए हैं, जिनके अंतर्गत निर्धारित मशीन पर सिख समाज के प्रतिनिधियों द्वारा धार्मिक मर्यादा के अनुरूप उनका मापन किया जाएगा। इसके अलावा जीरकपुर से प्रातः 5 बजे से विशेष बसों की व्यवस्था की गई है, जो अभ्यर्थियों को स्टेडियम तक पहुंचाएंगी।

श्री भूपेंद्र चौहान ने अभ्यर्थियों से अपील की कि वे शारीरिक माप परीक्षा (ढटळ) से पूर्व किसी भी प्रकार के एनर्जी बूस्टर या दवाइयों का सेवन न करें, क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। गर्भवती महिलाओं एवं अन्य महिला अभ्यर्थियों के लिए भी आयोग की ओर से विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि आयोग पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी, सुव्यवस्थित एवं अभ्यर्थी-अनुकूल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

जनगणना-2027: उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने ऑनलाइन स्व-गणना कर नागरिकों को दिया संदेश

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

जनगणना-2027 के तहत चल रही स्व-गणना प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने गुरुग्राम में स्वयं ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी जानकारी दर्ज कर स्व-गणना की। उन्होंने आम नागरिकों को इस सुविधा का उपयोग करने का संदेश भी दिया।

उन्होंने कहा कि स्व-गणना की व्यवस्था नागरिकों को घर बैठे अपनी जानकारी भरने का सरल और सुविधाजनक विकल्प देती है। इससे समय की बचत होती है और जानकारी सीधे सिस्टम में दर्ज होने से पारदर्शिता भी बनी रहती है।

उन्होंने कहा कि हर परिवार को 30 अप्रैल तक इस प्रक्रिया को पूरा कर लेना चाहिए, ताकि जनगणना का कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके।

कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि जनगणना केवल आंकड़ों का संग्रह नहीं, बल्कि देश और प्रदेश के विकास की योजनाओं की मजबूत नींव है। सही और पूरी जानकारी से ही सरकार को योजनाएं बनाने में मदद मिलती है।

उन्होंने नागरिकों से आह्वान किया कि वे जिम्मेदारी समझते हुए इस प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि आधिकारिक पोर्टल पर मोबाइल नंबर के माध्यम से ओटीपी वेरिफिकेशन कर लॉगिन किया जा सकता है और चरणबद्ध तरीके से सभी जरूरी जानकारी आसानी से भरी जा सकती है। जानकारी भरने के बाद मिलने वाली सेल्फ-एन्यूमरेशन आईडी को सुरक्षित रखना जरूरी है, जिसे बाद में गणना कर्मियों को दिखाना होगा।

सरकार किसानों के लिए एग्रोफॉरेस्ट्री पेड़ों की बिक्री हेतु ई-नीलामी पोर्टल लॉन्च करेगी: सुधीर राजपाल

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

- हरियाणा फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एचएफडीसी) के निदेशक मंडल की 146वीं बैठक में लिया गया निर्णय

अब किसान अपने खेतों में खड़े एग्रोफॉरेस्ट्री प्रजातियों के पेड़ों, जैसे यूकेलिप्टस, पॉपलर आदि को एचएफडीसी के ई-नीलामी पोर्टल के माध्यम से बेच सकेंगे, जिससे उन्हें बिचैलियों से अधिक कीमत मिल सकेगी। राज्य के किसानों के हित में यह निर्णय हरियाणा फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एचएफडीसी) के निदेशक मंडल की 146वीं बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता वन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं एचएफडीसी अध्यक्ष श्री सुधीर राजपाल ने की। बैठक के दौरान प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं प्रबंध निदेशक के.सी. मीणा ने यह प्रस्ताव रखा। योजना के अनुसार, जो किसान एचएफडीसी के ई-नीलामी पोर्टल का उपयोग करना चाहते हैं, वे संबंधित जनरल मैनेजर को आवेदन देंगे। इसके बाद कॉर्पोरेशन के फील्ड कार्यालय खड़े पेड़ों का आकलन और मार्किंग करेंगे तथा उनके वॉल्यूम के आधार पर एक आरक्षित मूल्य तय किया जाएगा। किसान चाहें तो अपना आरक्षित मूल्य स्वयं भी निर्धारित कर सकते हैं। इसके बाद पेड़ों के वॉल्यूम को ई-नीलामी पोर्टल पर डाला जाएगा। नीलामी में प्राप्त बोली की जानकारी किसान को दी जाएगी, और यदि किसान उस मूल्य से सहमत होता है, तो एचएफडीसी कुल नीलामी मूल्य का मात्र 5 प्रतिशत सेवा शुल्क लेगा और शेष राशि सीधे किसान के खाते में ऑनलाइन जमा कर दी जाएगी।

नारनौल के बड़कोदा-बडगांव में 14 एकड़ में बनेगा अत्याधुनिक जिला स्तरीय स्टेडियम, खेल राज्य मंत्री ने किया साइट निरीक्षण

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

हरियाणा के खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री श्री गौरव गौतम ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार खेलों और खिलाड़ियों के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार खेलों को लगातार बढ़ावा दे रही हैं।

खेल राज्य मंत्री आज गांव नारनौल के बड़कोदा-बडगांव में प्रस्तावित खेल स्टेडियम की साइट का निरीक्षण करने के बाद लोगों से बातचीत कर रहे थे।

श्री गौतम ने कहा कि खेल सुविधाओं को और अधिक बेहतरीन बनाने के लिए गांव बड़कोदा-बडगांव में लगभग 14 एकड़ भूमि पर एक भव्य जिला स्तरीय खेल स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खिलाड़ियों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर की ढांचागत सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। आज प्रदेश के खिलाड़ी पूरी दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं।

निरीक्षण के दौरान खेल राज्य मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 14 एकड़ में बनने वाले इस खेल स्टेडियम का निर्माण कार्य उच्च गुणवत्ता के साथ समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए।

उन्होंने कहा कि इस स्टेडियम के बनने से न केवल नारनौल, बल्कि पूरे जिले के उभरते खिलाड़ियों को अभ्यास के लिए आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी, जिससे वे भविष्य में देश के लिए पदक जीत सकें।

इस मौके पर पूर्व मंत्री व नारनौल के विधायक ओम प्रकाश यादव, जिला खेल अधिकारी नरेंद्र कुंडू व अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।

गौरव गौतम ने केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया से की मुलाकात

चंडीगढ़। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री श्री गौरव गौतम ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया संग मुलाकात की और सुनियोजित प्रयासों और मजबूत नीतियों के माध्यम से हरियाणा को वैश्विक खेल मानचित्र पर एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने व राज्य के खेल ढांचे को और सशक्त बनाने बारे में बैठक कर चर्चा की। बैठक में राज्य मंत्री श्री गौरव गौतम ने युवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कई अहम बिंदुओं के साथ साथ ह्यमिशन ओलंपिक 2036ह्ल को केंद्र में रखते हुए दीर्घकालिक योजनाओं पर विशेष रूप से चर्चा की। इसके अलावा ,खेलो इंडिया, फिट इंडिया और यूथ गेम्स जैसी प्रमुख योजनाओं को हरियाणा प्रदेश के गांव-गांव और प्रत्येक युवा तक पहुंचाने के लिए प्रभावी क्रियान्वयन रणनीति पर भी विचार किया गया। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार का उद्देश्य है कि राज्य के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं को समान अवसर मिलें और वे राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मंच पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकें। बैठक में खिलाडियों को आर्थिक सहायता, डाइट प्लान और अंतरराष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग देने जैसे मुद्दों पर भी जानकारी दी गई गई। बैठक में यह भी तय किया गया कि स्कूल और कॉलेज स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं को और अधिक व्यवस्थित किया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा युवा खेलों से जुड़ सकें और राज्य को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिला सकें। मिशन 2036 ओलंपिक को लेकर हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ियों के बारे में भी बातचीत हुई। खेल मंत्री श्री गौरव गौतम ने जिला पलवल में प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेल स्टेडियम के बारे में भी जानकारी दी।

संपादकीय

खुशखबरी ! 1.18 करोड़ सरकारी कर्मचारियों-पेंशनभोगियों की बल्ले-बल्ले – डी ए बढ़कर हुआ 60%

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महँगाई भत्ते तथा महँगाई राहत में 2 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी है, जिससे यह दर मूल वेतन के 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गई है। यह निर्णय 18 अप्रैल 2026 को लिया गया और 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए इस फैसले को सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है। परंतु इस निर्णय के व्यापक आर्थिक एवं सामाजिक परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण करना आवश्यक है कि यह वृद्धि वास्तव में कितनी पर्याप्त है। महँगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मूल्य वृद्धि से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए दिया जाने वाला एक महत्त्वपूर्ण वित्तीय प्रावधान है। यह भत्ता मूल वेतन के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में दिया जाता है और मुद्रास्फीति सूचकांकों के आधार पर समय-समय पर इसकी समीक्षा की जाती है। इसे प्रतिवर्ष दो बार – सामान्यतः जनवरी और जुलाई में – संशोधित किया जाता है, जो कि श्रम मंत्रालय के अंतर्गत श्रम ब्यूरो द्वारा जारी औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित होता है। इस प्रकार यह भत्ता सरकारी कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बनाए रखने का एक व्यवस्थित तंत्र है।इस निर्णय से लगभग 50.46 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 68.27 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा। इस वृद्धि से सरकारी खजाने पर सालाना 6,791.24 करोड़ रुपये का संयुक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। आँकड़ों की दृष्टि से देखें तो यह निर्णय करोड़ों परिवारों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। केवल कर्मचारी ही नहीं, बल्कि उनके परिवार भी इस वृद्धि के लाभार्थी बनते हैं। यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 50,000 रुपये है, तो 2 प्रतिशत की वृद्धि से उसके महँगाई भत्ते में प्रतिमाह 1,000 रुपये की बढ़ोतरी होगी। वार्षिक रूप से यह राशि 12,000 रुपये बनती है, जो बकाया राशि को छोड़कर एक मामूली किंतु सार्थक आर्थिक राहत प्रदान करती है। देखने में यह राशि बहुत बड़ी नहीं लगती, लेकिन पेंशनभोगियों और निम्न वेतनमान के कर्मचारियों के लिए यह सहायता निश्चित रूप से उनके मासिक बजट को कुछ हद तक संतुलित करने में मदद करती है। यह वृद्धि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित स्थापित सूत्र के अनुरूप की गई है। इससे पहले, अक्टूबर 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2025 से प्रभावी 3 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी थी, जिससे डी ए 55 प्रतिशत से बढ़कर 58 प्रतिशत हो गया था। यानी पिछले कुछ समय में केंद्र सरकार ने महँगाई भत्ते में क्रमिक वृद्धि की है, जो एक सुसंगत नीतिगत दिशा को दर्शाता है।किंतु प्रश्न यह उठता है कि क्या यह वृद्धि देश में बढ़ती हुई महँगाई की तुलना में पर्याप्त है ? आम नागरिक रोजमर्रा के जीवन में खाद्य पदार्थों, ईंधन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती कीमतों का सामना कर रहा है। थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में उतार-चढ़ाव का सीधा असर आम परिवारों के बजट पर पड़ता है। ऐसे में 2 प्रतिशत की वृद्धि कुछ विशेषज्ञों को अपर्याप्त प्रतीत होती है। विशेषकर तब, जब भारत में खाद्य मुद्रास्फीति की दर कई बार सामान्य से ऊँची रही है।एक अन्य महत्त्वपूर्ण पहलू यह है कि डी ए आयकर अधिनियम के अंतर्गत पूरी तरह कर योग्य है। अतः वृद्धि की जो राशि कर्मचारियों को मिलती है, उसमें से आयकर कटने के बाद वास्तविक लाभ और भी कम हो जाता है। यह एक ऐसा पहलू है जिस पर नीति-निमार्ताओं को गंभीरता से विचार करना चाहिए।साथ ही, इस फैसले को 8वें वेतन आयोग की मांगों के संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए। कर्मचारी संगठनों ने वेतन ढाँचे में व्यापक सुधार की माँग की है, जिसमें 'परिवार' की परिभाषा का विस्तार कर आश्रित माता-पिता को शामिल करना, वेतन असमानता को कम करना, और मुद्रास्फीति से जुड़े भत्तों को मजबूत बनाना शामिल है। इन माँगों से स्पष्ट होता है कि डी ए जैसी वृद्धिशील समायोजन नीतियों से आगे बढ़कर वेतन संरचना के समग्र पुनर्निर्माण की जरूरत है।यह भी उल्लेखनीय है कि पेंशनभोगियों को मिलने वाली महँगाई राहत और कर्मचारियों को मिलने वाले महँगाई भत्ते को एक साथ संशोधित किया जाता है। इससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी जीवन-यापन की बढ़ती लागत से कुछ हद तक संरक्षण मिलता है। भारत में वरिष्ठ नागरिकों की एक बड़ी आबादी सरकारी पेंशन पर निर्भर है और उनके लिए यह राहत मनोवैज्ञानिक और आर्थिक, दोनों दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है।आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि महँगाई भत्ते की नियमित समीक्षा और संशोधन की यह प्रक्रिया सरकारी तंत्र की एक उचित व्यवस्था है। यह सुनिश्चित करती है कि मूल्य वृद्धि का बोझ सरकारी कर्मचारियों के वेतन की वास्तविक क्रय शक्ति को बहुत अधिक कम न कर सके। परंतु इस व्यवस्था की एक सीमा यह है कि इसका लाभ केवल संगठित सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को ही मिलता है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, जो देश की कार्यबल का बड़ा हिस्सा हैं, इस प्रकार की किसी सुरक्षा से वंचित रहते हैं।अतः सरकार के सामने एक व्यापक चुनौती यह भी है कि वह ऐसी नीतियाँ बनाए जिनसे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को भी मुद्रास्फीति के विरुद्ध सुरक्षा मिल सके। न्यूनतम मजदूरी की समय-समय पर समीक्षा, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विस्तार और ग्रामीण रोजगार गारंटी जैसे कार्यक्रमों को इस दिशा में और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है।निष्कर्षतः, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा महँगाई भत्ते में की गई 2 प्रतिशत की वृद्धि एक स्वागत योग्य और आवश्यक कदम है। यह वृद्धि करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आर्थिक राहत प्रदान करती है और सरकार की अपनी कार्यबल के प्रति जिम्मेदारी को दशार्ती है। परंतु यह भी सत्य है कि यह वृद्धि महँगाई की समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। इसे एक व्यापक आर्थिक नीति के अंग के रूप में देखा जाना चाहिए, जिसमें मुद्रास्फीति नियंत्रण, आय वितरण में समानता और सामाजिक सुरक्षा का विस्तार भी शामिल हो। तभी इस प्रकार के निर्णय अपने वास्तविक उद्देश्य को पूर्णतः प्राप्त कर सकेंगे।

भगवान परशुरामः अन्याय,अत्याचार एवं दमनकारी वृत्तियों के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक

डॉ. उमेश चन्द्र शर्मा (हि.स)

त्रैता युग में जब परात्पर ब्रह्म के श्रीराम रुप में अवतरित होने पर संपूर्ण सृष्टि अलौकिक आनन्द वैभव से ओतप्रोत थी, और सब तरफ सात्विक भावों की प्रधानता थी, किंतु तब ऐसे ऊर्जा वान स्वर्णिम समय में भी मदोन्मत्त क्षत्रिय सत्ताधीषों की आतंक, अत्याचार एवं दमनकारी कुत्सित मनोवृत्ति के चलते भय और अशांति का वातावरण निर्मित हो गया था, तब उस भीषण काल में भगवान परशुराम का अभ्युदय हुआ, जिन्होंने सभी पाशविक वृत्तियों को पराभूत कर पृथ्वी पर अहिंसा, शांति और सद्भाव की स्थापना की। रक्तरंजित एवं विप्लवकारी कालखंड के उस विकराल दौर में दुष्ट, अहंकारी एवं अत्याचारी सत्ताधीशों का बाहुल्य हो गया था और उनके द्वारा ऋषि मुनि, गौ और ब्राह्मणों को असह्य पीड़ा पहुंचाई जाने लगी थी, तब अन्याय, अत्याचार, आतंक और व्यथा की उन विषम परिस्थितियों में सर्वशक्तिमान विश्वात्मा भगवान श्रीहरि ने भृगुवंशियों में परशुराम के रूप में अवतार ग्रहण किया। भगवान श्री विष्णु के छठवें अवतार के रूप में इस धराधाम पर अवतरित हुए पशुराम महाराज ने शिव प्रदत्त अपने अमोघ, विकराल परशू से आतंक की जड़ पर महाभीषण प्रहार करते हुए पृथ्वी के भारभूत राजाओं का नाश कर पृथ्वी का भार उतार दिया। भगवान परशुराम शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ और अपराजेय योद्धा थे, जिन्होंने भय और आतंक का नाश कर प्रेम, सौहार्द, शांति और निर्भयत्व की स्थापना की इसीलिए आज भी उनके महान्‌ यश का सारे संसार में गुणगान किया जाता है।

त्रैता युग के उस चुनौती पूर्ण भीषण दौर में जब राजाओं के आतंक से ऋषि मुनि, गौ एवं एवं ब्राह्मण व्यथित थे और वह व्यथा उस वक्त अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी, जब ऐसे ही दुष्ट राजाओं में से एक सहस्त्रार्जुन ने परशुराम के पिता जमदग्नि ऋषि की हत्या कर दी। पौराणिक काल की उस विकराल, वीभत्स एवं हृदयविदारक घटना ने पृथ्वी से अत्याचारियों के समूल नाश की शुरूआत कर दी और सहस्त्रबाहु अर्जुन के वध से शुरू हुआ दमनकारी राजाओं के वध का सिलसिला तब रुका जब उनका सर्वनाश हो गया। भगवान परशुराम ने इक्कीस बार पृथ्वी को क्षत्रिय राजाओं से रहित कर संपूर्ण रुप से पृथ्वी का भार उतार दिया। आरंभ में इन राजाओं ने उनके क्रोधावेग को केवल एक ब्राह्मण वेशधारी साधु का प्रलाप मानकर नजरअंदाज कर दिया था, किंतु जब क्षत्रियों पर उनका भीषण कुठार चला तो अंततः वे समूल नाश को प्राप्त हो गए।

श्रीमद्भागवत महापुराण के अनुसार परशुराम की गणना दशावतारों में होती है। वे वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, अर्थात अक्षय तृतीया को पुनर्वसु नक्षत्र में रात्रि के प्रथम प्रहर, प्रदोषकालीन महावेला में जमदग्नि ऋषि के पुत्र रूप में माता रेणुका के गर्भ से प्रादुर्भूत हुए थे। इस तरह हैहयवंश का अंत करने हेतु स्वयं भगवान् विष्णु ने परशुराम के रूप में अंशावतार ग्रहण कर दुष्ट राजाओं का नाश किया, और ऋषि मुनियों, गौ और ब्राह्मणों को अभयत्व प्रदान किया, वे भगवान श्रीहरि के अत्यंत प्रिय भक्त के रूप में अग्रगण्य और अजर अमर कहे गए है। इनकी गणना सात चिरजीवियों मे होती है, और वे आज भी महेंद्र पर्वत पर निवास करते हैं।

'श्रीमद्भागवत महापुराण में भगवान श्री शुकदेवजी महाराज कहते हैं, परीक्षित! जमदग्निनंदन भगवान परशुराम किसी को किसी प्रकार का दंड नहीं देते हुए आज भी शान्त चित्त से महेंद्र पर्वत पर निवास करते हैं, जहां सिद्ध, गन्धर्व और चारण उनके चरित्र का गुणगान किया करते हैं। आगामी मन्वन्तर में वे सप्तऋषियों के मंडल में रहकर वेदों का विस्तार करेंगे।'

भगवान परशुराम के अवतार का उद्देश्य जहां अन्याय और अत्याचार का समूल नाश था, वहीं दूसरी तरफ शार्ङ्गधनुष की रक्षा भी थी, जिसे त्रैता युग में भगवान विष्णु के ही अवतार श्री राम को सौंपा जाना था। विश्वकर्मा द्वारा भगवान विष्णु के लिए निर्मित यह शार्ङ्गधनुष भगवान विष्णु का अत्यंत शक्तिशाली दिव्यास्त्र माना जाता है, जो स्वयं अविनाशी होते हुए भी शत्रुओं के लिए कालरुप था। यही शार्ङ्गधनुष भगवान परशुराम के समक्ष एक चुनौती के रूप में मौजूद था, जिसे मनुष्य रूप में पृथ्वी पर विचरण कर रहे परब्रह्म को सौंपा जाना था, इसी बात को लेकर वे ब्रह्म का अनुसंधान करने लगे और तब शिव धनुष भंग होने पर राजा जनक की सभा में भगवान परशुराम का क्रोधावेश वस्तुतः उस परब्रह्म परमात्मा के अनुसंधान का ही एक प्रयास था, जिसके माध्यम से वे ब्रह्म का दर्शन कर शार्ङ्गधनुष रुपी धरोहर उन्हें लौटाना चाहते थे और जब उनके और श्रीराम के बीच हुए संवाद ने रहस्यात्मक दौर में प्रवेश किया तब उनका वह अनुसंधान पूर्णता की और जा चुका था।

श्रीरामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास के अनुसार भगवान श्री राम परशुराम से बोले कि- 'ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता (महिमा) है कि जो आपसे डरता है, वह सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भयरहित होता है, वह भी आपसे डरता है।' भगवान श्रीराम के इस रहस्यमय वचन को सुनकर श्री परशुराम की बुद्धि के बंद द्वार खुल गए। प्रभु के रहस्यमय वचन सुनकर और मनुष्य रूप में विचरण कर रहे अपने स्वामी के परमात्म स्वरूप का अनुभव कर परशुराम यद्यपि निश्चिन्त हो चुके थे, तथापि संशय के समूल नाश हेतु उन्होंने भगवान श्री राम से ही निवेदन किया। पुराण संहिताओं के अनुसार ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कोई भी महापुरुष शार्ङ्गधनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सकता। श्रीरामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि अपने मन में ऐसा विचार कर श्री परशुराम ने भगवान श्रीराम को दिव्य शार्ङ्गधनुष देते हुए निवेदन किया कि- 'हे राम ! यह लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिये, अथवा यह कि इस पर प्रत्यंचा चढ़ाइए, जिससे मेरा सन्देह मिट जाए।'

ऐसा कहकर जब परशुराम प्रभु श्रीराम को धनुष देने को उद्यत हुए तब बड़ी ही विस्मयकारी घटना हुई कि वह धनुष स्वयमैव प्रभु के पास चला गया। भगवान श्रीराम का ऐसा अद्भुत और अलौकिक प्रभाव जानकर श्री परशुराम हर्षातिरेक से भर उठे, और प्रेम गद्गद् हृदय से भगवान श्रीराम का गुणगान करते हुए बारम्बार उनकी जय-जयकार करने लगे।

(लेखक हिन्दुस्थान समाचार से संबद्ध हैं।)

नासिक टीसीएस प्रकरणः क्या गलत नीति ही समस्या की जड़ है?

डॉ. पंकज जगन्नाथ जयस्वाल (हि.स)

नासिक स्थित टीसीएस मामले में हिंदुओं और हिंदू महिलाओं के खिलाफ सामने आए भयावह खुलासों ने सच्चाई का पिटारा खोल दिया है। विभिन्न कंपनियों के कई कर्मचारियों ने अपने कार्यस्थलों पर इसी तरह की समस्याओं को उजागर किया है। इस बात का विश्लेषण जरुरी है कि वामपंथी इस्लामी कट्टरपंथी हिंदुओं को क्यों निशाना बना रहे हैं। इसके प्रमुख कारणों में से एक विविधता, समानता और समावेशन (डीईआई) की गलत नीति है। इसकी आड़ में वामपंथी विचारधारा के समर्थक कई कंपनियों में महत्वपूर्ण पदों पर पहुंच गए हैं।वे अपने पद का उपयोग कंपनी या संगठन के निर्माण के लिए नहीं बल्कि भारत में स्थापित कंपनियों में भारतीय संस्कृति को नष्ट करने के लिए कर रहे हैं। वामपंथी विचारधारा के लिए कंपनी और प्रबंधन उनके हिंदू-विरोधी और भारत-विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाने का एक हथियार मात्र हैं, जो अंततः अविश्वास, दबाव, धर्मांतरण, उत्पीड़न और यौन शोषण के माध्यम से कॉरपोरेट जगत और भारत को कमजोर करते हैं।

कर्मचारियों की कार्यकुशलता, प्रभावशीलता और कार्य की गुणवत्ता पर अत्यधिक तनाव, नैतिक मानकों के विरुद्ध कार्य करने और जन्म से ही उनमें समाहित भारतीय संस्कृति का प्रभाव के विरुद्ध काम तणाव निर्माण करता है। टीसीएस मामला सभी कॉरपोरेशनों के लिए एक चेतावनी है; अब समय आ गया है कि वे अपनी वर्तमान स्थिति का आकलन करें और उचित कानूनी कार्रवाई करें। अगला कदम कंपनी में डीईआई नीति को सही तरीके सें लागू करना है। डीईआई रणनीति को 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' और 'वसुधैव कुटुंबकम' जैसे भारतीय आदर्शों के अनुरूप पूरी तरह से संशोधित करने की आवश्यकता है। कई कॉरपोरेशनों में मौजूदा डीईआई प्रणाली इन मानवीय आदर्शों का उल्लंघन करती है। वर्तमान सिद्धांत विभाजन और ध्यान भटकाने के लिए विविधता, प्रवर्तन के लिए समानता और इस्लाम के लिए समावेशन हैं। अंततः, मानवता का ऐसा विकृत दृष्टिकोण कॉरपोरेट विनाश का कारण बनेगा। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के संदर्भ में आप जो भी अच्छा काम करें, आपकी विविधता और समावेशन नीति आपकी प्रतिष्ठा और विकास सहित सब कुछ बर्बाद कर देगी।

पिछले कुछ दशकों में डीईआई की अवधारणा एक प्रतीकात्मक महत्वाकांक्षा से विकसित होकर नियोक्ता की विश्वसनीयता, संस्कृति और अनुपालन परिपक्वता के आकलन के लिए एक परिभाषित मानक बन गई है, जिसका उपयोग उसके स्वयं के कर्मचारियों के साथ-साथ नियामकों, हितधारकों और आम जनता द्वारा भी किया जाता है। हालांकि कई संगठनों ने औपचारिक डीईआई प्रतिबद्धताएं की हैं, जैसा कि आंतरिक नीतियों, नेतृत्व के बयानों और सार्वजनिक घोषणाओं के साथ-साथ समावेशी भर्ती, मातृत्व सहायता, सुलभता अवसंरचना, उचित समायोजन और लैंगिक विविधतापूर्ण नेतृत्व की दिशा में उठाए गए कदमों से स्पष्ट है, फिर भी कार्यबल प्रणालियों में डीईआई का व्यावहारिक एकीकरण असमान बना हुआ है, क्योंकि कई कंपनिया हिंदुओं के प्रति पूर्वाग्रह का विशिष्ट एजेंडा अपना रहे हैं। विविधता, समानता, समावेशन और संवेदनशीलता डीईआई एक व्यापक शब्द है जिसका उद्देश्य हमारा ध्यान एक स्वस्थ और अधिक खुली कॉर्पोरेट संस्कृति की ओर आकर्षित करना है जो लोगों को उनके वर्ग, जाति, बोली, लिंग, पंथ, शारीरिक विशेषताओं आदि की परवाह किए बिना समान अवसर प्रदान करती है। हालांकि, अच्छे इरादों के बावजूद, वामपंथी विचारधारा ने इसका दुरुपयोग अपने स्वार्थी लाभों और उद्देश्यों के लिए किया है, जो कॉर्पोरेट सिद्धांतों और मानवता के बिल्कुल विपरीत हैं।

अमेरिका में विविधता, समानता और समावेशन

हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन के अनुसार, अमेरिका में डीईआई प्रशिक्षण कार्यक्रम हिंदू विरोधी भावना को बढ़ावा दे रहे हैं। फाउंडेशन ने न्यूयॉर्क टाइम्स और ब्लूमबर्ग पर इस अध्ययन को छिपाने का आरोप भी लगाया है। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने दो प्रमुख अमेरिकी मीडिया संस्थानों, न्यूयॉर्क टाइम्स और ब्लूमबर्ग पर एक रिपोर्ट को छिपाने का आरोप लगाया है, जिसमें यह खुलासा किया गया है कि अमेरिका में जाति-आधारित विविधता, समानता और समावेशन (डीईआई) प्रशिक्षण कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप हिंदुओं को किस प्रकार पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ता है। नेटवर्क कंटैजियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने रटगर्स विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी में यह अध्ययन किया, जिसमें विशेष रूप से इक्वालिटी लैब्स के जाति-विरोधी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जांच की गई और पाया गया कि ऐसे कार्यक्रम हिंदू विरोधी भेदभाव और घृणा को बढ़ाते हैं। नेटवर्क कंटैजियन रिसर्च इंस्टीट्यूट और रटगर्स विश्वविद्यालय द्वारा किए गए इस अध्ययन में दलित नागरिक अधिकार संगठन इक्वालिटी लैब्स की सामग्री का विश्लेषण किया गया। इस शोध में पाया गया कि इन प्रशिक्षणों में शामिल प्रतिभागियों द्वारा ब्राह्मणों को 'परजीवी' या 'वायरस' के समान बताने जैसी अमानवीय शब्दावली का प्रयोग करने की संभावना काफी अधिक थी। एचएएफ ने यह भी दावा किया कि शोध से पता चलता है कि इस तरह के डीईआई कार्यक्रम नस्लीय भेदभाव को कम करने के बजाय उसे और बढ़ा सकते हैं।प्रमुख मीडिया संगठनों की रुचि जताने के बावजूद, एचएएफ का आरोप है कि हिंदुओं के प्रति 'दंडात्मक प्रतिशोध' और बढ़ती शत्रुता के सबूतों को इन मुख्यधारा के मंचों ने लगभग अनदेखा कर दिया है।

भारत पर प्रभाव

विविधता, समानता और समावेशन के नाम पर चल रहे 'वोक' के औजार भारत तक भी पहुंच रहे हैं। सभ्यता अध्ययन के क्षेत्र में प्रख्यात शोधकर्ता, लेखक और अग्रणी राजीव मल्होत्रा ने अपनी पुस्तकों में कहा है कि 'वोक' तंत्र अब विविधता और समावेशन को बढ़ावा देने के बहाने भारत के शीर्ष शिक्षण संस्थानों, जैसे कि क्क्र्ळ, को निशाना बना रहा है। भारतीय संदर्भ में, 'वोक' लॉबी द्वारा दलितों के अधिकारों की वकालत करने का दिखावा तथाकथित उच्च जातियों को बदनाम कर रहा है और दलितों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों को उनके खिलाफ खड़ा कर रहा है। यह एक घातक प्रयोग है, और भारत पहले से ही इसका परीक्षण स्थल बन रहा है।

इसी प्रकार, जैसा कि राजीव मल्होत्रा चेतावनी देते हैं, विविधता और समावेशन की बयानबाजी भारत के सॉफ्टवेयर व्यवसायों में भी अपना प्रभाव दिखा रही है, जिससे हिंदुओं को विभाजित करने और योग्यता-आधारित व्यवस्था को नष्ट करने के प्रयास में जातिगत मुद्दा और भी गंभीर हो रहा है। प्रेम जिहाद और धर्मांतरण ने कई कंपनियों पर गहरा प्रभाव डाला है, जो हिंदुओं, व्यावसायिक विकास और भारतीयता के लिए अत्यंत चिंताजनक है।जो लोग यह मानने से इनकार करते हैं कि ऐसी घटनाएं नहीं होतीं, उन्हें प्रेम जिहाद और धर्मांतरण के पीड़ितों से मिलना चाहिए। यदि उन्हें कुछ भी गलत नहीं लगता, तो यह स्पष्ट है कि वे मनुष्य नहीं, बल्कि आधुनिक सभ्यता के राक्षस हैं। भावी पीढ़ियों और भारतीयता को इस विषैली पारिस्थितिकी से बचाने के लिए विश्वविद्यालयों को भी इस मुद्दे को समयबद्ध और प्रभावी ढंग से संबोधित करना चाहिए।

कंपनियों, सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), कर्मचारियों और प्रबंधन के लिए अब समय आ गया है कि वे सक्रिय रूप से काम करना शुरू करें और उचित कदम उठाएं। डीईआई पर विचार-विमर्श किया जाना चाहिए, सभी हितधारकों के साथ चर्चा की जानी चाहिए और फिर इसे अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। व्यवहार में, डीईआई को अनुसंधान और नवाचार क्षमताओं को मजबूत करना चाहिए, कार्यस्थल संस्कृति में सुधार करना चाहिए, तनाव को कम करना चाहिए और बिना किसी भेदभाव के व्यावसायिक और राष्ट्रीय लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

आज का राशिफल

मेषः आज कार्यक्षेत्र में आपको अपेक्षा से अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। किसी को जल्दबाजी में वादा करने से बचें, वरना बाद में मुश्किल हो सकती है। जीवनसाथी के करियर में सकारात्मक अवसर मिलेंगे। व्यापार में अचानक बदलाव देखने को मिल सकता है। *(सिटी दर्पण)*

वृषभः साझेदारी वाले कामों में तालमेल बेहतर होगा और पुराने मतभेद सुलझ सकते हैं। बीती बातों को लेकर तनाव न लें। स्वभाव में चिड़चिड़ापन हावी न होने दें। जिस काम के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, उसमें सफलता मिल सकती है। *(सिटी दर्पण)*

मिथुनः राजनीति से जुड़े लोगों को अपने करियर को लेकर चिंता रह सकती है। ज्यादा आत्मविश्वास के कारण छोटी गलतियां हो सकती हैं। किसी से भी गुस्से में बात करने से बचें। प्रतियोगी परीक्षाओं में उम्मीद से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। *(सिटी दर्पण)*

कर्कः जीवनसाथी के साथ खुशनुमा और रोमांटिक समय बिताने का अवसर मिलेगा। संतान के व्यवहार से संतोष मिलेगा। व्यापार में नकदी से जुड़ी समस्याओं का समाधान संभव है। आज आप घर पर आराम और परिवार के साथ समय बिताना पसंद करेंगे। *(सिटी दर्पण)*

सिंहः स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के नए अवसर मिल सकते हैं। नौकरी की तलाश कर रहे लोग इंटरव्यू दे सकते हैं। विद्वानों के बीच आपकी छवि मजबूत होगी। कोई शुभ समाचार मिलने की संभावना है। घर की सजावट पर खर्च हो सकता है। *(सिटी दर्पण)*

कन्याः आज आपका मन प्रसन्न रहेगा और परिस्थितियां आपके नियंत्रण में रहेंगी। दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी। हालांकि बिना कारण कुछ डर मन को परेशान कर सकता है। विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं। नए कामों को लेकर थोड़ी झिझक महसूस हो सकती है। *(सिटी दर्पण)*

तुलाः आज नए कार्यों की शुरूआत करने से बचना बेहतर रहेगा। व्यापार में नकदी की दिक्कत आ सकती है। प्रेम संबंधों में व्यवहार को संतुलित रखें। परिवार की उम्मीदों पर खरे उतरने का प्रयास करेंगे। स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रह सकता है और थकान महसूस होगी। *(सिटी दर्पण)*

वृश्चिकः घर में रिश्तेदारों का आना-जाना लगा रहेगा। बेरोजगार लोगों को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। प्रेम संबंध विवाह में बदल सकते हैं। लंबे समय से अटका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है। अधिकारी आपके काम से खुश रहेंगे। *(सिटी दर्पण)*

धनुः व्यापार में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। कानूनी मामलों में राहत मिल सकती है। महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता के संकेत हैं। गुस्से पर नियंत्रण रखें, नहीं तो काम बिगड़ सकते हैं। मित्रों के साथ व्यवहार अच्छा बनाए रखें। *(सिटी दर्पण)*

मकरः आप दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, लेकिन अनावश्यक मामलों में हस्तक्षेप न करें। घर में मेहमानों का आगमन हो सकता है। प्रेम जीवन सुखद रहेगा। दोस्तों के साथ किसी गंभीर विषय पर चर्चा हो सकती है। मेहनत से पीछे हटना आपके लिए ठीक नहीं होगा। *(सिटी दर्पण)*

कुंभः बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा और विद्यार्थी शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। काम की अधिकता के कारण परिवार को समय देना मुश्किल हो सकता है। वैवाहिक जीवन में हल्के मतभेद संभव हैं। व्यापार में तकनीकी दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन आप उन्हें जल्दी सुलझा लेंगे। *(सिटी दर्पण)*

मीनः आज आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे और अपनी तार्किक क्षमता से लोगों को प्रभावित करेंगे। कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहेंगे और नियमित व्यायाम करने का संकल्प ले सकते हैं। *(सिटी दर्पण)*

संसद में महिला अधिकार छीनकर खुश होले कांग्रेस!

डॉ. मयंक चतुर्वेदी (ह.स)

महिला आरक्षण विधेयक पर लोकसभा में हुई हालिया वोटिंग ने भारतीय राजनीति के एक महत्वपूर्ण विरोधाभास को उजागर किया है। ये दशार्ता है कि कांग्रेस, सपा एवं अन्य विपक्षी दल भले ही संसद एवं जनता के बीच महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, किंतु जब वास्तविक निर्णय का समय आता है, तब उनके ऊपर राजनीतिक स्वार्थ, संकीर्ण दृष्टिकोण इस बड़े उद्देश्य पर भी हावी हो जाता है। भारतीय राजनीतिक परिदृष्य में यह दुभाग्यपूर्ण है कि उन्होंने महिलाओं के अधिकारों को प्राथमिकता देने के बजाय राजनीतिक गणित को तरजीह दी।

सबसे पहले, इस पूरे घटनाक्रम को समझना जरूरी है। महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत, यानी 352 वोटों की आवश्यकता थी, किंतु इसके पक्ष में केवल 298 वोट ही पड़ सके। 230 सांसदों ने इसका विरोध किया, जिसके चलते यह विधेयक पास नहीं हो सका। अब भले ही इसे लेकर कांग्रेस एवं विपक्षी दल अपने कितने ही तर्क गढ़ें, हकीकत यह है कि यह परिणाम किसी राजनीतिक पार्टी के स्तर पर भाजपा के लिए विधायी असफलता नहीं है, यह तो देश की लगभग 50 प्रतिशत महिला आबादी की उम्मीदों को लगा एक गहरा झटका है।

कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इस विधेयक का विरोध सीधे तौर पर नहीं, बल्कि 'अगर-मगर' और 'किंतु-परंतु' के माध्यम से किया। उन्होंने विधेयक के क्रियान्वयन के तरीके, विशेषकर परिसीमन से जोड़ने पर आपत्ति जताई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे 'छलावा' करार दिया, किंतु आज जिस तरह से सदन में यह विधेयक गिरा, उससे साफ हो गया कि कांग्रेस सच में महिलाओं की कितनी बड़ी हिमायती है ! कहना होगा कि राहुल के सभी तर्क अपने आप में विरोधाभासी प्रतीत हुए हैं। यदि कांग्रेस वास्तव में महिला आरक्षण के पक्ष में थी, तो उसे इस विधेयक का समर्थन करते हुए बाद में संशोधन की मांग करनी चाहिए थी। लेकिन समर्थन के बजाय विरोध का रास्ता चुनना इस बात का संकेत है कि पार्टी की प्राथमिकता महिला सशक्तिकरण नहीं, बल्कि राजनीतिक लाभ-हानि का आकलन था। यही कारण है कि सत्ता पक्ष ने इसे 'दिखावटी समर्थन' और 'वास्तविक विरोध' की संज्ञा दी।

समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों की स्थिति भी कुछ अलग नहीं रही। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे पर सीधे समर्थन देने के बजाय सामाजिक समीकरणों और जातिगत प्रतिनिधित्व की बात उठाई। उनका तर्क था कि महिला आरक्षण के भीतर अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए अलग कोटा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यह मांग व्यवहारिक रूप से छोड़ें, सिद्धांततः भी उचित नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं देता है। जिस समय यह विधेयक पारित होने के कगार पर था, उस समय इस प्रकार की शर्तें जोड़ना वस्तुतः प्रक्रिया को जटिल बनाने और विधेयक को टालने का माध्यम ही दिखा।

यहां एक बड़ा प्रश्न उठता है, क्या विपक्ष वास्तव में महिलाओं के अधिकारों के प्रति प्रतिबद्ध है, या वह केवल अपने पारंपरिक वोट बैंक की राजनीति में उलझा हुआ है? यदि महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने का अवसर सामने था, तो उसे पहले स्वीकार कर लेना और बाद में उसमें सुधार की मांग करना अधिक व्यावहारिक और प्रभावी रणनीति होती, किंतु उसने ये रास्ता नहीं चुना और देश की उन तमाम महिलाओं का हक एक झटके में मार दिया, जोकि भविष्य में इस देश की कर्णधार बन सकती थीं।

काश, कांग्रेस मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से ही कुछ सीख ले लेती ! इस संदर्भ में यदि हम जमीनी स्तर पर देखें, तो कुछ राज्यों में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। मध्य प्रदेश में पंचायत स्तर पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व 50 प्रतिशत से अधिक हो चुका है। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत तीनों स्तरों पर महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 52-53 प्रतिशत तक पहुंच गई है। यह दशार्ता है कि जब राजनीतिक इच्छाशक्ति होती है, तो महिलाओं को नेतृत्व में आगे लाया जा सकता है। निश्चित ही इसके लिए मप्र की भाजपानीत डॉ. मोहन यादव की सरकार बधाई की पात्र है।

मध्य प्रदेश का यह उदाहरण विपक्षी दलों के लिए एक सीख हो सकता है। यहां न सिर्फ आरक्षण लागू किया गया, बल्कि उसे प्रभावी तरीके से क्रियान्वित भी किया गया। परिणामस्वरूप महिलाएं यहां पर नाममात्र की प्रतिनिधि न होकर पूर्णतः निर्णायक भूमिका में हैं, वे हर प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बन गई हैं। जल, स्वच्छता, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर उनकी प्राथमिकताओं ने ग्रामीण विकास को नई दिशा दी है।

इसके विपरीत, राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष की राजनीति अक्सर सैद्धांतिक बहसों और आशंकाओं में उलझी रहती है। परिसीमन को लेकर उठाई गई चिंताएं; जैसे उत्तर-दक्षिण असंतुलन या सीटों का पुनर्वितरण महत्वपूर्ण हो सकती हैं, किंतु इन्हें महिला आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे के रास्ते में बाधा बनाना उचित नहीं कहा जा सकता।

सत्ता पक्ष का यह आरोप कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने ऐतिहासिक रूप से भी सामाजिक न्याय के मुद्दों पर विलंब किया है, पूरी तरह निराधार नहीं है। ओबीसी आरक्षण के संदर्भ में काका कालेलकर आयोग और मंडल आयोग की सिफारिशों को लंबे समय तक लागू न करना, इस दिशा में कांग्रेस की धीमी गति को दशार्ता है। आज जब वही दल ओबीसी और महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं, तो उनके इरादों पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

इसके साथ कहना तो यह भी पड़ेगा कि वर्ष 2014 एवं 2019 में भारी बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पास था, तब क्यों नहीं उसने इस दिशा में प्रभावी पहल की, यदि की तो उसे परिणाम में बदलने के लिए इतना लम्बा इंतजार क्यों किया ? पर जो सामने से स्पष्ट दिखाई देता है वह यही है कि कांग्रेस समेत संपूर्ण विपक्ष पहले से ही ये मन बना चुका था कि सदन में इस 'महिला आरक्षण विधेयक' को पास होने ही नहीं देना है और वही हुआ ! राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का खेल चलता रहेगा, किंतु इससे उस महिला शक्ति की आकांक्षाएं पूरी नहीं होंगी, जोकि संसद या विधानसभा में अपनी आवाज उठाकर जनता के दर्द को दूर करने की मंशा रखती हैं।

इस पूरे प्रकरण से एक स्पष्ट संदेश तो अवश्य ही निकला है और वह यही है कि भारतीय राजनीति में अभी भी महिला सशक्तिकरण एक वास्तविक प्राथमिकता नहीं बन सकी है। यह सिर्फ एक चुनावी मुद्दा अवश्य है, जिसका उपयोग समय-समय पर राजनीतिक लाभ के लिए किया जाता रहा है और आगे भी किया जाता रहेगा ! वास्तव में अच्छा तो तब होता, जब कांग्रेस, सपा और अन्य विपक्षी दल इस मुद्दे पर सत्तारूढ़ भाजपा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। निश्चित ही उन्होंने एक ऐतिहासिक अवसर को गंवा दिया। उन्होंने अपनी वैचारिक और राजनीतिक आपत्तियों को प्राथमिकता दी, जबकि देश की आधी आबादी उनसे ठोस कदम की अपेक्षा कर रही थी। यदि वे वास्तव में महिलाओं के अधिकारों के प्रति प्रतिबद्ध होते, तो इस विधेयक को पास कराने में सहयोग करते और बाद में आवश्यक सुधारों के लिए संघर्ष करते।

इन दलों ने जो संदेश भारत के लोकतंत्र के सामने दिया है, वह यही है कि महिलाओं का अधिकार भी राजनीतिक सौदेबाजी का विषय बन गया है, जबकि यह हर दल के लिए एक संवैधानिक और नैतिक दायित्व होना चाहिए। जब तक राजनीति इस स्तर की परिपक्वता नहीं दिखाती, तब तक कहना यही होगा कि 'नारी सशक्तिकरण' सिर्फ भाषणों और घोषणाओं तक ही सीमित है। आज विपक्ष ने निश्चित ही देश को निराश किया है ! बहुत दुखद है, उसका ये निर्णय और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में स्त्री शक्ति का यह अपमान !

पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा एआई पर आयोजित दो-दिवसीय सम्मेलन में विद्यार्थियों को प्रौद्योगिकी के उपभोक्ताओं की बजाय सृजनकर्ता के रूप में तैयार करने पर जोर

डेटा गोपनीयता से लेकर अकादमिक तक: बोर्ड द्वारा गूगल, इंटेल और पीटीयू के सहयोग से स्कूलों में ए.आई. के उपयोग पर विभिन्न सत्र आयोजित

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

पंजाब की शिक्षा व्यवस्था में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को शामिल करने की दिशा में निर्णायक कदम उठाते हुए पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (पीएसईबी) द्वारा यहां सी.आई.आई. के नॉर्दर्न रीजन मुख्यालय में आयोजित दो-दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आज गूगल और इंटेल द्वारा व्यावहारिक वर्कशॉप के साथ समाप्त हो गया।

इस सम्मेलन ने क्लासरूम में एआई को शामिल करने के लिए एक उपयुक्त रोडमैप तैयार करने हेतु नीति निमार्ताओं, शिक्षकों और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों के लिए विचार-विमर्श का एक सार्थक मंच प्रदान किया। यह रोडमैप सीखने की गुणवत्ता में सुधार, पहुंच बढ़ाने और विद्यार्थियों को केवल उपभोक्ता न बनाकर प्रौद्योगिकी के निमार्ता के रूप में तैयार करने पर केंद्रित होगा।

पी.एस.ई.बी. के चेयरमैन डॉ. अमरपाल सिंह, आईएएस (सेवानिवृत्त) ने एआई के नैतिक उपयोग पर जोर दिया और कहा कि इसका उपयोग शिक्षार्थियों की रचनात्मकता और समस्या-समाधान कौशल को निखारने के लिए किया जा सकता है। आज के डिजिटल युग में, जहाँ एआई-आधारित उपकरण हमारे स्थायी साथी बन गए हैं, विद्यार्थियों से आग्रह किया गया कि वे ऐसे उपकरणों का चुनाव उसी तरह पूरी समझदारी और परख से करें, जैसे हम अपने मित्रों का चुनाव करते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को एआई का उपयोग पूरी जिम्मेदारी से और एक स्पष्ट कानूनी एवं नैतिक ढांचे में रहकर करने के लिए प्रोत्साहित किया, जो मुख्य उद्देश्यों से समझौता किए बिना उनके लिए सीखने में

लाभकारी साबित हो।

गूगल के नेतृत्व वाले सत्र में शिक्षा में एआई की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला गया, जिसमें संवेदनशीलता और जागरूकता-निर्माण पर जोर दिया गया। विचार-विमर्श के दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि शिक्षकों से लेकर प्रशासकों तक, शिक्षा प्रणाली के प्रमुख हिस्सेदार पहले से ही एआई-आधारित दृष्टिकोण से जुड़ रहे हैं और इसे अपना रहे हैं, जो इस बदलाव के लिए हमारी मजबूत तैयारी को दशार्ता है।

सम्मेलन का एक मुख्य हिस्सा ₹कार्य स्थल पर एआई का उपयोग₹ विषय पर इंटेल की व्यावहारिक कार्यशाला थी, जिसमें 112 से अधिक प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सत्र के दौरान सरकारी ढांचे के भीतर एआई उपकरण स्थापित करने पर व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें डेटा गोपनीयता, जिम्मेदारी से उपयोग और संगठन-विशिष्ट या संवेदनशील जानकारी को अनजाने में साझा करने जैसी स्थितियों की रोकथाम के लिए सुरक्षा उपायों पर जोर दिया गया।

आईकेजी पीटीयू द्वारा ₹स्कूल लीडरों के लिए स्कूलों में एआई₹ विषय पर एक और कार्यशाला आयोजित की गई, जो विशेष रूप से प्रिंसिपलों और स्कूल प्रमुखों को ध्यान में रखकर तैयार की गई थी। यह संस्थागत नेतृत्व और शैक्षणिक प्रबंधन में एआई उपकरणों को एकीकृत करने पर केंद्रित थी। साथ ही, एआई-सक्षम वातावरण में शैक्षणिक अखंडता को बनाए रखने के लिए स्कूलों द्वारा एआई-आधारित सामग्री की पहचान की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया।

नीव एआई द्वारा आयोजित छात्र-केंद्रित कार्यशाला ₹एआई इन एजुकेशन₹ ने एआई-आधारित एप्लीकेशनों में व्यावहारिक कौशल का प्रशिक्षण दिया। इस सत्र के दौरान विद्यार्थियों को व्यावहारिक उपयोग के मामलों से अवगत कराने के साथ-साथ उनमें एआई की प्रारंभिक, बुनियादी समझ को बढ़ावा दिया गया। साथ ही, उन्हें उभरते हुए उपकरणों के जिम्मेदार उपयोग के लिए भी प्रोत्साहित किया गया।

चेयरमैन ने बताया कि इसके साथ ही विद्यार्थियों को यह भी जानकारी दी गई कि एआई टूल कैसे विकसित किए जाते हैं, उनके पीछे की प्रक्रियाएँ क्या हैं, और ऐसी प्रौद्योगिकियों को बनाने के लिए आवश्यक विविध कौशल सेट कौन-से हैं। इस एक्सपोजर ने विद्यार्थियों की समझ को और गहरा करने के साथ-साथ उन्हें एआई और अन्य उभरते क्षेत्रों में भविष्य के मार्गों का पता लगाने के लिए प्रेरित किया। इस कार्यशाला में पंजाब के विद्यार्थियों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया और उनकी जिज्ञासा, अनुकूलनशीलता तथा उभरती प्रौद्योगिकियों से जुड़ने की इच्छा ने आने वाले वर्षों में एआई-आधारित शिक्षा के क्षेत्र में असीम संभावनाओं को उजागर किया।

डॉ. अमरपाल सिंह ने दो-दिवसीय सम्मेलन के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए एलिक्स इवेंट्स के प्रयासों की सराहना की।

पटियाला के ड्राइवर की मां ने कैंसर को हराया ; मुख्यमंत्री सेहत योजना बनी मुश्किल समय की सहारा

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़/पटियाला

पटियाला के रहने वाले गुरपिंदर जीत सिंह की जिंदगी पांच महीने पहले अचानक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई, जहां हर रास्ता मुश्किल नजर आने लगा था। उनकी 65 वर्षीय माता बलजीत कौर ने गंभीर बीमारी के कारण धीरे-धीरे खाना-पीना छोड़ दिया था। मजबूर और बेबस बेटे के लिए यह सिर्फ बीमारी नहीं, बल्कि रोज टूटती जा रही उम्मीदों का दर्द था।

गुरपिंदर जीत के अनुसार पहले निजी डॉक्टरों के पास दौड़-भाग की गई, फिर मां को राजिंद्रा अस्पताल, पटियाला रेफर कर दिया गया। दवाइयां चलीं, टेस्ट हुए, लेकिन हालत सुधरने की बजाय और गंभीर हो गई। जब रिपोर्ट आई तो जैसे आसमान ही ढह पड़ा—मां को बच्चेदानी का कैंसर था।

गुरपिंदर के लिए यह बहुत मुश्किल

घड़ी थी, यह उस मां की जिंदगी का सवाल था जिसने उसे जन्म दिया और पाला-पोसा। आज वह जिंदगी और मौत से जूझ रही थी। बिना देरी किए वह मां को संगरूर के टाटा कैंसर अस्पताल ले गया। इलाज शुरू हुआ, लेकिन पहले ही झटके में 60 हजार रुपये से अधिक खर्च हो गए। एक ड्राइवर की सीमित आय के सामने यह राशि पहाड़ जैसी थी।

गुरपिंदर के मन में एक ही सवाल था—मां को कैसे बचाऊं? कर्ज लेने की नौबत भी आ गई थी। तभी, जैसे अंधेरे में एक रोशनी की किरण उसके सामने आई। अस्पताल में उसे मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के बारे में पता लगा।

बिना और देरी किए गुरपिंदर ने वहीं रजिस्ट्रेशन करवा लिया। कुछ समय बाद ही उसके मोबाइल पर मैसेज आ गया और स्मार्ट कार्ड बन गया। इसके बाद जो हुआ, वह उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। लाखों रुपये का इलाज—जिसमें महंगे टेस्ट, बार-बार कीमोथेरेपी, दवाइयां, ऑपरेशन, आईसीयू, वेंटिलेटर और अस्पताल में रहने-खाने तक का खर्च शामिल था—सारा खर्च सरकार ने उठाया। गुरपिंदर की आंखें भर आती हैं जब वह कहता है, मां तो मां होती है॒उसे हर हाल में बचाना था। पैसे नहीं थे, लेकिन रब ने इस योजना के रूप में रास्ता दिखा दिया। डॉक्टरों के लिए भी यह केस बहुत चुनौतीपूर्ण था। कैंसर बच्चेदानी से आगे बढ़कर लीवर और फेफड़ों तक फैल गया था। पहले तीन बार कीमोथेरेपी दी गई, लेकिन शरीर कमजोर होने के कारण साइड इफेक्ट सामने आए। फिर धीरे-धीरे डोज कम करके नौ बार और कीमोथेरेपी दी गई।

इलाज के बाद ट्यूमर एक जगह सिमट गया और डॉक्टरों ने लगभग आठ घंटे लंबा ऑपरेशन करके उसे निकाल दिया। 35 से 40 टांकों के साथ मां ने दर्द सहते हुए भी जिंदगी की डोर थामे रखी। मां ऑपरेशन के बाद दो-तीन दिनों के लिए आईसीयू में और वेंटिलेटर पर रहीं, फिर उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया।

सरहद पार से नशा तस्करी करने वाले मॉड्यूल के दो व्यक्ति 64.6 किलो हेरोइन समेत अमृतसर से काबू

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़ / अमृतसर

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निदेर्शों पर पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने के उद्देश्य से चल रही मुहिम के दौरान नार्को-आतंकवादी नेटवर्क को बड़ा झटका देते हुए काउंटर इंटेलीजेंस विंग की स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल (एसएसओसी) अमृतसर यूनिट ने सरहद पार से नशा तस्करी करने वाले मॉड्यूल के दो मुलजिमों को 64.62 किलोग्राम हेरोइन समेत गिरफ्तार करके इस मॉड्यूल का पदार्फाश किया है। यह जानकारी पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने आज यहां साझा की।

गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान अमृतसर के गांव अवान वासाऊ के निवासी सरवन सिंह उर्फ गुज्जर और अमृतसर के गांव दयाल रंगड़ के रहने

वाले शमशेर सिंह उर्फ शेरा के रूप में हुई है। पुलिस टीम ने हेरोइन की बड़ी खेप बरामद करने के अलावा मुलजिमों की मारुति स्विफ्ट कार भी जब्त की है, जिसका वे नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए इस्तेमाल करते थे। डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि इस मॉड्यूल के पाकिस्तानी तस्करों और पुर्तगाल आधारित हैंडलर से भी संबंध हैं।

उन्होंने कहा, सरहद पार से तस्करी करने वाले इस गिरोह के पाकिस्तानी तस्कर मूसा, जिसका नाम 532 किलोग्राम हेरोइन रिकवरी मामले में सामने आया था, से भी संबंध हैं। उल्लेखनीय है कि भारतीय कस्टम अधिकारियों ने 2019 में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट (आईसीपी) अटारी में 532 किलोग्राम हेरोइन की सबसे बड़ी बरामदगी की थी। डीजीपी ने कहा कि इस मामले में पूरे नेटवर्क का पता लगाने के लिए आगे-पीछे के संबंध स्थापित करने हेतु और जांच की जा रही है।

ऑपरेशन संबंधी विवरण साझा करते हुए ए.आई.जी. एस.एस.ओ.सी. अमृतसर सुखमिंदर सिंह मान ने बताया कि विश्वसनीय सूत्रों से पुख्ता जानकारी मिली थी कि संदिग्ध सरवन सिंह और शमशेर सिंह ने कुछ दिन पहले सरहद पार से ड्रोन के जरिए हेरोइन की खेप प्राप्त की है। उन्होंने बताया कि जानकारी पर और छानबीन करने पर पता लगा कि अपने हैंडलरों के निदेर्शों पर ये दोनों प्राप्त की गई खेप को किसी अन्य पक्ष तक पहुंचाने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि तेजी से कार्रवाई करते हुए एस.एस.ओ.सी. अमृतसर यूनिट टीम ने मुलजिमों को अमृतसर के महल बाईपास के पास काबू किया और उनके कब्जे से 64.62 किलोग्राम हेरोइन बरामद की।

ए.आई.जी. ने कहा कि गिरफ्तार किए गए मुलजिमों को उनके हैंडलरों द्वारा खेप डिलीवर करने के बदले बड़ी रकम देने का वादा किया गया था।

कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत द्वारा रक्षा सेवा कल्याण विभाग के कार्यों की प्रगति का जायजा

चंडीगढ़ । पंजाब के रक्षा सेवा कल्याण मंत्री श्री मोहिंदर भगत ने शुक्रवार शाम पंजाब सचिवालय में रक्षा सेवा कल्याण विभाग के कार्यों की प्रगति का जायजा लेने के लिए उच्च अधिकारियों के साथ एक विशेष बैठक की। इस अवसर पर रक्षा सेवा कल्याण विभाग के प्रधान सचिव सुमेर सिंह गुर्जर और निदेशक भूपिंदर सिंह ढिल्लों (सेवानिवृत्त) विशेष रूप से उपस्थित थे।

बैठक के दौरान अधिकारियों ने मंत्री को जानकारी दी कि पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों से संबंधित मामलों में काफी प्रगति हुई है। उन्होंने बताया कि विभिन्न युद्धों के दौरान शहीद हुए अधिकांश सैनिकों के परिवारों को पंजाब सरकार द्वारा पहले ही मुआवजा दे दिया गया है। इसके अलावा बाकी बचे मामलों और उनकी वर्तमान स्थिति पर भी विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। अधिकारियों ने बताया कि खाली पदों को भरने के लिए कार्रवाई भी तेजी से की जा रही है। इस मौके पर विभागीय बजट और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया गया।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्री श्री भगत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों से संबंधित सभी मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए। उन्होंने कहा कि देश की रक्षा करते हुए अपनी जान न्योछावर करने वाले बहादुर सैनिकों के प्रति पंजाब सरकार पूर्ण श्रद्धा और सम्मान रखती है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की भलाई के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और उनकी हर संभव सहायता के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

विश्व लीवर दिवस 2026: द लैंसेट ने विश्व स्तर पर लीवर बीमारियों में वृद्धि की चेतावनी दी, पंजाब ने मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत तैयारी तेज की, स्क्रीनिंग का विस्तार

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

दुनिया भर में 19 अप्रैल को सॉलिड हैबिट्स, स्ट्रॉन्ग लीवर (स्वस्थ आदतें, स्वस्थ लीवर) थीम पर मनाए जाने वाले विश्व लीवर दिवस के अवसर पर, द लैंसेट की एक चेतावनी ने लीवर बीमारियों में तेजी से हो रही विश्व स्तर की वृद्धि को उजागर किया है।

रिपोर्ट के अनुसार मेटाबोलिक डिस्फंक्शन-एसोसिएटेड स्टेटोहैपेटिक लीवर डिजीज (एमएएसएलडी) के मामलों में 2050 तक तेज वृद्धि होने की संभावना है। इस चिंताजनक स्थिति के बीच, पंजाब इस चुनौती का डटकर सामना करने के लिए आगे बढ़ रहा है। राज्य ने विस्तृत स्क्रीनिंग और कैशलेस मुख्यमंत्री सेहत योजना के माध्यम से अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया है, जिससे वह आधुनिक जीवनशैली से जुड़ी इस तेजी से बढ़ रही मूक महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।

दुनिया भर में लीवर संबंधी बीमारियां एक मूक महामारी के रूप में उभर रही हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का अनुमान है कि लगभग हर तीन में से एक वयस्क व्यक्ति इससे प्रभावित है। यह ऐसी बीमारी है जिसके लक्षण अक्सर तब सामने आते हैं जब गंभीर नुकसान हो चुका होता है। द लैंसेट का अध्ययन चेतावनी देता है कि मरीजों की संख्या 2023 में 1.3 अरब से बढ़कर 2050 तक 1.8 अरब हो सकती है, जो 42 प्रतिशत की वृद्धि को दशार्ता है। भारत में भी इसी तरह का रुझान देखा जा रहा है, खासकर शहरी आबादी और उच्च-जोखिम समूहों में यह संख्या तेजी से बढ़ रही है।

पंजाब में डॉक्टरों के अनुसार हेपेटाइटिस-सी संक्रमण, शराब के सेवन और बदल रही खान-पान की आदतों के कारण स्थिति और गंभीर हो रही है। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंसेज (ढक्कछइर) के डायरेक्टर डॉ. वीरेंद्र सिंह ने कहा, भारत में लीवर की गंभीर बीमारियों के मुख्य कारणों में शराब एक बड़ा कारण है और यह वायरल हेपेटाइटिस के साथ मिलकर हालत को और भी खराब कर देती है। फैटी लीवर डिजीज अब शराब और हेपेटाइटिस-सी के साथ एक मुख्य कारण के रूप में उभर रही है। अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाना, तली हुई चीजें और ट्रांस-फैट्स का लंबे समय तक सेवन समस्या को बढ़ा रहा है।

डॉक्टर एक चिंताजनक बदलाव भी देख रहे हैं कि कम उम्र के मरीजों में लीवर की बीमारियां तेजी से सामने आ रही हैं। इसका मुख्य कारण शराब का बढ़ता सेवन और हेपेटाइटिस-सी का फैलाव है, जो राज्य में बदल रही जीवनशैली और व्यवहारिक रुझानों को दशार्ता है।

स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में उन्होंने बताया, पंजाब ने अपनी रेफरल प्रणाली को मजबूत किया है, जिससे लीवर बीमारियों की पहले की तुलना में जल्दी पहचान हो रही है। गांवों में स्क्रीनिंग और विशेषज्ञ सेवाओं तक पहुंच भी सुधरी है, हालांकि फैटी लीवर की मूक प्रकृति के कारण देर से पहचान की समस्या अभी भी मौजूद है।

जन स्वास्थ्य कार्यक्रमों के तहत विस्तृत स्क्रीनिंग से, शुरूआती पहचान में सुधार होने और बीमारी की प्रगति को धीमा करने की उम्मीद है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि लीवर डिजीज के शुरूआती चरण को जीवनशैली में बदलाव जैसे बेहतर खुराक, नियमित शारीरिक गतिविधियां और शराब के सेवन में कमी करके अक्सर ठीक किया जा सकता है।

संक्षिप्त-समाचार

आंगनवाड़ी वर्कर्रों और हेल्परों की भलाई को पंजाब सरकार द्वारा विशेष प्राथमिकता : डॉ. बलजीत कौर

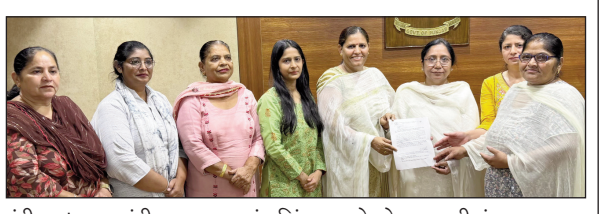

चंडीगढ़। मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार जहां समाज के हर वर्ग की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है, वहीं आंगनवाड़ी वर्कर्रों और हेल्परों की भलाई को भी विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। पंजाब सरकार द्वारा आंगनवाड़ी वर्कर्रों और हेल्परों की समस्याओं के समाधान और उनकी भलाई के लिए लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। यह बात सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कही। पंजाब भवन, चंडीगढ़ में सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग की डायरेक्टर श्रीमती शेना अग्रवाल और डिप्टी डायरेक्टर श्रीमती सुमनदीप कौर की मौजूदगी में आंगनवाड़ी वर्कर्रों और हेल्परों के साथ बैठक करते हुए कहा कि आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर विभाग का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और वे जमीनी स्तर पर बच्चों, महिलाओं और परिवारों तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आंगनवाड़ी वर्कर्रों और हेल्परों की हर जायज मांग को गंभीरता से विचार करके पूरी की जाएगी। बैठक के दौरान आंगनवाड़ी वर्कर्रों और हेल्परों द्वारा उठाई गई मांगों को कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बड़े ध्यान से सुना। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि आंगनवाड़ी वर्कर्रों और हेल्परों की समस्याओं का शीघ्र और प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाए।

रूपनगर में पंजाब राज्य गतका चैंपियनशिप का आगाज

रूपनगर। गतका एसोसिएशन ऑफ पंजाब के नेतृत्व में जिला गतका एसोसिएशन रूपनगर द्वारा आयोजित 12वीं पंजाब राज्य गतका चैंपियनशिप का आज भव्य शुभारंभ हुआ। गुरु नानक मॉडल स्कूल लौधीपुर में आयोजित इस दो दिवसीय चैंपियनशिप में पंजाब के 15 जिलों की टीमें भाग ले रही हैं जिससे खालसाई खेल का माहौल अपने पूरे उत्कर्ष पर है। टूर्नामेंट का उद्घाटन संत बाबा अवतार सिंह जी टिब्बी साहिब ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य जत्थेदार परमजीत सिंह लखोवाल, नेशनल गतका एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सरदार हरजीत सिंह ग्रेवाल एडवोकेट तथा जिला गतका एसोसिएशन की अध्यक्ष बीबी मनजीत कौर की उपस्थिति में किया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने गतका खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए गतका एसोसिएशन पंजाब द्वारा इस खेल के विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने गतका के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए हर संभव सहयोग देने का भरोसा भी दिलाया। इस मौके पर शिरोमणि कमेटी के सदस्य जत्थेदार परमजीत सिंह लखोवाल ने खिलाड़ियों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि जिला रूपनगर गतका के क्षेत्र में काफी अग्रणी है और पिछले वर्ष भी नेशनल गतका चैंपियनशिप के दौरान यहां के खिलाड़ियों ने पंजाब टीम का नेतृत्व करते हुए कई पदक जीते थे। उन्होंने नेशनल गतका एसोसिएशन के अध्यक्ष ग्रेवाल द्वारा गतका के विकास हेतु किए जा रहे सतत प्रयासों की भी प्रशंसा की।

सांसद विक्रमजीत सिंह साहनी द्वारा सिखों से जुड़े सभी मामलों पर काउंसिल को पूर्ण सहयोग का आश्वासन

ग्लोबल सिख काउंसिल द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता, तकनीकी बेअदबी और गुरमुखी के मुद्दे संसद में उठाने की माँग

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

28 देशों में सिख संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था ग्लोबल सिख काउंसिल के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में राज्यसभा सदस्य सरदार विक्रमजीत सिंह साहनी से मुलाकात कर सिखों की धार्मिक स्वतंत्रता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से पवित्र गुरबाणी, गुरु साहिबान और सिख संस्थाओं के अपमान तथा भाषाई विरासत के संरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर त्वरित विधायी और प्रशासनिक कदम उठाने की मांग की। अमेरिका से काउंसिल के उपाध्यक्ष सरदार परमजीत सिंह बेदी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने आधुनिक डिजिटल तकनीकों के दुरुपयोग और सिख कौम के सामने खड़ी चुनौतियों के समाधान हेतु इन विषयों को संसदीय स्तर पर उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस बैठक में अन्य सदस्यों के अलावा काउंसिल के कोषाध्यक्ष सरदार हरसरन सिंह पुडुचेरी, अफगानिस्तान से सदस्य सरदार गुलजीत सिंह तथा सिख कलेक्टिव के संयोजक सरदार जगमोहन सिंह भी शामिल रहे। काउंसिल की अध्यक्ष डॉ. कंवलजीत कौर यूके का विशेष संदेश देते हुए सरदार बेदी ने संसद में सिख मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने के लिए सरदार साहनी के प्रयासों की सराहना की। प्रतिनिधिमंडल ने विशेष रूप से पंजाब सहित विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं के लिए शिक्षा और कौशल विकास से जुड़े उनके प्रयासों को सराहा।

बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई जिनमें प्रमुख रूप से देशभर में विभिन्न परीक्षाओं के दौरान सिख छात्रों को अपने धार्मिक ककारों के कारण झेलनी पड़ रही समस्याएं शामिल रहीं। अमृतधारी परीक्षार्थियों को अक्सर कड़ा, कृपाण और दस्तार जैसे धार्मिक प्रतीक उतारने के लिए बाध्य किया जाता है जिससे उनकी गरिमा और संवैधानिक धार्मिक अधिकारों को ठेस पहुंचती है। काउंसिल ने इस मुद्दे को गंभीर मानते हुए इसके त्वरित समाधान की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके अतिरिक्त काउंसिल ने तकनीकी बेअदबी को लेकर भी गहरी चिंता व्यक्त की जिसके तहत कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आधुनिक डिजिटल तकनीकों के माध्यम से गुरबाणी, सिख संस्थाओं और सिख सिद्धांतों को सोशल मीडिया पर तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रतिनिधिमंडल ने केंद्र सरकार से अपील की कि ऐसी भ्रामक और धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली डिजिटल सामग्री पर रोक लगाने के लिए सख्त नियम बनाए जाएं ताकि सिख मर्यादा की पवित्रता बनी रहे।

इसके अलावा सिख इतिहास, पहचान और धार्मिक मूल्यों से जुड़े मामलों में संतुलित और तथ्याधारित मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड में एक योग्य सिख विद्वान की नियुक्ति की मांग भी की। साथ ही दिल्ली की पंजाबी अकादमी की कमजोर प्रशासनिक स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए इसकी कार्यप्रणाली की समीक्षा करने की आवश्यकता पर बल दिया गया ताकि राजधानी में बसे सिखों के बीच पंजाबी भाषा, साहित्य और संस्कृति को मजबूत किया जा सके।

काउंसिल ने केंद्रीय गुरमुखी विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग करते हुए इस संस्थान को केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के समान राष्ट्रीय दर्जा और पूर्ण संस्थागत समर्थन प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि पंजाबी भाषा और गुरमुखी लिपि न केवल सांस्कृतिक बल्कि धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं इसलिए इनके संरक्षण, संवर्धन और प्रसार के लिए एक विशेष राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना आवश्यक है।

इन सभी मुद्दों पर सरदार साहनी ने प्रतिनिधिमंडल को पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि वे इन मुद्दों को संसद में उठाएंगे और संबंधित केंद्रीय मंत्रियों के साथ लिखित रूप में भी साझा करेंगे। उन्होंने सिख कौम की भलाई तथा धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास का समर्थन करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक के दौरान सरदार साहनी को इसी वर्ष अक्टूबर में चंडीगढ़ में आयोजित होने वाली काउंसिल की वार्षिक बैठक में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया।

होर्मुज जलडमरूमध्य पर तनाव: ईरान ने अमेरिका को दी कड़ी चेतावनी, नाकेबंदी हटाने की मांग

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरघची ने इसे लेबनान युद्धविराम का उल्लंघन बताया

एजेंसी (हि.स.)
तेहरान

वैश्विक ऊर्जा बाजार में एक बार फिर हलचल मच गई है। ईरान ने शुक्रवार को अमेरिका को सीधी चेतावनी देते हुए कहा है कि वह होर्मुज जलडमरूमध्य में अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी को तत्काल हटाए। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरघची ने इसे लेबनान युद्धविराम का सीधा उल्लंघन करार दिया है। तेहरान ने स्पष्ट किया है कि यदि अमेरिकी नौसेना अपनी नाकेबंदी जारी रखती है, तो ईरान इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को दोबारा बंद करने के लिए मजबूर होगा।

यह घटनाक्रम लेबनान में लागू युद्धविराम के बीच उपजा है। ईरान ने पहले घोषणा की थी कि युद्धविराम की अवधि के दौरान यह जलडमरूमध्य वाणिज्यिक जहाजों के लिए खुला रहेगा, लेकिन अमेरिकी नौसैनिक गतिविधियों को देखते हुए ईरान का रुख कड़ा हो गया है। ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (कम्ब्कड़) से संबद्ध 'फार्स न्यूज' के अनुसार, ईरान इस नाकेबंदी को न केवल उकसावा, बल्कि युद्धविराम की शर्तों का उल्लंघन मानता है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरघची ने 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) पर एक संदेश के माध्यम से स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने बताया कि लेबनान में युद्धविराम के मद्देनजर ईरान के 'बंदरगाह और समुद्री संगठन' द्वारा समन्वित मार्गों पर वाणिज्यिक जहाजों की आवाजाही को मंजूरी दी गई है। हालांकि, यह मंजूरी कुछ कठोर शर्तों के साथ आई है- केवल वाणिज्यिक जहाजः जलडमरूमध्य का उपयोग केवल उन जहाजों द्वारा किया जा सकता है जो विशुद्ध रूप से वाणिज्यिक (व्यापारिक) प्रकृति के हैं। सैन्य जहाजों का इस जलमार्ग से गुजरना पूरी तरह प्रतिबंधित है। शत्रुतापूर्ण संबंधों पर रोकः ऐसे किसी भी जहाज या उनके कार्गो (माल) को गुजरने की अनुमति नहीं होगी, जिनका संबंध ईरान द्वारा चिह्नित 'शत्रु देशों' से हो। निर्धारित मार्ग का पालनः जहाजों को अनिवार्य रूप से ईरान द्वारा निर्धारित समुद्री गलियारों से ही गुजरना होगा। आवागमन का समन्वय ईरान के समुद्री सुरक्षा बलों के साथ करना आवश्यक है, ताकि किसी भी अनहोनी या सैन्य गलतफहमी से बचा जा सके।

शर्तें लागू: ईरान ने आवागमन के लिए जारी की गाइडलाइंस

ईरान का तर्क है कि वह केवल अपनी समुद्री सीमाओं की रक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है, जबकि अमेरिका की मौजूदगी इस नाजुक स्थिति में तनाव बढ़ा रही है।

होर्मुज जलडमरूमध्य का बंद होना या वहां तनाव बढ़ना न केवल खाड़ी देशों के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा आर्थिक संकट बन सकता है। यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण 'चौक पॉइंट्स' में से एक है। आंकड़ों के अनुसार, वैश्विक स्तर पर समुद्री मार्ग से होने वाली तेल आपूर्ति का लगभग 20 से 30 प्रतिशत हिस्सा इसी संकीर्ण रास्ते से गुजरता है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात जैसे प्रमुख तेल निर्यातक देशों का कच्चा तेल इसी जलडमरूमध्य से होकर दुनिया के बाजारों तक पहुँचता है। ऐतिहासिक रूप से भी यह क्षेत्र तनाव का केंद्र रहा है। पिछले दशकों में, जब भी ईरान और पश्चिम (विशेषकर अमेरिका) के बीच तनाव बढ़ा है, ईरान ने होर्मुज को बंद करने की धमकी दी है। 1980 के दशक के 'टैंकर युद्ध' से लेकर हाल के वर्षों में ईरान द्वारा तेल टैंकरों को जब्त करने की घटनाओं तक, यह जलडमरूमध्य भू-राजनीतिक खींचतान का एक प्रमुख अखाड़ा रहा है।

वर्तमान में, लेबनान में युद्धविराम की नाजुक स्थिति के बीच, यह समुद्री मार्ग एक कूटनीतिक सौदेबाजी का हिस्सा बन गया है। ईरान का यह कदम अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए एक संदेश है कि वह अपनी शर्तों पर क्षेत्रीय सुरक्षा को नियंत्रित करना चाहता है। अमेरिका, जो 'फिफ्थ फ्लीट' के माध्यम से खाड़ी क्षेत्र में अपनी बड़ी नौसैनिक उपस्थिति बनाए रखता है, का कहना है कि उसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय समुद्री आवागमन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है।

अमेरिका की तर्ज पर चीन ने नेपाल के जेन-जी के लिए नए कार्यक्रम की घोषणा की

एजेंसी (हि.स.)
काठमांडू

नेपाल स्थित चीनी दूतावास ने नेपाल के जेन-जी युवाओं को लक्षित करते हुए एक युवा नेतृत्व कार्यक्रम संचालित करने की घोषणा की है। अमेरिकी दूतावास के द्वारा संचालित यूथ काउंसिल ऑफ अमेरिका कार्यक्रम के तर्ज पर ही चीनी दूतावास ने जेन-जी लक्षित इस कार्यक्रम की घोषणा की है। चीनी दूतावास के तरफ से आज नेपाल के सभी अखबारों के प्रथम पृष्ठ पर एक विज्ञापन देते हुए चाइनीज एम्बेसी यूथ पायोनियर प्रोग्राम (सी.एन.वाई.पी.) नामक कार्यक्रम की घोषणा की है। इसमें बताया गया है कि इस पहल का उद्देश्य नेतृत्व विकास, सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन में युवाओं की भूमिका का विस्तार तथा चीनझ्ननेपाल के बीच आपसी समझ और सहयोग को मजबूत करना है।

काठमांडू स्थित चीनी दूतावास के शनिवार कए एक बयान के अनुसार, इस कार्यक्रम के तहत प्रतिभागियों को नेतृत्व प्रशिक्षण, नीतिगत एवं सामाजिक मुद्दों पर चर्चा, कार्यशालाओं और अध्ययन भ्रमण में भाग लेने का अवसर दिया जाएगा। साथ ही चयनित युवाओं को चीन यात्रा का अवसर भी प्रदान किया जाएगा। दूतावास ने बताया कि इस कार्यक्रम का लक्ष्य नेपाल में परिवर्तनकारी सोच रखने वाले युवाओं का एक नेटवर्क तैयार करना है। प्रतिभागियों को विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों, कूटनीतिज्ञों और उद्यमियों के साथ संवाद का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आयु सीमा 22 से 34 वर्ष निर्धारित की गई है। इच्छुक युवा पेशेवर, सामाजिक कार्यकर्ता तथा विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं। दूतावास ने आवेदन पत्र अंग्रेजी में भरकर ईमेल cnypnepal@163.com पर भेजने को कहा है। आवेदन की अंतिम तिथि 17 मई 2026 निर्धारित की गई है। दूतावास के अनुसार आवेदन पत्रों का मूल्यांकन कार्यक्रम के उद्देश्यों के अनुरूप किया जाएगा और अंततः 10 से 20 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। चयनित प्रतिभागी एक वर्ष तक विभिन्न प्रशिक्षण, गतिविधियों और नेटवर्किंग कार्यक्रमों में शामिल रहेंगे। कार्यक्रम पूर्ण होने के बाद वे पूर्व प्रतिभागी नेटवर्क (एलुमनाइ) से जुड़ेंगे, जो निरंतर अवसर और सहयोग के मंच उपलब्ध कराएगा। काठमांडू स्थित दूतावास ने बताया कि यह कार्यक्रम प्रतिभागियों को समुदाय-आधारित परियोजनाओं के संचालन के लिए प्रोत्साहित करेगा। दूतावास को उम्मीद है कि यह पहल नेपाल के युवाओं में नेतृत्व क्षमता विकसित करने के साथ-साथ सतत सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान देगी। उल्लेखनीय है कि अमेरिका भी नेपाली युवाओं को लक्षित कर ऐसे कार्यक्रम संचालित करता रहा है। अमेरिकी यूथ काउंसिल के नाम से चल रहे इस संस्था के बारे में आम लोगों और अंतरराष्ट्रीय मीडिया को उस समय जानकारी हुई जब नेपाल में जेन-जी आंदोलन से जुड़े सभी बड़े नाम और नेतृत्वकर्ता अमेरिकी यूथ काउंसिल से उनकी आबाद्धता का पता चला। इतना ही नहीं नेपाल में सुशीला कार्की के नेतृत्व में बनी अंतरिम सरकार के अधिकांश मंत्री अमेरिकी यूथ काउंसिल से ही जुड़े दिखाई दिए।

गोली उपहार मामले में एपीबीएन जवान गिरफ्तार

फोटोः हि.स.

एजेंसी (हि.स.)
इटानगर

अरुणाचल प्रदेश की राजधानी इटानगर में पुलिस ने एक एपीबीएन (अरुणाचल आर्म्ड पुलिस बटालियन) के जवान को कथित तौर पर 9 एमएम की जिंदा गोली उपहार में देने के मामले में एफआईआर दर्ज होने के कुछ ही घंटों के भीतर गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस के अनुसार, यह मामला उस समय सामने आया जब एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें एक व्यक्ति एंटी-ड्रग्स वॉरियर एनजीओ के सदस्य गुमिन मिजे को जिंदा गोली देते हुए दिखाई दिया। वीडियो के प्रसार के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया और पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू की। शिकायत मिलने के बाद एसडीपीओ इटानगर चेड़ा साबन के नेतृत्व में, चिम्पू थाना प्रभारी निरीक्षक एन निशांत और उपनिरीक्षक संजीत झा की टीम ने संयुक्त अभियान चलाकर आरोपित की पहचान और गिरफ्तारी के लिए प्रयास तेज कर दिए। तकनीकी निगरानी और फील्ड स्तर पर समन्वय के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज होने के चार घंटे के भीतर ही आरोपित को पकड़ लिया। यह पूरी कार्रवाई इटानगर कैपिटल रीजन के पुलिस अधीक्षक जुम्मर बसर के पर्यवेक्षण में की गई। गिरफ्तार आरोपित की पहचान एपीबीएन के कॉन्स्टेबल नगेलोंग नगेमू के रूप में हुई है।

बिहार के दोनों डिप्टी सीएम को 'Z' श्रेणी की सुरक्षा, गृह विभाग ने जारी किया आदेश

सुपौल। बिहार सरकार ने राज्य के विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। गृह विभाग (विशेष शाखा) की ओर से जारी आदेश के अनुसार बिहार के दोनों उपमुख्यमंत्री को 'Z' श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। गृह विभाग के संयुक्त सचिव नवीन चंद्र द्वारा 17 अप्रैल को जारी पत्र के अनुसार राज्य सुरक्षा समिति की बैठक में की गई अनुशंसाओं के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। जारी आदेश के मुताबिक उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और उपमुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव को 'Z' श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इस संबंध में पुलिस महानिदेशक और विशेष शाखा को निर्देश दिया गया है कि राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में दोनों उपमुख्यमंत्रियों को निर्धारित सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। गृह विभाग ने आदेश की प्रतिलिपि पुलिस महानिरीक्षक (सुरक्षा), सहायक निदेशक आसूचना ब्यूरो और विभागीय आईटी प्रबंधक को भी भेजते हुए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है।

अमेरिका के सहायक विदेश मंत्री 20-22 अप्रैल तक नेपाल दौरे पर

एजेंसी (हि.स.)
काठमांडू

दक्षिण एवं मध्य एशिया मामलों को देखने वाले अमेरिका के सहायक विदेश मंत्री समीर पॉल कपूर सोमवार २० अप्रैल से २२ अप्रैल तक नेपाल का दौरा करने वाले हैं। बालेन्द्र शाह के नेतृत्व में सरकार गठन के बाद नेपाल आने वाले वे अमेरिकी सरकार के सबसे वरिष्ठ अधिकारियों होंगे। आमतौर पर अमेरिकी विदेश मंत्री या अन्य उच्च अधिकारी भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश या दक्षिण एवं दक्षिण-पूर्व एशिया के अन्य देशों की यात्रा के दौरान ही काठमांडू आते रहे हैं।

सहायक विदेश मंत्री पॉल अमेरिका से उड़ान भरकर इस्तांबुल ट्रांजिट होते हुए सीधे काठमांडू पहुंचेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार, उनके सोमवार को आने और बुधवार को लौटने का कार्यक्रम है। काठमांडू में रहते हुए वे

बालेन्द्र सरकार की आर्थिक प्राथमिकताओं पर वित्त मंत्री डॉ. स्वर्णिम वाग्ले के साथ चर्चा करेंगे। मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन (एमसीसी) के नेपाल कॉम्पैक्ट के शीघ्र कार्यान्वयन में अमेरिका की रुचि बनी हुई है। नेपाल के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि काठमांडू प्रवास के दौरान सहायक विदेश मंत्री कपूर नेपाल के वित्त मंत्री और विदेश मंत्री के अलावा और किन-किन लोगों से मिलेंगे, किस समय और किन विषयों पर वार्ता करेंगे- इसकी विस्तृत कार्यसूची तैयार की जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अक्टूबर 2025 में दक्षिण एवं मध्य एशिया मामलों के सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू को पद से हटा दिया था। उनकी जगह सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ कपूर को नियुक्त किया गया था। भारत की राजधानी नई दिल्ली में जन्मे कपूर दक्षिण एशिया के मुद्दों की जमीनी वास्तविकताओं को अच्छी तरह समझने और उनका विश्लेषण करने की क्षमता रखते हैं। विदेश मंत्रालय में नियुक्ति से पहले वे अमेरिकी नौसेना के नेवी पोस्ट ग्रेजुएट स्कूल में प्रोफेसर थे, जहां वे सैन्य संचालन, तकनीकी नेतृत्व और युद्ध कौशल जैसे विषय पढ़ाते थे।

नेपाल में नई सरकार बनने के बाद किसी वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी का सीधे काठमांडू आना इस बात का संकेत है कि वाशिंगटन डीसी की प्राथमिकताओं में नेपाल महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

संक्षिप्त-समाचार

आरटीई : निजी विद्यालयों में प्रवेश के लिए 354 सीटें आवंटित

धमतरी। धमतरी जिले के 214 निजी स्कूलों में आरटीई के तहत सत्र 2026-27 के लिए पहले चरण की सीटों का आवंटन 15 अप्रैल को लाटरी पद्धति से किया गया। रिक्त 450 सीटों में से 354 सीटें छात्रों को आवंटित हुई हैं। इन आवंटित सीटों पर अब प्रवेश की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सत्र 2026-27 में आरटीई के तहत प्रवेश प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। इस बार नर्सरी और केजी वन की सीटों में प्रवेश नहीं होगा बल्कि बच्चों को सीधे कक्षा पहली में प्रवेश दिया जाएगा। नियमों में बदलाव के कारण प्रवेश को लेकर प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। जिले में संचालित 214 निजी स्कूलों में कक्षा पहली में प्रवेश के लिए आरटीई के तहत प्रक्रिया जारी है। बुधवार को रिक्त कुल 450 सीटों के लिए लाटरी पद्धति से 354 सीटें आवंटित की गई हैं। पहले चरण में प्रवेश के लिए 31 मार्च तक कुल 1235 आनलाइन आवेदन प्राप्त हुए थे। दस्तावेजों की जांच के बाद 45 नोडल अधिकारियों द्वारा 843 आवेदनों को पूर्ण रूप से स्वीकृत किया गया। इनमें से 354 छात्रों को सीट आवंटित की गई है। सीट आवंटन के बाद अब एक से 30 मई के बीच चयनित छात्र निर्धारित स्कूलों में प्रवेश लेंगे।पिछले सत्र 2025-26 में जिले के 197 निजी स्कूलों में नर्सरी, केजी वन और कक्षा पहली के लिए निर्धारित कुल 1092 सीटों में प्रवेश की प्रक्रिया की गई थी। जिसमें लाटरी पद्धति से चयनित होकर 1018 सीटों में छात्रों ने प्रवेश लिया था। पिछले साल की तुलना में इस साल सीटें घटकर 450 हो गई। वहीं प्रवेश लेने वाले स्कूलों की संख्या 214 हो गई हैं।

कुएं में डूबने से दो बच्चियों की मौत

गिरिडीह। जिले के सरिया थाना क्षेत्र में एक हादसे में कुएं में डूबने से दो नाबालिग बच्चियों की मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची । घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई है। घटना के बाद शनिवार स्थानीय लोगों के प्रयास से दोनों को कुएं से बाहर निकाला गया।जब तक दोनों को कुएं से बाहर निकाला दोनों की मौत हो चुकी थी। घटना सरिया थाना क्षेत्र के लालोकोनी गांव की है। मृतकों की पहचान नगमा खातुन और साहिन प्रवीण के रूप में हुई है । बताया जा रहा कि दोनों शुकवार रात शौच के लिए गई थी । वापस नही लौटने पर लोगों ने खोज बीन की। इस दौरान शनिवार को दोनों के शव कुएं मे तैरते मिले। फिलहाल घटना का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है । घटना को लेकर थाना प्रभारी पिंकू कुमार का कहना है कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है । पुलिस ने दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया है । इधर घटना के बाद परिजनों का रो रोकर बुरा हाल हो गया है। गांव में भी शोक की लहर है। जिप सदस्य अनुप कुमार पांडेय ने कहा कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस को सूचना दी गई। जिसके बाद पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

मणिपुर-म्यांमार सीमा के पास केवाईकेएल उग्रवादी गिरफ्तार, नकदी और मोबाइल बरामद

तेंगनौपाल (मणिपुर)। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने शुक्रवार को एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन केवाईकेएल (सोरेपा) के एक सक्रिय सदस्य को भारत-म्यांमार सीमा के पास गिरफ्तार किया। गिरफ्तार उग्रवादी की पहचान फांजौबाम मुहिंद्रो के रूप में हुई है, जो इम्फाल पूर्व जिले के एंड्रो नंबर-3, खुमान लैकाई का निवासी है। उसे तेंगनौपाल जिले के मोरेह थाना क्षेत्र अंतर्गत भारत-म्यांमार फ्रेंडशिप ब्रिज के पास बॉर्डर पिलर 76 और 77 के बीच स्थित इलाके से गिरफ्तार किया गया। सुरक्षा बलों ने उसके पास से दो मोबाइल फोन और 20,500 क्यात (म्यांमार की मुद्रा) बरामद किए हैं। ज्ञात हो कि सुरक्षा बलों ने गुरुवार को भी इस इलाके में क्यात (म्यांमार की मुद्रा) बरामद किए थे। गिरफ्तार उग्रवादी और जब्त सामग्री को आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को सौंप दिया गया है।

मयूरभंज में उबालः छात्रा की संदिग्ध मौत के बाद बीजद का 12 घंटे का 'जिला बंद'

भुवनेश्वर। मयुरभंज जिले में एक आश्रम स्कूल की छात्रा की कथित खाद्य विषाक्तता से हुई मौत के विरोध में बीजू जनता दल ने 12 घंटों का मयुरभंज जिला बंद का आह्वान किया है। सुबह 6 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलने वाला यह बंद के जिले में जनजीवन को प्रभावित हुआ है। बीजद समर्थकों ने विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शन करते हुए प्रमुख सड़कों, राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों को अवरुद्ध किया और कई जगहों पर टायर जलाकर विरोध जताया। उल्लेखनीय है कि जिले के रासगोबिंदपुर आश्रम स्कूल की कक्षा 5 की छात्रा रूपाली बेशरा की मौत के विरोध में जिला-बंद का आह्वान किया गया है। छात्रा की मृत्यु कथित रूप से स्कूल के छात्रावास में परोसे गए दूषित या बासी भोजन के सेवन के बाद हुई। उसी भोजन को खाने के बाद 146 से अधिक छात्र उल्टी और दस्त जैसी शिकायतों के साथ बीमार पड़ गए। बीजद नेताओं ने इस घटना को गंभीर लापरवाही करार देते हुए स्कूल प्रशासन और राज्य सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। पार्टी ने मृत छात्रा के लिए न्याय और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बीजद जिला अध्यक्ष सुदाम मरांडी के नेतृत्व में चल रहे इस विरोध प्रदर्शन में बीजद के युवा, छात्र और अन्य संगठनात्मक इकाइयों के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हैं। बंद का असर जिले के सभी चार सबडिविजन बारिपदा, कप्तिपदा बामनघाटी और पांचपीढ–में देखा जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने विरोध के तहत कुछ समय के लिए बेतनोती स्टेशन के पास बांगिरीपोसी-पुरी सुपरफास्ट ट्रेन को भी रोक दिया। हालांकि, आवश्यक सेवाओं को बंद से बाहर रखा गया है। एंबुलेंस और आपातकालीन वाहनों की आवाजाही जारी है, जबकि जरूरी दुकानें खुली हुई हैं। खबर लिखे जाने तक बंद शांतिपूर्ण तरीके से जारी है और किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है।

राजस्थान में फिर बढ़ेगी गर्मी, पारा चढ़ने के आसार

जयपुर। राजस्थान में मौसम के उतार-चढ़ाव के बीच अब एक बार फिर गर्मी तेज होने के संकेत हैं। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार आगामी दिनों में तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, जिससे प्रदेश में गर्मी का असर और तेज होगा। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से शुक्रवार को कई जिलों में मौसम ने अचानक करवट ली। चूरू में जहां अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस रहा, वहीं बाड़मेर, जैसलमेर और पाली समेत कुछ शहरों में तापमान में गिरावट देखने को मिली। पिछले 24 घंटों में हनुमानगढ़ और चूरू जिलों में सुबह से बादल छाए रहे और दोपहर बाद आंधी के साथ बारिश व ओलावृष्टि हुई।

काकोपथार में भीषण सड़क हादसे में दो युवकों की मौत, कड़ी सजा की मांग

एजेंसी (हि.स.)
तिनसुकिया (असम)

ऊपरी असम के तिनसुकिया जिलांतर्गत काकोपथार इलाके के लाजुम गांव में बीती देर रात हुए एक सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई। इस घटना के बाद शनिवार की सुबह से भारी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया और प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग-15 को जाम कर दिया, जिससे हजारों गाड़ियां फंस गईं।

मृतकों की पहचान काकोपाथर के निवासी एवं काकोपाथर फुटबॉल कोचिंग सेंटर में गोलकीपर के तौर पर काम करने वाले प्रणजीत दास और तेजी गांव के शशांक मोरान के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय लोगों के अनुसार, यह घटना शुक्रवार देर रात बिहू उत्सव के दौरान हुई। बताया जा रहा है कि एक तेज रफ्तार बोलेरो गाड़ी ने सड़क किनारे खड़ी एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। टक्कर के समय दोनों

फोटोः हि.स.

युवक कथित तौर पर मोटरसाइकिल पर ही बैठे थे। दोनों युवकों को गंभीर चोटें आईं और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहां मौजूद लोगों और स्थानीय निवासियों ने उन्हें तुरंत पास के एक अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि बोलेरो गाड़ी (रजिस्ट्रेशन नंबर एएस-01वी-0399) काकोपाथर की तरफ से आ रही थी, तभी उसने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। दुमदुमा पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। हादसे में शामिल गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया है। इस घटना से स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा फैल गया। शनिवार सुबह उन्होंने काकोपाथर पुलिस स्टेशन के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-15 को जाम कर-के विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर टायर जलाए और मृतकों के परिवारों के लिए तत्काल न्याय, साथ ही उचित मुआवजा और पुनर्वास उपायों की मांग की। स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों से अपील की गई है कि वे प्रदर्शनकारियों की शिकायतों को दूर करने और यातायात व्यवस्था को सामान्य बनाने के लिए तत्काल हस्तक्षेप करें। इस मामले में अभी और जानकारी का इंतजार है।

दरभंगा के होटल में सुपौल के कारोबारी की संदिग्ध मौत, बाथरूम में मिला शव

सुपौल। बिहार के दरभंगा में एक कारोबारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र की है, जहां रेलवे स्टेशन के पास स्थित एक होटल के कमरे से उसका शव बरामद किया गया। मृतक सुपौल जिले के गुदरी बाजार निवासी संजय प्रसाद अग्रवाल (35) के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार संजय प्रसाद अग्रवाल 15 अप्रैल से नारायण होटल में ठहरे हुए थे। इस दौरान उन्हें कमरे से बाहर आते-जाते किसी ने नहीं देखा। शुक्रवार की शाम कमरे से तेज दुर्गंध आने पर होटल कर्मियों को शक हुआ, जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके बाद दरवाजा तोड़कर पुलिस अंदर दाखिल हुई। जांच के दौरान बाथरूम में संजय प्रसाद का शव पड़ा मिला। होटल के एंट्री रजिस्टर और उनके पहचान पत्र के आधार पर शव की पहचान की गई, जिसके बाद परिजनों को सूचना दी गई। मामले को लेकर थानाध्यक्ष सुधीर कुमार ने बताया कि जांच के लिए एसएफएल (फॉरेंसिक) टीम को बुलाया गया है। घटनास्थल की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई गई है।

लखीपथार में अवैध शिकारियों ने काटे जिंदा पालतू हाथी के दोनों दांत

एजेंसी (हि.स.)
तिनसुकिया (असम)

राज्यभर में रंगाली बिहू के उल्लासपूर्ण माहौल के बीच तिनसुकिया के लखीपथार वनक्षेत्र में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई हुई। अवैध शिकारियों ने एक जिंदा पालतू हाथी के दोनों दांत काट लिए। इस घटना को लेकर इलाके में भारी रोष व्याप्त है।

घटना के संबंध में हाथी के महावत के अनुसार, मार्घेरिटा के सोनजॉय दोवानिया नामक व्यक्ति के स्वामित्व वाले मंगल सिंह नामक हाथी को चराने के लिए वन विभाग को सूचित करते हुए लखीपथार वनक्षेत्र में रखा गया था। अन्य दिनों की तरह बीते 14 अप्रैल की शाम को भी हाथी को निर्दिष्ट स्थान पर बांधकर महावत अपने घर चला गया। अगले दिन यानी 15 अप्रैल की सुबह बांधे गये स्थान पर जब हाथी नहीं देखा गया, तो इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई गई। महावत के अनुसार हाथी पहले कई बार अपने बंधन को छुड़ाकर आसपास के

इलाकों में घूमने चला जाता था, इसी आशंका के मद्देनजर उसकी आसपास के क्षेत्रों में काफी समय तक खोजबीन किया गया। लंबे समय के बाद अत्यंत कमजोर स्थिति में जंगल के बीचों-बीच हाथी को पाया गया, हाथी के दोनों दांत काट लिये गये थे, जिसके चलते हाथी बेहद दर्द की स्थिति में था। इस बीच, घटना के संबंध में वन विभाग के लोगों को जानकारी देकर हाथी का इलाज शुरू किया गया है। दुष्कर्मी ने निर्दयता से जीवित हाथी के दोनों दांत काटने के कृत्य की सभी ने निंदा की है। प्रकृति प्रेमियों ने कहा है कि इसे मानवता का पतन कहा जा सकता है। पुलिस सूत्रों ने आज बताया है कि वन विभाग एवं पुलिस घटना को अंजाम देने वाले अवैध शिकारियों की तलाश में जुटी हुई है।

सुपौल में बच्ची की मौत, परिजनों में आक्रोश

एजेंसी (हि.स.)
सुपौल

जिले के भपटियाही थाना क्षेत्र अंतर्गत पिपराखुर्द चौक पर एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां झोलाछाप डॉक्टर द्वारा लगाए गए इंजेक्शन के बाद 10 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। मिली जानकारी के अनुसार, पिपराखुर्द वार्ड संख्या 6 निवासी सिताराम शर्मा की नातिन शिवानी कुमारी को तेज बुखार था। परिजन उसे इलाज के लिए गांव के चौक स्थित एक मेडिकल दुकान पर ले गए। दुकान संचालक विद्यानंद मंडल, जो स्वयं को ग्रामीण चिकित्सक बताते हैं, ने बच्ची को इंजेक्शन लगाया। उस समय बच्ची का तापमान करीब 102 डिग्री बताया जा रहा है। परिजनों के अनुसार, देर शाम करीब आठ बजे इंजेक्शन लगवाकर वे बच्ची को घर ले आए। लेकिन करीब 20 मिनट के भीतर ही उसकी हालत अचानक बिगड़ने लगी। बच्ची के हाथ-पैर सिकुड़ने लगे और वह अचेत होने लगी। स्थिति गंभीर देख परिजन घबराकर उसे दोबारा उसी डॉक्टर के

पास लेकर पहुंचे, जहां से उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाने की सलाह दी गई। इसके बाद परिजन बच्ची को राघोपुर रेफरल अस्पताल ले जाने लगे, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। राघोपुर रेफरल अस्पताल पहुंचने पर ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉ. अंजार अहमद ने जांच के बाद बच्ची को मृत घोषित कर दिया। मृतका के मामा रंजीत कुमार ने आरोप लगाया कि उनकी भांजी की मौत झोलाछाप डॉक्टर द्वारा लगाए गए गलत इंजेक्शन के कारण हुई है। उन्होंने कहा कि इंजेक्शन लगते ही बच्ची की हालत बिगड़ गई थी, जो स्पष्ट रूप से लापरवाही का मामला है। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि बिना वैध डिग्री के ग्रामीण क्षेत्रों में इलाज कर रहे ऐसे लोगों पर प्रशासन की लापरवाही के कारण ही इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं।

बेंगलुरु में गूंजी दहाड़ | दक्षिण अफ्रीका से आए चार दुर्लभ चीतों का स्वागत

बैनरघट्टा उद्यान में शुरू हुआ 'मिशन कंजर्वेशन'

एजेंसी (हि.स.)
बेंगलुरु

दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चार दुर्लभ चीतों का बेंगलुरु पहुंचने पर वन मंत्री ईश्वर खंड्रे ने देर रात केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के कार्गो विभाग में औपचारिक स्वागत किया। इन चीतों को विशेष व्यवस्था के तहत बैनरघट्टा जैविक उद्यान लाया जा रहा है, जहां इन्हें संरक्षित वातावरण में रखा जाएगा।

मंत्री ईश्वर खंड्रे कलबुर्गी का कार्यक्रम समाप्त करने के बाद हैदराबाद होते हुए बेंगलुरु पहुंचे और सीधे हवाई अड्डे के कार्गो टर्मिनल पहुंचे। यहां उन्होंने अधिकारियों के साथ मिलकर चीतों के आगमन और उनकी सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि इन विदेशी मेहमानों को नए मौसम और वातावरण में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए विशेष निगरानी, अनुकूल तापमान व्यवस्था

फोटोः हि.स.

और सुरक्षित आवास सुनिश्चित करने को कहा गया है। साथ ही, पशु चिकित्सकों को 30 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन, नियमित स्वास्थ्य जांच और क्वारंटाइन प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए।

मंत्री ने चीतों को हवाई अड्डे से बैनरघट्टा जैविक उद्यान तक सुरक्षित रूप से पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया का भी बारीकी से निरीक्षण किया और सुरक्षा में किसी भी प्रकार की चूक न होने की हिदायत दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि एक समय कर्नाटक के जंगलों में चीते पाए जाते थे, लेकिन अब वे पूरी तरह लुप्त हो चुके हैं। ऐसे में इन दुर्लभ वन्यजीवों को चिड़ियाघरों में लाकर आम जनता को उन्हें देखने और उनके संरक्षण के प्रति जागरूक करने का अवसर मिलेगा। अंत में मंत्री ने कर्नाटक चिड़ियाघर प्राधिकरण के अधिकारियों को निर्देश दिया कि चीतों की सुरक्षा, देखभाल और संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए, ताकि वे स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण में रह सकें।

प्रीमियर लीग में 25 साल बाद लौटा कोवेंट्री सिटी ब्लैकबर्न से ड्रॉ के साथ किया प्रमोशन पक्का

कोवेंट्री सिटी ने 43 मैचों में 86 अंक हासिल कर तालिका में शीर्ष स्थान हसिल किया

एजेंसी (हि.स.)
ब्लैकबर्न

कोवेंट्री सिटी ने 25 साल बाद प्रीमियर लीग में वापसी कर इतिहास रच दिया। टीम ने ब्लैकबर्न रोवर्स के खिलाफ शुक्रवार रात 1-1 से ड्रॉ खेलते हुए चैंपियनशिप से प्रमोशन सुनिश्चित कर लिया।

कोवेंट्री सिटी को प्रमोशन पक्का करने के लिए सिर्फ एक अंक की जरूरत थी, जिसे टीम ने हासिल कर लिया। मैच में ब्लैकबर्न ने दूसरे हाफ की शुरूआत में रयोया मोरिशिता के गोल से बढ़त बनाई, लेकिन अंत में बॉबी थॉमस ने हेडर से बराबरी का गोल कर टीम को जरूरी अंक दिला दिया। इस ड्रॉ के साथ कोवेंट्री सिटी ने 43 मैचों में 86 अंक हासिल कर तालिका में शीर्ष स्थान मजबूत किया। तीसरे स्थान पर मौजूद मिलवॉल उससे 13 अंक पीछे है और अब उसे पकड़ नहीं सकता।

फोटोः हि.स.

टीम के कोच फ्रैंक लैम्पार्ड ने स्काई स्पोर्ट्स से इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर करते हुए कहा, यह एक अविश्वसनीय पल है। हमें पता था कि हम करीब हैं, लेकिन 25 साल बाद इसे हासिल करना शानदार है। यह क्लब और इसके प्रशंसकों के लिए बहुत मायने रखता है। लैम्पार्ड के कोचिंग करियर में यह पहला प्रमोशन है। उन्होंने कहा कि यह अहम मानी जा रही है। चैंपियनशिप से प्रीमियर लीग में पहुंचने पर क्लब को प्रसारण और अन्य स्रोतों से लगभग 120 से 170 मिलियन पाउंड तक की आय होने की उम्मीद है। गौरतलब है कि कोवेंट्री सिटी ने 1967 में प्रमोशन के बाद लगातार 34 सीजन इंग्लैंड की शीर्ष लीग में बिताए थे, लेकिन 2000-01 सीजन में टीम को बाहर होना पड़ा। इसके बाद क्लब को आर्थिक और प्रदर्शन दोनों स्तरों पर कठिन दौर से गुजरना पड़ा। 2012 में टीम तीसरे डिवीजन में पहुंच गई और 2017 में चौथे डिवीजन तक गिर गई थी। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में टीम ने शानदार वापसी की और अब एक उपलब्धि उनके करियर की सबसे खास उपलब्धियों में से एक है। कोवेंट्री सिटी के लिए यह सफलता सिर्फ खेल तक सीमित नहीं है, बल्कि आर्थिक रूप से भी बेहद बार फिर इंग्लैंड के शीर्ष फुटबॉल स्तर पर पहुंच गई है। कोवेंट्री सिटी की यह वापसी क्लब और उसके प्रशंसकों के लिए ऐतिहासिक और भावनात्मक पल साबित हुई है।

व्यक्तिगत प्रदर्शन से ऊपर टीम की जीतः शुभमन गिल की नजरें अब आईपीएल खिताब पर

एजेंसी (हि.स.)
अहमदाबाद

फोटोः हि.स.

नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शुक्रवार को खेले गए आईपीएल 2026 के एक रोमांचक मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ पांच विकेट से महत्वपूर्ण जीत दर्ज की। गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि क्यों उन्हें आधुनिक क्रिकेट का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज माना जाता है। 181 रनों के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करते हुए, गिल ने 50 गेंदों में 86 रनों की शानदार पारी खेलकर न केवल अपनी टीम को जीत दिलाई, बल्कि अंक तालिका में भी टीम की स्थिति को मजबूत किया।

मैच के दौरान गिल ने अपनी तकनीक और सूझबूझ का बेहतरीन प्रदर्शन किया। उन्होंने पारी की शुरूआत से ही केकेआर के गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा। गिल की इस पारी में 8 चौके और 4 छक्के शामिल थे, जिसने गुजरात के समर्थकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस जीत के साथ गुजरात टाइटंस अब अंक तालिका में शीर्ष चार की दौड़ में मजबूती से शामिल हो गई है, जबकि केकेआर की लगातार हार का सिलसिला जारी है। पुरस्कार समारोह के दौरान जब गिल से उनकी शानदार फॉर्म और 2023 के सत्र जैसी बल्लेबाजी के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बहुत ही विनम्रता के साथ अपना दृष्टिकोण साझा किया। गिल ने कहा, ईमानदारी से कहूं तो मुझे नहीं लगता कि व्यक्तिगत स्कोर या पिछली फॉर्म के आंकड़े मायने रखते हैं। सबसे जरूरी चीज टीम की जीत है। टूर्नामेंट के बीच में व्यक्तिगत उपलब्धियों के बजाय, मेरा अंतिम लक्ष्य फाइनल खेलकर कप जीतना है। गिल ने यह भी स्वीकार किया कि वह अपनी पारी को अंत तक ले जाना चाहते थे और जल्दी आउट होने से थोड़े निराश थे। उनकी यह परिपक्वता दशार्ती है कि एक कप्तान के रूप में वे किस तरह अपनी टीम के प्रति जवाबदेही और जिम्मेदारी समझते हैं। आईपीएल 2026 के मौजूदा सत्र में चार मैचों में 251 रनों के साथ ऑरेंज कैप की रेस में शीर्ष पर पहुंचना उनकी निरंतरता को दशार्ता है, लेकिन गिल के लिए यह केवल शुरूआत है। गुजरात की जीत की नींव उनके गेंदबाजों ने पहले ही डाल दी थी। केकेआर के खिलाफ नई गेंद से कैगिसो रबाडा और मोहम्मद सिराज की जोड़ी ने कहर बरपाया। रबाडा ने 29 रन देकर तीन विकेट लिए, जबकि सिराज ने 23 रन देकर दो महत्वपूर्ण सफलताएं हासिल कीं। इन दोनों गेंदबाजों ने पावरप्ले में ही केकेआर के शीर्ष क्रम को ध्वस्त कर दिया, जिससे मेहमान टीम दबाव में आ गई। गिल ने मैच के बाद अपने गेंदबाजों की रणनीति की खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा, पिच पर गेंद रुक कर आ रही थी और गर्मी का असर भी था। ऐसे में हमने रबाडा और सिराज को अतिरिक्त ओवर देने का फैसला किया, ताकि दबाव बनाया जा सके। बीच के ओवरों में विकेट लेने की हमारी मानसिकता ने ही अंततः मैच का रुख बदला।

आईपीएल 2026 में लगातार हार से निराश केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने कहा-मुश्किल दिनों को अपनाना होगा

एजेंसी (हि.स.)
अहमदाबाद

फोटोः हि.स.

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) की खराब फॉर्म जारी है। टीम अपने शुरूआती छह मुकाबलों में जीत दर्ज नहीं कर सकी है। टीम को शुक्रवार को गुजरात टाइटंस के 180 रन बनाने के बावजूद 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा।

इस बीच कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टीम की स्थिति पर खुलकर बात करते हुए खिलाड़ियों से सकारात्मक बने रहने और कठिन समय को स्वीकार करने की अपील की है। मैच के बाद रहाणे ने कहा कि टीम ने पहले बल्लेबाजी का फैसला इस सोच के साथ लिया था कि बल्लेबाज खुलकर खेल सकें। उन्होंने कहा, हम बतौर बल्लेबाजी टीम इस विकेट पर 200 रन का लक्ष्य सोच रहे थे, जो चुनौतीपूर्ण होता। हालांकि, उन्होंने कैमरन ग्रीन की पारी की जमकर तारीफ की। रहाणे ने कहा, कैमरन ग्रीन ने शानदार बल्लेबाजी की। आप विकेट गंवा सकते हैं, लेकिन हम 180 रन तक पहुंचे, उसमें उनका बड़ा योगदान रहा। लगातार हार के बावजूद रहाणे ने टीम को सकारात्मक रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा, एक खिलाड़ी के रूप में आपको कठिन दिनों को भी अपनाना पड़ता है। सिर ऊंचा रखें, हर दिन अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करें। हमारे लिए जरूरी है कि हम सकारात्मक सोच के साथ मैदान पर उतरें और खुलकर खेलें। गेंदबाजी को लेकर रहाणे ने साफ तौर पर माना कि पावरप्ले में टीम की कमजोरी सामने आई है। उन्होंने कहा, सच यह है कि पावरप्ले में गेंदबाजी करने वाले खिलाड़ी अनुभवहीन हैं। लेकिन वे पूरी कोशिश कर रहे हैं, विकेट लेने की कोशिश कर रहे हैं, भले ही अभी सफलता नहीं मिल रही। उन्होंने अनुकूल रॉय, कार्तिक त्यागी और वैभव अरोड़ा जैसे गेंदबाजों का समर्थन करते हुए कहा कि ये खिलाड़ी लगातार मेहनत कर रहे हैं। रहाणे ने यह भी बताया कि कैमरन ग्रीन गेंदबाजी नहीं कर सके क्योंकि उन्हें ऐंठन (क्रैम्प्स) की समस्या थी। कप्तान ने अंत में कहा, जब आप लगातार हारते हैं तो नकारात्मक सोच आना आसान होता है, लेकिन मैं टीम पर गर्व करता हूं। हमें एक-एक मैच पर ध्यान देना है और हर दिन बेहतर बनने की कोशिश करनी है।

आईपीएल 2026: सनराइजर्स हैदराबाद ने डेविड पेन की जगह जेराल्ड कोएट्जी को टीम में शामिल किया

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

फोटोः हि.स.

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद ने चोटिल डेविड पेन के स्थान पर दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज जेराल्ड कोएट्जी को टीम में शामिल किया है। पेन इस सीजन में दो मैच खेलने के बाद टखने की चोट के कारण पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं।

25 वर्षीय जेराल्ड कोएट्जी इस साल की नीलामी में अनसोल्ड रहे थे, लेकिन अब उन्हें 2 करोड़ रुपये में सनराइजर्स हैदराबाद ने अपनी टीम में जोड़ा है। कोएट्जी इससे पहले आईपीएल में मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के लिए खेल चुके हैं, जहां उन्होंने 14 मैचों में 15 विकेट हासिल किए हैं। कोएट्जी हाल ही में टी20 विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका की टीम का हिस्सा थे, हालांकि उन्हें कोई मैच खेलने का मौका नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज में हिस्सा लिया था। इस बीच, सनराइजर्स हैदराबाद को एक और बड़ी मजबूती कप्तान पैट कमिंस के टीम से जुड़ने से मिली है। कमिंस 17 अप्रैल को टीम के साथ जुड़े और 25 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मुकाबले के लिए उपलब्ध रहेंगे।

फिलहाल सनराइजर्स हैदराबाद अंक तालिका में पांचवें स्थान पर है और आज (18 अप्रैल) चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ अपना अगला मुकाबला खेलेगी।

स्टटगार्ट ओपनः एंड्रीवा ने स्वियातेक को चौंकाया सेमीफाइनल में रयबाकिना से भिड़ंत तय

एजेंसी (हि.स.)
स्टटगार्ट

फोटोः हि.स.

स्टटगार्ट ओपन टेनिस टूर्नामेंट में बड़ा उलटफेर देखने को मिला, जहां रूस की युवा खिलाड़ी मिर्रा एंड्रीवा ने दो बार की चैंपियन इगा स्वियातेक को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। अब उनका सामना शीर्ष वरीय एलेना रयबाकिना से होगा। 18 वर्षीय एंड्रीवा ने शानदार वापसी करते हुए स्वियातेक को 3-6, 6-4, 6-3 से हराया। पहले सेट में पिछड़ने के बाद एंड्रीवा ने जबरदस्त खेल दिखाया और निर्णायक सेट में दो बार सर्विस ब्रेक कर मुकाबला अपने नाम किया।

इससे पहले, शीर्ष वरीय रयबाकिना ने कनाडा की लेयला फर्नांडीज को कड़े मुकाबले में 6-7 (5/7), 6-4, 7-6 (8/6) से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। यह मैच करीब तीन घंटे तक चला, जिसमें रयबाकिना ने अंतिम सेट के टाईब्रेक में दो मैच प्वाइंट बचाकर शानदार जीत दर्ज की। मैच के बाद रयबाकिना ने कहा, शुरूआत में काफी निराशा थी और मेरी सर्विस काम नहीं कर रही थी। लेकिन धीरे-धीरे मैंने खुद को संभाला और लय हासिल की। स्वियातेक, जिन्होंने अपने छह ग्रैंड स्लैम खिताबों में से चार फ्रेंच ओपन की क्ले कोर्ट पर जीते हैं, इस मुकाबले में फेवरेट मानी जा रही थीं, लेकिन एंड्रीवा के आक्रामक खेल के सामने टिक नहीं सकीं। गौरतलब है कि एंड्रीवा ने पहले दौर में गत चैंपियन जेलेना ओस्टापेंको को भी बाहर किया था, जिससे उनका आत्मविश्वास पहले ही बढ़ चुका था।

एंड्रीवा ने मैच के बाद कहा, मैं खुद से कह रही थी कि चाहे जो भी हो, मुझे लड़ते रहना है और विश्वास बनाए रखना है कि मैं किसी भी स्थिति से मैच जीत सकती हूं। अब सेमीफाइनल में एंड्रीवा और रयबाकिना के बीच मुकाबला बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है।

दर्पण विशेष

विश्व यकृत दिवसः जागरूकता ही यकृत संबंधी रोगों का उपचार

हमारे शरीर के सभी अंग अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन आवश्यक अंगों में से, यकृत कई कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह पाचन, चयापचय, हार्मोन उत्पादन और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालकर शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में सहायता करता है। यकृत पाचन, चयापचय, हार्मोन उत्पादन और विषहरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दुनिया भर में यकृत और यकृत से संबंधित बीमारियों के बारे में कई गलत धारणाएं हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में लीवर रोग मृत्यु का 10वां सबसे आम कारण है। यकृत और यकृत से संबंधित बीमारियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस मनाया जाता है।

लिवर हमारे शरीर के लिए बहुत खास

हम जो कुछ भी खाते-पीते हैं, वह लीवर से होकर गुजरता है। इसे स्वस्थ और मजबूत बनाए रखना आवश्यक है। यह हमें कई गंभीर बीमारियों से बचाता है। यह एक ऐसा अंग है, जिसकी यदि उचित देखभाल न की जाए तो वह क्षतिग्रस्त हो सकता है। यकृत न केवल भोजन को पचाने में मदद करता है बल्कि शरीर के कई अन्य कार्यों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यकृत से संबंधित कोई भी समस्या या रोग न केवल पाचन तंत्र को प्रभावित करता है, बल्कि गुर्दे, फेफड़े, हृदय और मस्तिष्क जैसे अन्य महत्वपूर्ण अंगों की कार्यप्रणाली को भी प्रभावित करता है। यह यकृत संक्रमण और रोगों से लड़ने, रक्त शर्करा को नियंत्रित करने, शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने, रक्त के थक्के जमने में सहायता करने और पित्त को कम करने जैसे महत्वपूर्ण कार्य करता है।

फैटी लिवर

लिवर सिरोसिस और लिवर फेलियर मोटापे और फैटी लिवर के कारण हो सकते हैं। ऐसे कई कारक हैं जो मोटापे और फैटी लिवर के जोखिम को बढ़ाते हैं, जिनमें अत्यधिक वजन या मोटापा, टाइप 2 मधुमेह, उच्च रक्तचाप और आनुवंशिक इतिहास शामिल हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के शोध के अनुसार, दुनिया में हर 8 में से एक व्यक्ति मोटापे से ग्रस्त है। मोटापा न केवल लीवर के लिए बल्कि अन्य अंगों के लिए भी खतरनाक है। वर्ष 2019 में, गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) जैसे हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर, तंत्रिका संबंधी विकार, पुरानी श्वसन संबंधी बीमारियां और मोटापे और फैटी लिवर के कारण होने वाले पाचन विकारों के कारण अनुमानित 5 मिलियन मौतें हुईं। मोटापे और फैटी लिवर से होने वाली लिवर की विफलता को रोकने के लिए, स्वस्थ वजन बनाए रखें, मधुमेह और उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करें, संतुलित आहार लें, खूब पानी पिएं, नियमित व्यायाम करें और शराब से बचें।

लक्षण

लिवर से संबंधित बीमारियों के लक्षणों के बारे में लिवर से जुड़ी किसी भी बीमारी का निदान करने के लिए उसके लक्षणों को जानना सबसे जरूरी है। लिवर में कोई समस्या होने पर सबसे आम लक्षण पीलिया होता है, जिससे शरीर पीला दिखाई देने लगता है। इसके अलावा, पैरों या पेट में सूजन (एडिमा), पेट में सूजन, भूख न लगना, मतली या उल्टी, त्वचा पर आसानी से चोट लगना, थकान, या मल और मूत्र के रंग में परिवर्तन ऐसे लक्षण हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। यकृत से संबंधित संक्रमण जैसे हेपेटाइटिस ए, बी या सी, फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, लिवर कैंसर, विल्सन रोग और हेमोक्रोमैटोसिस आमतौर पर यकृत से संबंधित समस्याओं में देखे जाते हैं।

अपने लीवर को जानें

स्वास्थ्य और महत्वपूर्ण अंगों पर विचार करते समय, हृदय, फेफड़े और मस्तिष्क सबसे पहले दिमाग में आते हैं। लीवर को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, भले ही यह शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग है और 500 से अधिक आवश्यक कार्यों के लिए जिम्मेदार है। लीवर पूरे शरीर के लिए फिल्टर का काम करता है। यह हानिकारक पदार्थों को डिटॉक्स करता है और हमारे द्वारा खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों के पोषक तत्वों को तोड़ता है। स्वस्थ लीवर के बिना, विषाक्त पदार्थ जमा हो जाते हैं, पोषक तत्वों का अवशोषण कम हो जाता है और चयापचय कमजोर हो जाता है, जिससे समग्र स्वास्थ्य प्रभावित होता है। तनावग्रस्त या अस्वस्थ लीवर को अपने कार्यभार को यथासंभव कम करने से लाभ होता है। कई अलग-अलग चीजें हैं जो लीवर की बीमारी का कारण बन सकती हैं, जिनमें संक्रमण, आनुवंशिकी और जीवनशैली विकल्प शामिल हैं। आपको किसी भी उम्र में लीवर की समस्या हो सकती है।

स्वस्थ यकृत के लिए सुझाव

फलों और सब्जियों तथा प्रोटीन से भरपूर संतुलित आहार लीवर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है, जबकि अधिक चीनी और अस्वास्थ्यकर वसा लीवर को बीमार बना सकते हैं। शरीर के वजन का मात्र 5-10% कम करने से यकृत की वसा में उल्लेखनीय कमी आ सकती है तथा यकृत की कार्यप्रणाली में सुधार हो सकता है। लीवर में खुद को फिर से बनाने की अनोखी क्षमता होती है, यहाँ तक कि बहुत ज्यादा नुकसान होने के बाद भी। स्वस्थ आदतें अपनाने से, जैसे कि खान-पान में सुधार और व्यायाम को बढ़ाने से लीवर को ठीक होने और फिर से सामान्य रूप से काम करने में मदद मिलती है। यदि वसा लीवर के वजन का 5% से अधिक है, तो यह सूजन, निशान और कैंसर का कारण बन सकता है, साथ ही मेटाबोलिक डिसफंक्शन-एसोसिएटेड स्टेटोटिक लीवर डिजीज मधुमेह, मोटापे और उच्च कोलेस्ट्रॉल से जुड़ा हुआ है। एमएएसएलडी अक्सर अपने शुरूआती चरणों में चुप रहता है। चीनी, परिष्कृत काबोर्हाइड्रेट और ट्रांस/संतृप्त वसा से भरपूर आहार, वसा को संसाधित करने की यकृत की क्षमता को प्रभावित कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप वसा का संचय होता है और यकृत रोग का खतरा बढ़ जाता है। नियमित भोजन समय बनाए रखने से रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद मिलती है और यकृत पर दबाव कम होता है। देर रात को खाना, नाश्ता छोड़ना, दिन में केवल एक बार भोजन करना चयापचय संबंधी विकार विकसित होने के जोखिम को बढ़ा सकता है। खाद्य लेबलिंग सूचित, स्वस्थ विकल्प बनाने के लिए उपयोगी है। खाद्य लेबल पर आम तौर पर सर्विंग साइज, कैलोरी, पोषक तत्व आदि प्रदर्शित होते हैं। इन घटकों को समझने से आहार संबंधी जरूरतों को प्रबंधित करने, अत्यधिक उपभोग से बचने और स्वस्थ विकल्प चुनने में मदद मिलती है।

मिथक बनाम सत्य

मिथकः डिटॉक्स टी या डिटॉक्स जूस पीने से लिवर साफ हो जाता है। **सत्यः** यह एक मार्केटिंग ट्रिक है। लिवर खुद एक डिटॉक्स मशीन है! इसे किसी विशेष जूस की जरूरत नहीं होती। इसे स्वस्थ रखने के लिए सिर्फ संतुलित आहार और पर्याप्त पानी की आवश्यकता है। **मिथकः** दर्द निवारक दवाएं लिवर के लिए सुरक्षित हैं। **सत्यः** दर्द निवारक दवाओं (जैसे पैरासिटामोल) का अत्यधिक या बिना डॉक्टर की सलाह के सेवन लिवर को गंभीर नुकसान पहुँचा सकता है।

लिवर स्वास्थ्य के लिए 3 स्वर्ण नियम

टीकाकरणः हेपेटाइटिस इ का टीका जरूर लगवाएं। यह लिवर कैंसर और सिरोसिस से बचाव का सबसे सस्ता और प्रभावी तरीका है। **नियमित जांचः** यदि आप 40 वर्ष से अधिक हैं, तो साल में एक बार 'लिवर फंक्शन टेस्ट' और अल्ट्रासाउंड जरूर करवाएं। **दवाओं में सावधानीः** किसी भी सप्लीमेंट या दवा को लेने से पहले लिवर पर उसके प्रभाव के बारे में जरूर पूछें।

लिवरः शरीर की 'अद्भुत रासायनिक प्रयोगशाला'

लिवर केवल एक अंग नहीं, बल्कि शरीर का 'पावरहाउस' है। **पुनर्जीवन क्षमताः** लिवर मानव शरीर का एकमात्र ऐसा अंग है जो खुद को पुनर्जीवित कर सकता है। यदि इसका 75% हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो जाए, तो उचित उपचार और देखभाल से यह वापस अपने मूल आकार में आ सकता है। **मूक रक्षकः** लिवर को साइलेंट ऑर्गन कहा जाता है। इसका कारण यह है कि जब तक लिवर 70-80% तक डैमेज नहीं हो जाता, तब तक यह दर्द के कोई स्पष्ट लक्षण नहीं दिखाता। इसीलिए लिवर की बीमारियों को 'साइलेंट किलर' भी कहते हैं।

स्वच्छता रैली के साथ चंडीगढ़ नगर निगम का सख्त एक्शन, कई सेक्टरों में सुधार के निर्देश

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

शहर को स्वच्छ और हरित बनाने के उद्देश्य से नगर निगम चंडीगढ़ की ओर से शनिवार सुबह स्वच्छ साइकिल रैली का आयोजन किया गया। सेक्टर-17 प्लाजा से सुबह 8 बजे शुरू हुई इस रैली में निगम अधिकारियों, कर्मचारियों और शहरवासियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। रैली का नेतृत्व नगर निगम के चीफ इंजीनियर संजय अरोड़ा ने किया। रैली सेक्टर-17, 18, 19, 27, 7 और 9 से होकर गुजरी, जहां लोगों को स्वच्छता, हाइजीन और सामुदायिक सहभागिता के प्रति जागरूक किया गया। रैली के साथ ही चीफ इंजीनियर ने विभिन्न सेक्टरों में जमीनी स्तर पर नागरिक सुविधाओं और रखरखाव कार्यों का निरीक्षण भी किया। सेक्टर-17 में सार्वजनिक शौचालयों की सफाई व्यवस्था पर विशेष जोर देते हुए नियमित मेंटेनेंस और सफाई चेकलिस्ट को अपडेट रखने के निर्देश दिए गए। सेक्टर-18 और 18/19 में स्ट्रीट लाइट प्वाइंट्स को दुरुस्त करने तथा रोड गली चैंबर को दोबारा ठीक करने के निर्देश जारी किए गए। इसके अलावा सभी संबंधित अधिकारियों को बैक सर्विस लेन की दैनिक सफाई सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए गए। चीफ इंजीनियर संजय अरोड़ा ने विभिन्न सेक्टरों का औचक निरीक्षण कर नागरिक सुविधाओं और रखरखाव कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान कई स्थानों पर खामियां सामने आने पर संबंधित अधिकारियों को तुरंत सुधार के सख्त निर्देश दिए गए। सेक्टर-19सी में ग्रीन बेल्ट, ट्यूबवेल और पार्किंग एरिया का विस्तृत निरीक्षण किया गया। यहां पार्कों में झूलों की मरम्मत, बिजली के खंभों के रखरखाव, अनुपयोगी विद्युत बॉक्स हटाने और कचरे के उचित निस्तारण के निर्देश दिए गए। साथ ही पार्किंग बोर्डों की दोबारा पेंटिंग और मॉडल पार्किंग विकसित करने के लिए सर्वे कराने को कहा गया। संस्थागत क्षेत्रों में ब्रांडेड गमले लगाने और इसकी अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी जारी किए गए। सेक्टर-27 स्थित कम्युनिटी सेंटर में क्षतिग्रस्त साइन बोर्ड की मरम्मत और म्यूरल्स को दोबारा रंगने के निर्देश दिए गए। वहीं, सेक्टर-7 में एससीओ के पीछे जमा मलबा हटाने और क्षेत्र के समग्र सौंदर्यीकरण को प्राथमिकता देने को कहा गया। इसके अलावा सेक्टर-7 में मकान नंबर 1511 के सामने स्थित पार्क में व्यापक सुधार कार्यों के निर्देश जारी किए गए। इनमें वॉकिंग पाथ की मरम्मत, पेड़ों की छंटाई, कांटेदार तार की फेंसिंग, नए सार्वजनिक शौचालय का निर्माण और लंबे समय से बंद पड़े फाउंटेन को चालू करना शामिल है। इन सभी कार्यों की प्रगति रिपोर्ट (एटीआर) दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। सेक्टर-9 में मकान नंबर 206 के सामने जलभराव की समस्या को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही पेड़ों की छंटाई और ड्रेनेज चैनलों की मरम्मत कर जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने को कहा गया। निरीक्षण के दौरान चीफ इंजीनियर ने सभी अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने, साफ-सफाई के उच्च मानकों को बनाए रखने और मॉनिटरिंग सिस्टम को और मजबूत करने के निर्देश दिए।

यह साइकिल रैली स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत चल रही पहलों का हिस्सा थी, जिसका उद्देश्य चंडीगढ़ की रैंकिंग में सुधार लाने के साथ-साथ नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है। नगर निगम ने शहरवासियों से अपील की है कि वे स्वच्छता अभियानों में बढ़-चढ़कर भाग लें और शहर को साफ, स्वस्थ और सतत बनाने में अपना योगदान दें।

चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में रचा गया इतिहास

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

एपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के Centre of Excellence Digital Marketing & AI ने Influencia ने Influencia2.0 के दौरान एक ही दिन में 25+ एमओयू साइन कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की।

यह महत्वपूर्ण पहल नवाचार, सहयोग और राष्ट्र-निर्माण के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता को दशार्ती है, जो विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है।

इस उपलब्धि को खास बनाने वाले प्रमुख पहलू:

विभिन्न क्षेत्रों के शीर्ष इन्फ्लुएंसर्स के साथ पहला Influencer Award Show आयोजित किया गया, जहां देश-विदेश से आए शीर्ष इन्फ्लुएंसर्स को उनके क्षेत्र में बेहतर योगदान के लिए सम्मानित किया गया

मुख्य अतिथि Mr. Anurag Dixit, Senior Editor, News Nation TV को विश्वविद्यालय के शीर्ष अधिकारियों द्वारा सम्मानित किया गया

एक ही मंच पर 25+ रणनीतिक एमओयू साइन किए गए

"A Life of Influencers" थीम के साथ एक इमर्सिव एआई एरीना स्थापित किया गया

शीर्ष इन्फ्लुएंसर्स द्वारा विशेष मास्टरक्लास आयोजित किए गए

यह पहल केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है – यह अकादमिक, इंडस्ट्री और क्रिएटर्स के एक मजबूत इकोसिस्टम के निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम है। नए ज्ञान सृजन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इंटर्नशिप, लाइव प्रोजेक्ट्स और centre of excellence Digital Marketing & AI के अंतर्गत डिजिटल मार्केटिंग, अक व Data Analytics में मास्टरक्लास के माध्यम से हम अपने विद्यार्थियों के लिए वास्तविक दुनिया के अवसर सृजित कर रहे हैं।

हमें शीर्ष इन्फ्लुएंसर्स और अग्रणी इंडस्ट्री पार्टनर्स, जैसे Omjee's Group के साथ सहयोग करने पर गर्व है, जहां क्रिएटर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, सिंगर्स और इनोवेटर्स एक मंच पर एकत्रित हुए।

चंडीगढ़ विश्वविद्यालय भविष्य की दिशा में अग्रणी बना हुआ है – हर मजबूत साझेदारी के साथ एक नई मिसाल कायम करते हुए।

आर बी आई कॉलोनी में 50 सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए फायर सेफ्टी वर्कशॉप आयोजित

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

चंडीगढ़ के सेक्टर 44 स्थित आर बी आई कॉलोनी में 50 सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए एक फायर सेफ्टी ट्रेनिंग वर्कशॉप का आयोजन किया गया।

इस वर्कशॉप का आयोजन फायर स्टेशन सेक्टर 32 चंडीगढ़ और फायर अवेयरनेस एंड सेफ्टी एसोसिएशन (एफएएसए) द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।

इस सेशन का मुख्य उद्देश्य सिक्योरिटी कर्मियों में सबसे पहले मदद पहुंचाने वाले के तौर पर काम करने के कौशल को विकसित करना था। इसमें फायर एक्सटिंग्विशर को चलाने, फायर हाइड्रेंट का उपयोग करने और आपातकालीन स्थिति में लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के प्रोटोकॉल पर लाइव डेमो दिए गए।

एफएएसए के संस्थापक अध्यक्ष जसज्योत सिंह अलमस्त ने कहा, किसी भी रिहायशी कॉम्प्लेक्स में कोई घटना होने पर अक्सर सिक्योरिटी गार्ड्स ही सबसे पहले मदद के लिए आगे आते हैं। उन्हें फायर सेफ्टी के कौशल से लैस करने से न केवल प्रतिक्रिया की गति तेज होती है, बल्कि जान-माल के नुकसान का खतरा भी कम हो जाता है। सेक्टर 32 फायर स्टेशन के वरिष्ठ फायरमैन मांगे राम और जोगिंदर सिंह ने सभी प्रतिभागियों से आग्रह किया कि वे अपने परिसर में लगे फायर सेफ्टी उपकरणों की नियमित रूप से जांच करते रहें; साथ ही, उन्होंने विभिन्न प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर को चलाने का तरीका भी डेमो के माध्यम से समझाया।

एपिक 2026 में देशभर से 600 डॉक्टर हुए शामिल

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

एपिक 2026, एक प्रतिष्ठित नेशनल मेडिकल कॉन्फ्रेंस, का आयोजन यहां हयात रीजेंसी, चंडीगढ़ में आरंभ हुआ, जिसमें देशभर से 600 से अधिक डॉक्टरों और स्वास्थ्य पेशेवरों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी और पुडुचेरी की पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी रहीं।

अपने मुख्य संबोधन में उन्होंने नेतृत्व, धैर्य और ईमानदारी पर दृढ़ता से विचार रखते हुए साहस और दृढ़ता को सार्वजनिक सेवा तथा चिकित्सा पेशे दोनों में अत्यंत आवश्यक मूल्यों के रूप में रेखांकित किया, जिससे श्रोताओं पर गहरा प्रभाव पड़ा।

महिला सशक्तिकरण की वकालत करते हुए उन्होंने नेतृत्व पदों में महिलाओं की अधिक भागीदारी का आान किया और राष्ट्र निर्माण में उनके महत्वपूर्ण योगदान को सराहा। उन्होंने चंडीगढ़ की शहरी योजना, स्वच्छता और पर्यटन आकर्षण की प्रशंसा की, साथ ही प्रभावी ट्रैफिक प्रबंधन और जिम्मेदार नागरिक भागीदारी के महत्व पर भी विचार साझा किए। कॉन्फ्रेंस ने एक जीवंत और सहभागितापूर्ण वातावरण प्रदान किया, जो अकादमिक आदान-प्रदान, क्लिनिकल उन्नति और बहु-विषयक सहयोग के लिए एक सार्थक मंच साबित हुआ। सम्मेलन की प्रमुख विशेषताओं में ओबेसिटी मैनेजमेंट, डायबिटिक फुट केयर और स्त्री रोग-एंडोक्रिनोलॉजी इंटीग्रेशन पर केंद्रित व्यावहारिक कार्यशालाएं शामिल रहीं। ये सत्र अत्यंत इंटरएक्टिव और प्रायोगिक थे, जिनमें केस-आधारित जानकारियां दी गईं, जिन्हें उनकी तत्काल क्लिनिकल उपयोगिता के लिए व्यापक सराहना मिली। एपिक 2026 के दूसरे दिन ने प्रतिभागियों को प्रेरित किया और स्वास्थ्य समुदाय में चिकित्सा उत्कृष्टता के साथ-साथ नेतृत्व, नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।

संक्षिप्त-समाचार

अक्षय तृतीया: लैब-ग्रोन डायमंड्स निवेश का एक नया और शुभ विकल्प

चंडीगढ़।: जैसे-जैसे 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया नजदीक आ रही है – एक ऐसा दिन जिसे निवेश करने के लिए बेहद शुभ माना जाता है, और जिसके बारे में माना जाता है कि ऐसा निवेश बढ़ता है और लंबे समय तक बना रहता है। इस शुभ मौके पर कल्टीवेटेड कैरेट्स, सोने की पारंपरिक खरीदारी का एक आधुनिक विकल्प पेश कर रहा है: लैब-ग्रोन डायमंड्स, जो एनएसी, मनीमाजरा स्थित उनके स्टोर पर उपलब्ध हैं। इस बदलाव पर रोशनी डालते हुए, कल्टीवेटेड कैरेट्स के संस्थापक और लैब-ग्रोन डायमंड्स के विशेषज्ञ, दीपक गुप्ता कहते हैं कि अक्षय तृतीया हमेशा से ही किसी ऐसी चीज की शुरुआत करने का अवसर रही है जो लंबे समय तक बनी रहे – और लैब-ग्रोन हीरा, ठीक इसी बात का प्रतीक है। लैब-ग्रोन डायमंड्स फाइन ज्वैलरी का भविष्य हैं। वे खदानों से निकले हीरों जैसी ही सटीर्फाइड चमक प्रदान करते हैं, और साथ ही आज के जागरूक व जानकार खरीदारों के मूल्यों के अनुरूप भी होते हैं। आज की महिला सिर्फ.ज्वैलरी नहीं खरीद रही है; वह इसके जरिए यह भी बता रही है कि वह कौन है – और लैब-ग्रोन डायमंड्स उसे गुणवत्ता, सुंदरता या नैतिकता से कोई समझौता किए बिना वो ताकत देते हैं। इस अवसर का जश्न मनाने के लिए, कल्टीवेटेड कैरेट्स ने अक्षय तृतीया पर एक विशेष ऑफर की घोषणा की है: प्रमाणित लैब-ग्रोन डायमंड्स पर प्रति कैरेट 11,000 रुपए तक की छूट, जो सीमित समय के लिए उपलब्ध है। हर पीस विशेष रूप से तैयार किया गया है और ऑर्डर पर बनाया जाता है; इसमें पर्सनलाइज्ड डिजाइन के साथ आईजीआई/जीआईए-सटीर्फाइड हीरों का मेल होता है – जो फाइन ज्वैलरी में निवेश करने का एक दुर्लभ अवसर प्रदान करता है, और वह भी असाधारण मूल्य पर।

चंडीगढ़ में सीबीएसई 10वीं में शानदार प्रदर्शन करने वाले छात्रों का सेक्टर-34 में सम्मान

चंडीगढ़। सीबीएसई कक्षा 10वीं के परिणामों में एक बार फिर लड़कियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बाजी मारी। ट्राइसिटी का नाम रोशन करते हुए बड़ी संख्या में छात्राओं ने 90 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल किए। इस उपलब्धि का जश्न मनाते हुए सेक्टर-34 स्थित फिजिक्स विद्यापीठ संस्थान में 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के सम्मान में एक विशेष समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में प्रिशा, धवल तिवारी, हर्षिता, रोहित, विष्णु सहित कई मेधावी छात्रों को उनके परिवारों सहित आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम के दौरान संस्थान के सेंटर हेड ने सभी टॉपर्स का फूल-मालाओं से स्वागत कर उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर सेंटर हेड ने कहा कि यदि विद्यार्थियों को सही मार्गदर्शन, अनुशासन और सकारात्मक माहौल मिले, तो वे बड़ी आसानी से ऊंचाइयों को छू सकते हैं। उन्होंने छात्रों की मेहनत और अभिभावकों के सहयोग की सराहना करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। समारोह के दौरान अभिभावकों और विद्यार्थियों में उत्साह देखने को मिला, वहीं सभी ने इस उपलब्धि को आगे और बेहतर करने का संकल्प भी लिया।

नारी शक्ति वंदन एक्ट का विरोध शर्मनाक और दुखद: अजय मित्तल

पंचकूला। भाजपा जिला अध्यक्ष अजय मित्तल ने लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध करने पर कांग्रेस सहित समूचे विपक्ष पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे शर्मनाक और दुखद बताया है। उन्होंने कहा, इससे कांग्रेस व अन्य विपक्षी पार्टियों का महिला विरोधी रवैया उजागर हुआ है। अजय मित्तल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अधिनियम का विरोध कर देश की करोडो माँ, बहन, बेटियों को उनका हक दिलवाने में बाधा डालने का दुःसाहस किया है, जिसका परिणाम आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। अजय मित्तल ने कहा, भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी के विरोध के चक्कर में कांग्रेस पार्टी स्वयं अपने पाव पर कुल्हाड़ी मार ली है। उन्होंने कहा, महिलाओं को मिलने वाले 33% आरक्षण को रोकना और फिर उसका जश्न मनाकर देश की आधी आबादी का अपमान करना कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों के मानसिक दिवालियापन को दशार्ता है। गौरतलब है, केंद्र सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से 33% आरक्षण को 2029 के चुनावों से पहले लागू करने के लिए संशोधन ला रही थी, लेकिन दो-तिहाई बहुमत न मिलने के कारण यह संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में गिर गया।

सीबीएसई परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बापूधाम के छात्र को सम्मानित किया

चंडीगढ़। सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करने वाले बापूधाम कॉलोनी, सेक्टर 26 के निवासी छात्र तन्मय को आज कॉलोनीवासियों ने सम्मानित किया। तनमय ने कक्षा 10वीं की परीक्षा में 94% अंक प्राप्त कर अपने माता-पिता, स्कूल तथा बापूधाम क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इस उपलब्धि पर गोपाल अग्री, सुशील कुमार, कृष्ण कुमार, सुमित पुरी, कमल नायक सहित समाजसेवकों ने छात्र को सम्मानित करते हुए उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। वक्ताओं ने कहा कि यह सफलता कड़ी मेहनत, अनुशासन और दृढ़ संकल्प का परिणाम है, जो अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। कार्यक्रम के दौरान तन्मय ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता और शिक्षकों के मार्गदर्शन को दिया। अंत में सभी उपस्थित लोगों ने छात्र के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उसे आगे भी इसी तरह उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया।

गुरु नानक ग्लोबल फाउंडेशन ने युवाओं और किसानों के लिए बड़ी पहल शुरू की

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

गुरु नानक ग्लोबल फाउंडेशन ने आधुनिक शिक्षा, नवीन सोच और वैश्विक अवसरों के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण पहल शुरू करने की घोषणा की है। यह फाउंडेशन गुरु नानक देव ग्लोबल यूनिवर्सिटी, टेक्सास (यूएसए) के सहायक निकाय के रूप में कार्य करता है।

प्रमुख पहलों में एक विशेष उच्च शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी में एक पाठ्यक्रम, किसानों के लिए एक फसल सुरक्षा योजना और एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन शामिल है।

उच्च शिक्षा पहल के तहत, स्नातकोत्तर छात्रों को एक संरचित तीन-चरणीय कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा। इसका उद्देश्य नवाचार, सतत विकास और उद्यमिता में क्षमताओं को विकसित करना है, जिससे छात्र जिम्मेदार और प्रभावशाली नेता के रूप में उभर सकें।

सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम युवाओं को चिप डिजाइन, निर्माण और उन्नत विनिर्माण तकनीकों में कौशल से लैस करेगा। इस पहल से युवा पेशेवरों के लिए बेहतर रोजगार के अवसर पैदा करते हुए देश की बढ़ती तकनीकी मांगों को पूरा करने की उम्मीद है।

किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए एक समर्पित फसल सुरक्षा योजना भी शुरू की गई है। हाल ही में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से कई राज्यों में फसलों को काफी नुकसान हुआ है। इस योजना के तहत फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए किफायती और पर्यावरण-अनुकूल सुरक्षात्मक समाधान विकसित किए जाएंगे।

इसके अलावा, फाउंडेशन 2026 में भारत में एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा, जिसमें दुनिया भर के विशेषज्ञों, उद्योग जगत के नेताओं, नीति निमार्ताओं और पर्यावरण विशेषज्ञों को एक साथ लाया जाएगा। सम्मेलन ज्ञान के आदान-प्रदान और सहयोगात्मक अवसरों के लिए एक मजबूत मंच प्रदान करेगा।

इस अवसर पर अध्यक्ष बलजीत सिंह ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य युवाओं को दिशा प्रदान करना और उन्हें समाज और राष्ट्र के लिए सार्थक योगदान देने के लिए तैयार करना है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, नवाचार और सामाजिक सेवा को मजबूत करने के लिए ऐसे प्रयास भविष्य में भी जारी रहेंगे।

गुरु नानक ग्लोबल फाउंडेशन ने मूल्य-आधारित शिक्षा और मानवता की सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की

पंचकूला की मंडियों में सुचारू रूप से चल रहा है गेंहू की खरीद और उठान का कार्य

सिटी दर्पण संवाददाता
पंचकूला

अब तक 25832 मीट्रिक टन गेंहू की खरीद तथा 9237 मीट्रिक टन गेंहू का हुआ उठान

जिला में रबी सीजन 2026-27 के दौरान गेंहू की खरीद और उठान का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। सरकारी खरीद एजेंसियों द्वारा जिला की मंडियों में से अब तक 25832 मीट्रिक टन गेंहू की खरीद की गई और 9237 मीट्रिक टन गेंहू का उठान किया गया है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि सरकारी खरीद एजेंसियों हैफेड और हरियाणा वेयर हाउसिंग कारपोरेशन द्वारा रायपुररानी, बरवाला और पंचकूला स्थित अनाज मंडियों में गेहूं की खरीद की जा रही है।

उन्होंने बताया कि रायपुररानी अनाज मंडी से हैफेड द्वारा 3047 मीट्रिक टन गेंहू और हरियाणा वेयर हाउसिंग कोरपोरेशन द्वारा 7945 मीट्रिक टन गेंहू की खरीद की गई। इसी प्रकार बरवाला अनाज मंडी से हैफेड द्वारा 6545 मीट्रिक टन गेंहू और हरियाणा वेयर हाउसिंग कारपोशन द्वारा 7475 मीट्रिक टन गेंहू की खरीद की गई। इसके अलावा पंचकूला अनाज मंडी से हैफेड द्वारा 820 मीट्रिक टन गेंहू की खरीद की गई।

उन्होने बताया कि मंडियों में खरीद के साथ साथ उठान का कार्य भी सुचारू रूप से चल रहा है। रायपुररानी अनाज मंडी से हैफेड द्वारा 628 मीट्रिक टन गेंहू और हरियाणा वेयर हाउसिंग कोरपोरेशन द्वारा 2719 मीट्रिक टन गेंहू का उठान किया गया। इसी प्रकार बरवाला अनाज मंडी से हैफेड द्वारा 2297 मीट्रिक टन गेंहू और हरियाणा वेयर हाउसिंग कारपोशन द्वारा 3443 मीट्रिक टन गेंहू का उठान किया गया। पंचकूला अनाज मंडी से हैफेड द्वारा 150 मीट्रिक टन गेंहू का उठान किया गया।

आयुक्त की पहल पर नगर निगम और मंडियों के प्रतिनिधियों की बीच संयुक्त बैठक आयोजित

पंचकूला जिले की सभी किसान मंडियां होंगी सुव्यवस्थित: विनय कुमार

सिटी दर्पण संवाददाता
पंचकूला

शहर भर में किसान मंडियों के कामकाज को बेहतर बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए, नगर निगम पंचकूला के आयुक्त श्री विनय कुमार और किसान मंडियों के प्रतिनिधियों के बीच एक संयुक्त बैठक आयोजित की गई। किसान मंडियों के प्रतिनिधियों का नेतृत्व श्री अजय कुमार ने किया। इस बैठक में जनता की चिंताओं के समाधान और मंडियों को अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी तथा नागरिक-अनुकूल बनाने की साझा प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया।

यह पहल सहयोगात्मक शासन का एक मजबूत उदाहरण है, जिसमें दोनों हितधारकों ने एक साथ आकर किसान मंडियों के वर्तमान संचालन से निवासियों को हो रही समस्याओं के व्यावहारिक और टिकाऊ समाधान विकसित करने का प्रयास किया।

बैठक में आपसी सहमति से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनमें सुव्यवस्थित योजना और जनता की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर विशेष जोर दिया गया।

नगर निगम पंचकूला के इंजीनियरिंग विंग ने मंडियों के लिए सेक्टर-वार लेआउट प्लान तैयार किए हैं। इन योजनाओं का मुख्य फोकस स्पष्टरूप से निर्धारित वेंडिंग जोन, पैदल यात्रियों और वाहनों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त चौड़ी लेन, तथा उचित रूप से चिन्हित पार्किंग स्थलों पर है। भविष्य में व्यवस्था, सुरक्षा और सभी के लिए आसान पहुंच बनाए रखने के लिए इन लेआउट का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

सभी वाहनों को केवल निर्धारित पार्किंग क्षेत्रों में ही खड़ा करना अनिवार्य होगा। यातायात के सुचारू प्रवाह और भीड़भाड़ को रोकने के लिए किसी भी उल्लंघन पर चालान किया जाएगा।

सड़क के किनारों (बर्म्स) पर किसी भी प्रकार की दुकान लगाने की अनुमति नहीं होगी। विक्रेताओं को अनुमोदित लेआउट के अनुसार केवल निर्धारित स्थानों के भीतर ही अपना व्यवसाय संचालित करना होगा।

प्रत्येक विक्रेता के लिए कचरे के पृथक्करण हेतु दो अलग-अलग कूड़ेदान रखना अनिवार्य होगा। नगर निगम पंचकूला प्रत्येक मंडी में दो निर्धारित स्थानों पर कम से कम चार बड़े सामुदायिक कूड़ेदान स्थापित करेगा, ताकि कचरे का कुशल संग्रह सुनिश्चित किया जा सके।

विक्रेता गैर-बायोडिग्रेडेबल (नष्ट न होने वाली) प्लास्टिक पॉलीथीन थैलियाँ उपलब्ध नहीं कराएंगे। पर्यावरण-अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए ग्राहकों को पुनः उपयोग योग्य थैलियाँ साथ लाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

मंडी प्रतिनिधियों ने निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं का कड़ाई से पालन करने पर सहमति व्यक्त की है। दोषपूर्ण बाटों और मापों के उपयोग से कम तौलने जैसी अनुचित व्यापारिक प्रथाओं को पूरी तरह समाप्त किया जाएगा।

दुकानदारों द्वारा रंगीन रोशनी (कलर लाइट्स) का उपयोग एक सप्ताह के भीतर पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। केवल सफेद रोशनी की अनुमति होगी, ताकि फलों और सब्जियों का प्राकृतिक रंग एवं गुणवत्ता उपभोक्ताओं को स्पष्ट रूप से स्पष्ट दिखाई दे सके।

आयुक्त श्री विनय कुमार ने शहरी सेवाओं को बेहतर बनाने और यह सुनिश्चित करने के प्रति पंचकूला नगर निगम की प्रतिबद्धता को दोहराया कि किसान मंडियों जैसे सार्वजनिक स्थान अनुशासित और स्वच्छ तरीके से संचालित हों। उन्होंने नागरिकों से भी एक स्वच्छ, सुरक्षित और अधिक व्यवस्थित शहर के निर्माण में इस पहल का सहयोग और समर्थन करने का आान किया।